



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3343]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2017/अग्राहायण 14, 1939

No. 3343]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2017/AGRAHAYANA 14, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017

सं. 41/2015-2020

का.आ. 3813(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 को अधिसूचित करती है। यह विदेश व्यापार नीति 5-12-2017 से प्रभावी होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: संशोधित और अद्यतित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

[फा.सं. 01/94/180/332/एम15/पीसी-4/खण्ड-II]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अध्याय - 1

विधिक ढांचा और व्यापार सरलीकरण

क. विधिक ढांचा

1.00 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का विधिक आधार

दिनांक 05.12.2017 से यथा अद्यतित विदेश व्यापार नीति 2015-20 को, संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं० 22) [एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम] की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

1.01 विदेश व्यापार नीति की अवधि

दिनांक 05.12.2017 से यथा अद्यतित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020, जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, अधिसूचना की तारीख से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। अधिसूचना की तारीख तक किए गए सभी निर्यात तथा आयात प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति द्वारा तदनुसार शासित होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

1.02 विदेश व्यापार नीति में संशोधन

केन्द्र सरकार समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार रखती है।

1.03 प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (एएनएफ):

महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों में दिए गए प्रयोजनों के लिए, निर्यातक या आयातक या किसी लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र सहित प्रक्रिया पुस्तक अथवा उससे संबंधित संशोधन को सार्वजनिक सूचना के द्वारा अधिसूचित कर सकते हैं।

1.04 सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रावधान

जहाँ विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में होगा, वहाँ यह सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण होगा।

1.05 परिवर्ती व्यवस्था

(क) दिनांक 05.12.2017 से यथा अद्यतित विदेश व्यापार नीति 2015-20 लागू होने से पहले कोई भी लाइसेंस/प्राधिकारपत्र/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय सहायता या वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ के साधन ऐसे लाइसेंस/प्राधिकारपत्र/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय या राजकोषीय लाभ निर्गमित प्राधिकार पत्र के प्रयोजन और अवधि के लिए वैध रहेंगे जब तक अन्यथा नियत न किया गया हो।

(ख) यदि इस विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो। यह इस शर्त के अधीन है कि निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध लगाने की तारीख से पूर्व लागू अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के मूल वैधता अवधि के भीतर किया गया हो और यह अपरिवर्तनीय साख-पत्र की उपलब्ध शेष मूल्य और मात्रा तथा समयावधि तक सीमित हो। ऐसे अपरिवर्तनीय साख-पत्र के परिचालन के लिए आवेदक को किसी ऐसे प्रतिबन्ध या विनियम के लागू होने के 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आर.ए.) के पास साख पत्र का पंजीकरण कराना होगा जिसकी कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाएगी।

ख. व्यापार सरलीकरण एवं व्यापार करने की सुगमता

1.06 उद्देश्य

सौदा लागत को कम करने और समय में कटौती करने हेतु व्यापार सरलीकरण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जिसके द्वारा भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहा है। व्यापार सरलीकरण की दिशा में विदेश व्यापार नीति के विभिन्न उपबंधों और सरकार द्वारा किए गए उपायों को इस अध्याय में आयात और निर्यात व्यापार के हितधारियों के लाभ हेतु समेकित किया गया है।

1.07 डीजीएफटी निर्यात/आयात हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में

डीजीएफटी निर्यात और आयात के सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। अच्छे अभिशासन पर फोकस है जो दक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार सुपुर्दगी प्रणाली पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आसान बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा व्यापार तथा उद्योग निकायों के साथ समय-समय पर परामर्श करता है।

1.08 निर्यात बंधु-नए निर्यात/आयात उद्यमियों के लिए समर्थन (हैन्ड होल्डिंग)स्कीम

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय परामर्श, प्रशिक्षण और आउट-रीच कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश व्यापार की जटिलताओं के बारे में नए और संभावित निर्यातक को परामर्श देने के लिए निर्यात बंधु स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) विनिर्माण क्षेत्र में और रोजगार सृजन में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के कार्यनीतिक महत्व पर विचार करते हुए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संकेन्द्रित हस्तक्षेप के लिए क्लस्टर में उत्पाद की निर्यात संभावना तथा उद्योगों की सघनता के आधार पर 'एमएसएमई क्लस्टरों' को चिन्हित किया गया है।

(ग) निर्यात बंधु स्कीम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु 'उद्योग साझेदारों' के रूप में निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय के अन्य इच्छुक 'ज्ञान साझेदारों' की सहायता से आउटरीच कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सीमाशुल्क, ईसीजीसी, बैंक तथा संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हित धारकों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएंगे।

1.09 नागरिक चार्टर

डीजीएफटी में समुचित नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सारणी दी गई है। किसी आवेदन को निपटाने की समय-सीमा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.10 में दी गई है।

1.10 आनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली

डीजीएफटी के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने तथा अन्य ईडीआई से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक ईडीआई सहायता डेस्क उपलब्ध है। सहायता प्राप्त करने के लिए dgftedi@nic.in पर ई मेल भेजा जा सकता है अथवा टाल फ्री नम्बर 1800111550 का उपयोग किया जा सकता है। डीजीएफटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों (विवरण <http://dgft.gov.in> पर उपलब्ध है) में भी सहायता डेस्क की सुविधा प्रदान की जाती है। आनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा निगरानी प्रणाली से प्रयोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने तथा आनलाइन स्थिति का पता लगाने/उत्तर प्राप्त करने (विवरण <http://dgft.gov.in> पर उपलब्ध है) की अनुमति है।

1.11 ई-आईसीसी (इलेक्ट्रॉनिक-आयातक निर्यातक कोड) जारी करना

(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईसीसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रॉनिक फार्म (ई-आईसीसी) में आयातक निर्यातक कोड जारी करता है। ई-आईसीसी जारी करने के लिए डीजीएफटी की वेबसाइट (<http://www.dgft.gov.in>) पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तथापि, आवेदक डिजिटल रूप में विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) द्वारा ऐसे आवेदनों की प्रोसेसिंग की जाएगी तथा सामान्यतः दो कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-आईसीसी जारी/ईमेल किया जाएगा।

(ग) यदि आवेदन अपूर्ण है या अन्यथा अपात्र है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा आवेदक को अस्वीकृति पत्र/ईमेल (अस्वीकृत के कारणों के साथ) भेजा जाएगा।

(घ) ई-आईसीसी जारी करने हेतु आवेदन ईबिज प्लैटफॉर्म (<https://www.ebiz.gov.in>) पर भी किया जा सकता है।

1.12 ई-बीआरसी

(क) डीजीएफटी द्वारा ई-बीआरसी (इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र) परियोजना प्रारंभ करना तथा इसका सफलता से कार्यान्वयन करना हाल ही में की गई प्रमुख पहल है। इसने डीजीएफटी को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधा बैंकों से निर्यात आय की प्राप्ति का विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इससे हितधारियों के साथ बिना किसी वास्तविक विचार विमर्श के विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने भी माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात को मानीटर करने तथा एक ही प्लैटफॉर्म से विभिन्न लाभ की रिपोर्ट भेजने के लिए एडी बैंकों को सुविधा प्रदान करने हेतु निर्यात आंकड़ा प्रॉसेसिंग एवं मानीटरिंग प्रणाली (ईडीपीएमएस) नामक एक व्यापक आईटी आधारित प्रणाली विकसित की है।

1.13 ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

14 राज्य सरकारों के साथ ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे राज्य सरकारों द्वारा निर्यातकों को वैट/जीएसटी की वापसी को सुविधाजनक किया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय, कृषि निदेशालय, कृषि संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.14 निर्यातक आयातक प्रोफाइल

निर्यातक आयातक प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तैयार की गई है। अपलोड कर दिए जाने के बाद इन दस्तावेजों/दस्तावेजों की प्रतियों को प्रत्येक आवेदन के साथ बार-बार क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उद्देश्य सौदा लागत और समय में कमी लाना तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय में विभिन्न आवेदनों की कागज रहित प्रॉसेसिंग की ओर कदम बढ़ाना है।

1.15 निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में कमी

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.06 के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार भारत से/में माल के निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या घटाकर प्रत्येक के लिए तीन कर दी गई है।

1.16 आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा

डीजीएफटी के सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों आरए और विस्तार केन्द्रों को उच्च स्पीड इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त और प्रक्रियाबद्ध किया जाता है। डीजीएफटी ने ईडीआई पहल के तहत आयातक निर्यातक कोड और विभिन्न प्राधिकार पत्र/स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा प्रदान की है। डीजीएफटी डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित भारत सरकार (जीओआई) के विभागों में से है जिसने एन्क्रिप्टेड 2048 बिट के उच्च स्तर का डिजिटल हस्ताक्षर शुरू किया है। डीजीएफटी वेबसाइट (<http://dgft.gov.in>) पर जाने के पश्चात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु वेब इंटरफेस है। निर्यातक/सीएचए द्वारा घर अथवा कार्यालय में बैठे-बैठे 24 x 7 वातावरण में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी संबद्ध बैंकों से डेबिट/क्रेडिट कार्डों के द्वारा किया जा सकता है। आवेदनों पर डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षर किए जाते हैं और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कम्प्यूटर पर इसे प्रोसेस किया जाता है और प्राधिकार पत्र/स्क्रिप जारी किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन फाइलिंग ने क्षेत्रीय प्राधिकारी के साथ वास्तविक अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) को न्यूनतम कर दिया है।

1.17 ऑनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

इस समय निर्यातकों को आईकान ई-काम के तहत डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होता है और सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे तकनीकी विनिर्देशन, साहित्यिक सामग्री आदि के साथ ऑनलाइन आवेदन का विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहरयुक्त प्रिन्ट-आउट प्रस्तुत करना होता है। अब (क) मानदंड समितियों द्वारा अग्रिम प्राधिकार के तहत मानदण्डों के निर्धारण (ख) प्रतिबंधित मदों के निर्यात (ग) प्रतिबंधित मदों के आयात (घ) स्कोमेट मदों के संबंध में ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली में पीडीएफ/जेपीजी/जेपीईजी/जीआईएफ फॉर्मेट में तकनीकी विनिर्देशनों, साहित्यिक सामग्री आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। निर्यातकों को वास्तुकला रेखाचित्र, मशीन रेखाचित्र जिसे स्कैन और अपलोड करना कठिन हो सकता है, को छोड़कर आवेदन की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। आवेदनों को ऑनलाइन भी प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

1.18 सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा

कागज रहित प्रक्रिया की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। आरंभ में यह सुविधा अध्याय-3 के तहत भारत से निर्यात स्कीम के लिए तैयार की जाएगी। ऐसे दस्तावेजों जैसे एएनएफ 3ख, एएनएफ 3ग और एएनएफ 3घ में संलग्न अनुलग्नक जिन्हें वर्तमान में इन हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, को इस प्रक्रिया से सरल बनाया जा सकता है। ऐसी सुविधा के तैयार होने के बाद निर्यातक डिजिटल रूप से अपलोड किए गए अनुलग्नक को अपने ऑनलाइन आवेदन से सम्बद्ध कर सकता है। अग्रिम प्राधिकार, डीएफआईए और ईपीसीजी जैसी अन्य स्कीमों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इन सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा सकता है।

1.19 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई)

डीजीएफटी ने निर्यात सुविधा प्रदान करने और अच्छे अभिशासन के प्रयोजन हेतु सुदृढ़ ईडीआई प्रणाली लागू की है। डीजीएफटी के पास अन्य प्रशासनिक विभागों नामतः सीमाशुल्क, बैंक और ईपीसी के साथ स्थापित आयात और निर्यात प्राधिकारपत्रों सहित विभिन्न दस्तावेजीकरण संबंधी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित ईडीआई संदेश आदान-प्रदान प्रणाली पहले से ही है। इससे सरकारी विभागों के साथ निर्यातकों और आयातकों के वास्तविक अंतरापृष्ठ में कमी आई है और सौदा लागत में कमी की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपाय है। डीजीएफटी का प्रयास ईडीआई के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे कि भागीदार विभागों के साथ एकीकरण का उच्च स्तर हासिल किया जा सके।

1.20 सामुदायिक सहभागियों के साथ संदेश विनिमयता

संदेश विनिमयता हेतु सीमाशुल्क विभाग, बैंक, निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) डीजीएफटी के प्रमुख सामुदायिक सहभागी हैं। एक कुशल संदेश विनिमय प्रणाली विभिन्न सामुदायिक सहभागियों के साथ सुचारु रूप से कार्य करती है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) सीमाशुल्क विभाग के साथ संदेश विनिमयता

- (i) आयातक निर्यातक कोड सं.।
- (ii) डीएफआईए, एए, ईपीसीजी हेतु प्राधिकार पत्र/स्क्रिप।
- (iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए), निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) प्रोत्साहन स्क्रिपों हेतु पोतलदान बिल।

(ख) ईबिज (<https://www.ebiz.gov.in>) के साथ संदेश आदान-प्रदान

ई-आईसी के लिए आवेदन

(ग) बैंकों के साथ संदेश आदान प्रदान

- (i) आवेदन शुल्क
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) आंकड़े।

(घ) ईपीसी के साथ संदेश विनिमयता

पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) आंकड़े

(ङ.) जीएसटीएन और आरबीआई के साथ संदेश का आदान-प्रदान**1.21 तीसरा पक्ष एपीआई के विकास को बढ़ावा देना**

विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ताओं को डीजीएफटी के साथ सम्पर्क करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश करने हेतु अपनी प्रणाली के साथ एकीकरण हेतु तीसरा पक्ष साफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देगा।

1.22 आगामी ई-गवर्नेन्स की पहल

डीजीएफटी वर्तमान में निम्नलिखित ईडीआई पहलों पर कार्य कर रहा है:

- (i) सीमाशुल्क विभाग से डीजीएफटी तक प्रविष्टि बिलों (आयात ब्योरा) के प्रेषण के लिए संदेश का आदान-प्रदान करना।
- (ii) निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र को आनलाइन जारी करना।
- (iii) सीआईएन और डीआईएन सूचना हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संदेश का आदान-प्रदान करना।
- (iv) पैन हेतु सीबीडीटी के साथ संदेश का आदान-प्रदान करना।
- (v) ई-आईसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खुला एपीआई ।
- (vi) विदेश व्यापार नीति के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ।

1.23 निर्यात खेप हेतु मुक्त रास्ता

केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु वस्तुओं की खेप को किसी कारण से रोका/विलंब नहीं किया जाएगा। किसी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी निर्यातक से वचनबद्धता प्राप्त करके उस खेप को जारी कर सकता है।

1.24 निर्यात से संबंधित स्टॉक की जब्ती नहीं

किसी अभिकरण द्वारा कोई जब्ती नहीं की जाएगी जिससे विनिर्माण कार्यकलाप और निर्यात की सुपुर्दगी की निर्धारित अवधि अवरुद्ध हो। कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में संबंधित अभिकरण गंभीर अनियमितता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकता है। तथापि, ऐसे जब्त सामान को 7 दिनों के अंदर छोड़ा जा सकता है जब तक कि कोई अनियमितता साबित नहीं हो।

1.25 24X7 सीमाशुल्क निकासी

सीबीईसी ने सरलीकृत प्रविष्टि बिल और मुक्त पोत-लदान बिल के तहत निर्यातित फैक्टरी में भरे गए कंटेनर और माल हेतु वर्ष 2012 में 24X7 सीमा शुल्क निकासी की सुविधा लागू की है। इस समय यह सुविधा 19 समुद्री पत्तनों तथा 17 एयर कार्गो परिसरों में उपलब्ध है। 24X7 सीमा शुल्क निकासी की सुविधा अब 19 समुद्री पत्तनों तथा 17 एयर कार्गो परिसरों में सभी प्रविष्टि बिलों (न केवल सरलीकृत प्रविष्टि बिलों) के लिए भी प्रदान की गई है। इसके अलावा 24X7 सीमा शुल्क पत्तनों और एयरपोर्टों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमओटी शुल्क वसूलने की आवश्यकता नहीं है।

1.26 सीमाशुल्क कार्यालय में एकल खिड़की

भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने व्यापार को सुगम बनाना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 01.04.2016 से स्विफ्ट (व्यापार सुगमीकरण हेतु एकल खिड़की इन्टरफेस) लागू किया है। स्विफ्ट के अंतर्गत आयातक केवल सीमा शुल्क विभाग के पास एक ही स्थान पर एकीकृत घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य विनियामक एजेंसियों (जैसे पशु संगरोध, पौधा संगरोध, औषध नियंत्रक, वस्त्र समिति आदि) से अपेक्षित अनुमति यदि कोई हो आयातक/निर्यातक द्वारा इन एजेंसियों से अलग से सम्पर्क किए बिना आनलाइन प्राप्त की जाती है। एकल खिड़की स्कीम के लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. व्यापार करने में कम लागत;

ख. अधिक पारदर्शिता;

ग. कम पुनरावृत्ति और अनुपालन की कम लागत;

घ. जनशक्ति का अधिकतम उपयोग।

1.27 सीमाशुल्क का स्वयं आकलन

(क) वित्त अधिनियम, 2011 के तहत आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा सीमाशुल्क का स्वयं आकलन किया जाना प्रारंभ किया गया था। यह प्रणाली विश्वसनीयता पर आधारित है। इसका उद्देश्य आयात/निर्यात की गई वस्तुओं को शीघ्र निर्मुक्त कराना है। यह प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अनुसार प्रचालित होती है।

(ख) स्वमूल्यांकित प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने की तारीख को शुल्क/कर/उपकर भुगतान करने हेतु आयातक को प्राधिकृत करने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 में संशोधन किया है।

1.28 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम

(क) डब्ल्यूसीओ के मानकों के सेफ (एसएफई) ढांचा (एफओएस) के आधार पर भारतीय सीमाशुल्क द्वारा निम्नलिखित लाभ लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसाय को समर्थ बनाने के लिए 'प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम' विकसित किया गया है: अन्तर्राष्ट्रीय

- (i) निर्यात स्थल से आयात तक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला;
- (ii) विदेशी आयातकों/निर्यातकों को आपूर्ति करने हेतु संविदा करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन दर्शाने की क्षमता;
- (iii) परस्पर मान्यता करार (एमआरए) साझेदार देशों में सीमा पर परिवर्द्धित मंजूरी की सुविधाएं;
- (iv) सुरक्षा संबंधित गड़बड़ी के बाद कार्गो के परिचालन में न्यूनतम गतिरोध
- (v) रखने के समय और संबंधित लागत में कमी तथा
- (vi) सीमाशुल्क परामर्श/सहायता यदि व्यापार को उन देश के सीमाशुल्क के कार्यालयों के साथ अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न होती है जिनके साथ भारत का एमआरए है।

(ख) अन्य सीमाशुल्क प्रशासनों द्वारा एईओ कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं जो एईओ स्तर धारकों को जांच समय में कमी, शीघ्र स्वीकृति तथा अन्य लाभ प्रदान करके सीमाशुल्क विभाग की ओर से तरजीह देता है। इस प्रकार एईओ कार्यक्रम से इन सीमाशुल्क विभाग के प्रशासकों में आपसी मान्यता समझौता (एमआरए) होने की आशा है। एमआरए से यह सुनिश्चित होगा कि हमारे निर्यात माल को विदेश में प्रविष्टि के समय सीमाशुल्क विभाग की विधिवत सुविधा प्रदान की जाए। आपूर्ति श्रृंखला प्राप्त करने के अलावा इसके लाभों में माल को रोकने के समय में तथा परिणामस्वरूप व्यापार की लागत में कमी लाना शामिल है। भारत के सीमाशुल्क विभाग ने संबंधित एईओ कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए हांगकांग के सीमाशुल्क विभाग के साथ आपसी मान्यता समझौते (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि व्यापार में पारस्परिक आधार पर लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। भारत का सीमा शुल्क विभाग भी अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, संयुक्त राज्य अमरीका इत्यादि के साथ भी एमआरए को अंतिम रूप देने हेतु कार्यरत है।

(ग) विश्वास आधारित अनुपालन की ओर एक अगले कदम के रूप में भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने नए/पुनर्निर्मित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें उन फर्मों को अधिक सुविधा और स्व-प्रमाणन सहित विस्तृत लाभ प्रदान किए गए हैं जिन्होंने सीबीईसी के समक्ष आन्तरिक ठोस नियंत्रण प्रणाली और अनुपालन का प्रदर्शन किया है।

1.29 पोत लदान बिलों की पूर्व फाइलिंग की सुविधा

वास्तविक पोतलदान से पूर्व पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा पोतलदान बिलों को पोतलदान से पूर्व ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा दी गई है। इसे हवाई पोतलदान और आईसीडी के लिए 7 दिन के अंदर तथा समुद्र के रास्ते पोतलदान हेतु 14 दिनों के अंदर फाइल करना होता है।

1.30 शुल्क वापसी हेतु निर्यात सामान्य घोषणा (ईजीएम) फाइल करने में विलंब को कम करना

ईजीएम को शीघ्र फाइल करने तथा ईजीएम में होने वाली त्रुटियों को शीघ्र ठीक करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क विभाग के मुख्य आयुक्त द्वारा ईजीएम की मासिक निगरानी की जाती है ताकि इस संबंध में सुविधा में कोई विलंब न हो (अनुदेश सं. 603/01/2011-डीबीके दिनांक 31.07.2013)

1.31 विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु दी जाने वाली साझा बांड/एल्यूटी की सुविधा

सीबीईसी परिपत्र 11(ए)/2011-सीमाशुल्क दिनांक 25.02.2011 के तहत अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) हेतु साझा बांड/एल्यूटी के निष्पादन की वित्तीय वर्ष-वार सुविधा प्रदान की गई है जो सभी ईडीआई पत्तनों/स्थानों पर कारगर है।

1.32 विदेशों में प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर से छूट

(हटा दिया गया है।)

1.33 खराब होने वाले कृषि उत्पादों का निर्यात

सौदा और अनुक्षण लागत को कम करने हेतु खराब होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकल विन्डो प्रणाली प्रारंभ की गई है। प्रणाली में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित की जाने वाली बहुविध नोडल अभिकरणों को सृजित करना शामिल है। विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 1ग में अधिसूचित की गई है।

1.34 समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस)

सीमाशुल्क प्राधिकरण ने डब्ल्यूसीओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख सीमाशुल्क स्थलों पर छमाही आधार पर 'समय निर्गमन अध्ययन' (टीआरएस) करने का निर्णय लिया है। डब्ल्यूसीओ समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस) सीमाशुल्क के वास्तविक कार्यनिष्पादन को मापने का एक विशिष्ट साधन और पद्धति है। समय निर्गमन अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों/या सीमाशुल्क निर्मुक्ति को प्रभावित करने वाले अवरोधों की पहचान करना।
- (ii) आधाररेखा व्यापार सरलीकरण कार्यनिष्पादन पैमाना स्थापित करना।

1.35 निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई)

(क) उद्देश्य: निर्यात उत्पादन केन्द्रों का विकास एवं वृद्धि। कई शहर सक्रिय औद्योगिक समूह के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं। इन औद्योगिक समूहों को उनकी संभावनाओं को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने तथा नए बाजारों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से मान्यता प्रदान करना आवश्यक है।

(ख) निर्यात वृद्धि की संभावना के आधार पर 750 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक का माल उत्पादन करने वाले चुनिंदा शहरों को टीईई के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, हथकरघा, हस्तकला, कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में टीईई के लिए सीमा रेखा 150 करोड़ रुपए की होगी। ऐसे टीईई के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:

- (i) एमएआई स्कीम के तहत प्राथमिकता आधार पर विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवाओं की निर्यात संवर्धन परियोजनाओं के लिए इकाइयों के मान्यता प्राप्त संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ii) इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र लिए पात्र होंगे।

(ग) अधिसूचित शहर (टीईई) परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 1ख में सूचीबद्ध हैं।

1.36 व्यापार आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता

डीजीएफटी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन डीजीसीआई एंड एस एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है तथा यह व्यापार से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराती है। यह व्यापार आंकड़ा प्रदाता है जो निर्यात और आयात व्यापार के लिए मार्गदर्शन और निर्देशन के स्रोत का कार्य करता है जिससे निर्यातकों और आयातकों को अपने व्यापार की कार्यनीति तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है। डीजीसीआई एंड एस द्वारा विदेश व्यापार आंकड़ों का प्रसारण (i) सीडी के रूप में मासिक और तिमाही प्रकाशन (ii) प्रयोक्ता के अनुरोध के अनुसार विदेश व्यापार डाटाबेस से आंकड़े प्राप्त करके किया जाता है। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु एक मूल्य आधारित सूचना प्रणाली (पीआईएस) है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों को पूर्णतया छोड़ा गया है। डीजीसीआई एवं एस की एक आंकड़ा नियंत्रण नीति है। इस नीति का उद्देश्य आयातकों और निर्यातकों के व्यावसायिक रूप से संवेदनशील व्यापार आंकड़ों की गोपनीयता को कायम रखना है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सौदा स्तर के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। डीजीसीआई एंड एस व्यापार आंकड़ों को समग्र आधार पर व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार न्यूनतम संभाव्य समय सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा। डीजीसीआई एंड एस का विवरण www.dgciskol.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.37 सीमा शुल्क निकासी में प्रिन्टआउट में कमी लाना/समाप्त करना

व्यापार करना सरल करने और कागजमुक्त मंजूरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीबीईसी ने जीएआर 7 प्रपत्र/टीआर 6 चालान, टीपी प्रतिलिपि, प्रविष्टि बिल की विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि और पोतलदान बिल तथा पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि सहित अनेक दस्तावेजों की नैमित्तिक प्रिन्टआउट को समाप्त कर दिया है।

तथापि, पोतलदान बिल/प्रविष्टि बिल की ईपी प्रतिलिपि की हार्ड कापी केवल अनुरोध करने पर प्रदान की जाएगी।

1.38 राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण संबंधी समिति (एनसीटीएफ)

व्यापार सरलीकरण संबंधी डब्ल्यूटीओ समझौता पर अप्रैल, 2016 में भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण संबंधी समिति (एनसीटीएफ) का गठन किया गया है। समिति की स्थापना करना टीएफए की अनिवार्य, संस्थागत व्यवस्था का एक भाग है। व्यापार सरलीकरण संबंधी इस अन्तर मंत्रालयी निकाय की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाएगी। इसका सचिवालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निर्यात संवर्धन महानिदेशालय नई दिल्ली में होगा। एनसीटीएफ स्थापित करने का परिभाषित उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की निकाय की स्थापना करना है जो टीएफए प्रावधानों का घरेलू समन्वय और कार्यान्वयन का कार्य करेगा। यह व्यापार सरलीकरण के लिए समस्त भारत के लिए रोड मैप तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। यह देशभर के विभिन्न व्यापार सरलीकरण परिदृश्यों के बीच सामन्जस्य स्थापित करने का कार्य करेगा तथा टीएफए के बारे में सभी हितधारकों के सुग्राहीकरण के लिए आउटरीच कार्यक्रमों पर भी बल प्रदान करेगा।

1.39 ईमेल की पहल

सीबीईसी ने आयात मंजूरीयों के सभी महत्वपूर्ण चरणों से संबंधित सूचना के लिए आयातकों के लिए ई-मेल अधिसूचना की सेवा आरंभ की है।

1.40 आस्थगित भुगतान की सुविधा

व्यापार सरलीकरण के उपाय के रूप में सीबीईसी ने सीमा शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा लागू की है। इसके अलावा आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 अधिसूचित की गई है और यह 16.11.2016 से लागू हो गई है। एईओ कार्यक्रम (श्रेणी-2) और (श्रेणी-3) के अंतर्गत प्रमाणित आयातकों को इन नियमों का लाभ उठाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

अध्याय - 2

आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 उद्देश्य

माल एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात को शासित करने वाले सामान्य प्रावधानों की व्याख्या इस अध्याय में दी गई है।

2.01 आयात एवं निर्यात- 'मुक्त' जब तक कि विनियमित न किया जाए

(क) निर्यात एवं आयात मुक्त होंगे सिवाए उन मामलों में जब उन्हें 'प्रतिबंध' 'रोक' अथवा 'राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के जरिए अनन्य व्यापार' के माध्यम से विनियमित किया जाए जैसा कि निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित तंत्र) [आईटीसी (एचएस)] में निर्धारित किया गया है। 'प्रतिबंधित' 'रोक लगाई गई' और 'एसटीई' मदों की सूची <http://dgft.gov.in> के डाउनलोड्स पर क्लिक कर देखी जा सकती है।

(ख) इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी मदें हैं जो आयात/निर्यात हेतु 'मुक्त' हैं परन्तु अन्य अधिनियमों अथवा वर्तमान में लागू विधि में नियत शर्तों के अधीन हैं।

2.02 निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)]

(क) आईटीसी(एचएस) निर्यात/आयात हेतु सभी पण्य/माल के लिए कोडों का संकलन है। माल को उसके समूह अथवा उप-समूह के आधार पर 2/4/6/8 अंकों में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) आईटीसी(एचएस) को विश्व सीमाशुल्क संगठन (<http://www.wcoomd.org>) द्वारा देख-रेख किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय सुमेलित तंत्र माल नाम-पद्धति के साथ 6 अंकीय स्तर पर संरेख किया गया है। तथापि, भारत माल के राष्ट्रीय सुमेलित तंत्र को 8 अंकीय स्तर पर बनाए रखता है जिसे <http://dgft.gov.in> 'डाउनलोड्स' को क्लिक कर देखा जा सकता है।

(ग) सभी माल के लिए आयात/निर्यात नीतियाँ आईटीसी(एचएस) की प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई हैं। आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-1 में आयात नीति व्यवस्था निर्धारित की गई है जबकि आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-2 में निर्यात नीति व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) सिवाए उस मामले के जहाँ यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो, आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-1, आयात नीति नए माल के लिए है न कि पुराने माल के लिए। पुराने माल के लिए आयात नीति व्यवस्था इस विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.31 में दी गई है।

2.03 स्वदेशी कानूनों के साथ आयात का अनुपालन

(क) स्वदेशी उत्पादित माल पर लागू स्वदेशी कानून/नियम/आदेश/विनियम/तकनीकी विनिर्देशन/पर्यावरण/सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदण्ड यथा आवश्यक परिवर्तन सहित आयात पर लागू होंगे, यदि इन्हें विशिष्ट रूप से छूट नहीं दी गई हो।

(ख) तथापि, निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/खपत किए जाने वाले माल, डीजीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित, को घरेलू मानकों/गुणवत्ता विनिर्देशों से छूट दी जा सकती है।

2.04 प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकार

महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों तथा इस विदेश व्यापार नीति को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अथवा संशोधन, यदि कोई हो, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी।

आयातक निर्यातक कोड/ई-आईसी**2.05 आयातक निर्यातक कोड (आईसी)**

(I) आईसी किसी व्यक्ति को आवंटित की जाने वाली 10 अक्षर-अंकीय संख्या है जो किसी निर्यात/आयात कार्यकलाप आरंभ करने हेतु अनिवार्य होता है। किसी कम्पनी (फर्म/कम्पनी/एलएलपी आदि) की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से, जीएसटी के लागू/कार्यान्वित होने के परिणामस्वरूप आईसी पैन के समान होगा और आवेदन के आधार पर डीजीएफटी द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

(क) आईसी प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र लागू शुल्क के साथ एएनएफ-2क में आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है तथा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई-आईसी अनुमोदित कर दिया जाता है तो आवेदक के ई-मेल के जरिए यह सूचना दी जाती है कि डीजीएफटी वेबसाइट पर कम्प्यूटर सृजित ई-आईसी उपलब्ध है। "ऑनलाइन आईसी आवेदन" वेबपेज में अपेक्षित ब्यौरे भरकर और प्रस्तुत करने के पश्चात् "आवेदन स्थिति" पर क्लिक कर आवेदक अपना ई-आईसी देख सकता है और प्रिंट ले सकता है।

(ग) आवेदक आईसी आवेदन सहित निम्नलिखित ब्यौरों/दस्तावेजों (स्कैन की गई प्रतिलिपि को प्रस्तुत/अपलोड किया जाना है) के साथ आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(i) हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफ;

(ii) उस व्यवसाय कम्पनी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि जिनके नाम आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाले फर्मों के मामले में आवेदक स्वयं)

(iii) रद्द किया हुआ चेक जिसमें फर्म का पहले से ही प्रिन्टेड नाम हो या निर्धारित प्रपत्र एएनएफ-2क(झ) में बैंक प्रमाणपत्र।

(घ) आईसी में संशोधन के लिए आवेदक डिजिटल हस्ताक्षर (वर्ग-ii और वर्ग iii) के द्वारा देय फीस का भुगतान करके और मांगे गए परिवर्तनों के अनुरूप अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करके आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ड.) ई-आईसी हेतु आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश <<http://dgft.gov.in/exim/2000/iec an/iecanf.htm>>. पर उपलब्ध है।

(II) आईसी के बिना कोई निर्यात/आयात नहीं

- (i) जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती, किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक निर्यातक कोड नम्बर (आईसी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। विशेष
- (ii) छूट प्राप्त श्रेणियाँ और तदनुसूची स्थायी आई ई सी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.07 में दी गई है।

2.06 भारत से/में माल के निर्यात/आयात हेतु अनिवार्य दस्तावेज

(क) भारत से माल के निर्यात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज।

1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल/लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/डाक रसीद
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. पोत लदान बिल/निर्यात बिल/निर्यात का डाक बिल

(ख) भारत में माल के आयात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज।

1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल/लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/डाक रसीद
सीएन-22 या सीएन-23 फार्म में जैसा भी मामला हो,
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. प्रविष्टि बिल

[टिप्पणी: *(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी सीबीईसी परिपत्र के अनुसार

(ii) पृथक वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची भी स्वीकार किए जाएंगे।]

(ग) विशिष्ट माल अथवा माल की श्रेणी, के जो किसी प्रतिबंध/नीतिगत शर्तों अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा किसी संविधि के तहत उत्पाद विशिष्ट अनुपालनों के अधीन हों, के निर्यात अथवा आयात के लिए संबंधित प्राधिकारी निर्यात अथवा आयात के प्रयोजनों के अतिरिक्त दस्तावेज अधिसूचित कर सकता है।

(घ) निर्यात अथवा आयात के विशिष्ट मामलों में संबंधित विनियामक प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित में अतिरिक्त दस्तावेज अथवा जानकारी, विधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक हो, की माँग कर सकता है।

(ड.) उपर्युक्त शर्तें 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगी।

2.07 प्रतिबंध के सिद्धांत

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु आवश्यक निर्यात और आयात संबंधी प्रतिबंध लगाया जा सकता है :-

- (क) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण।
- (ख) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।
- (ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम।
- (घ) कौदी श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम।
- (ड.) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व संबंधी मूल्य की राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण।
- (च) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण।
- (छ) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण;
और
- (ज) हथियारों, गोला-बारूद और युद्ध के साजो-सामान के व्यापार की रोकथाम।
- (झ) सोना या चांदी के आयात या निर्यात से संबंधित

2.08 प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात

कोई भी माल/सेवा जिसका निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित है, का इस संबंध में जारी किए गए प्राधिकार पत्र/अनुमति के अनुसार या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।

2.09 स्कोमेट मर्दों का निर्यात

विशेष रसायनों, जीवों, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) का निर्यात जैसा कि निर्यात एवं आयात मर्दों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है, निर्यात प्राधिकारों के विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक में अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधानों के अलावा (i) समय-समय पर यथासंशोधित एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 का अध्याय IVक (ii) निर्यात एवं आयात मर्दों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की सारणी क की क्रम सं0 4 और 5 और परिशिष्ट-3 (iii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.16, पैरा 2.17, पैरा 2.18 तथा (IV) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.73-2.82 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

2.10 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

जिन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरूरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है जब तक कि महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त विशीं स्प से हटा न दी गई हो।

2.11 प्राधिकार पत्र की शर्तें

प्रत्येक प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी अन्य शर्तें जो विनिर्दिष्ट की जाए, के अलावा निम्नलिखित में से सभी या कुछ नियम एवं शर्तें (पैरा जिसके तहत प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, के अनुसार यथा लागू) शामिल होंगी:

- (क) माल का विवरण, मात्रा एवं मूल्य;
- (ख) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त; (अध्याय 9 में यथापरिभाषित)
- (ग) निर्यात दायित्व;
- (घ) प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य संवर्धन; और
- (ङ.) न्यूनतम निर्यात/आयात मूल्य
- (च) सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचन/बॉण्ड
(जैसा कि एफटीपी के पैरा 2.35 में दिया गया है)।
- (छ) प्रक्रिया पुस्तक में यथा विनिर्दिष्ट आयात/निर्यात की वैधता की अवधि।

2.12 आवेदन शुल्क

आईटीसी/प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/स्क्रिप के लिए आवेदन करते समय आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है जैसा कि परिशिष्टों और आयात निर्यात फार्मों के परिशिष्ट 2ट में दर्शाया गया है। फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) तंत्र या क्रेडिट/डेबिट कार्डों के द्वारा आनलाइन किया जाना चाहिए यदि अन्यथा कोई अन्य प्रावधान न हो।

2.13 प्राधिकार पत्र के अधीन सीमाशुल्क विभाग से माल की निकासी

अग्रिम में पहले ही आयातित/भेजा गया/आया हुआ माल परन्तु जिसकी निकासी सीमाशुल्क विभाग द्वारा नहीं की गई है, की निकासी बाद में निर्गमित प्राधिकार पत्र से भी की जा सकती है। तथापि, अग्रिम में पहले से आयातित/भेजे गए/आए हुए ऐसे माल को सर्वप्रथम गोदाम में माल रखने हेतु प्रविष्टि बिल के लिए माल को गोदाम में रखा जाता है और उसके बाद जारी प्राधिकार पत्र के लिए घरेलू खपत हेतु मंजूर किया जाता है। तथापि, यह सुविधा "प्रतिबंधित" वस्तुओं अथवा एसटीई के जरिए व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

2.14 प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है

कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्राधिकार पत्र देने या नवीकरण करने से इंकार करने का अधिकार होगा।

2.15 दंडात्मक कार्रवाई और निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) में किसी कम्पनी को रखना

(क) यदि कोई प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है अथवा राजस्व विभाग और/अथवा डीजीएफटी द्वारा जारी माँग सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और देशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी भी कानून के अनुसार कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा।

(ख) नैतिक मानकों का स्तर उठाने के उद्देश्य से और व्यापार करते हुए सुविधा हेतु डीजीएफटी ने विभिन्न स्कीमों के तहत स्व-प्रमाणन प्रणाली की व्यवस्था की है। ऐसे मामलों में आवेदकों को स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया में जानकारी/विवरण भरने समय पर्याप्त ध्यान और सावधानी बरतनी है। बाद में किसी जानकारी/विवरण के असत्य/गलत पाए जाने पर किसी अन्य अधिनियम/आदेश के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा एफटीडीआर अधिनियम, 1992 और तत्संबंधी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी फर्म को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियमन के प्रावधान के तहत निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखा जा सकता है। लिखित में कारणों को दर्ज किए जाने हेतु ऐसा आदेश जारी करने पर किसी फर्म को वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप अथवा किसी लिखित प्रदान किए जाने अथवा नवीकरण से इन्कार किया जा सकता है। यदि किसी फर्म को डीईएल के तहत रख दिया जाता है तो सभी नए लाइसेंस, स्क्रिप, प्रमाण-पत्र, लिखत आदि को मुद्रण/निर्गम/नवीकरण से रोक दिया जाएगा।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए डीईएल आदेशों को स्थगित किया जा सकता है। डीईएल आदेश को एक बार में 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता।

(ड.) यदि फर्म निर्यात दायित्व पूरा कर लेती है/दंड राशि का भुगतान कर देती है/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी माँग सूचना की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा कर दिया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए, डीईएल से फर्म के नाम को हटाया जा सकता है।

प्रतिबंध (देश, संगठन, समूह, व्यक्ति आदि और उत्पाद विशिष्ट)

2.16 इराक से/को 'हथियारों और संबंधित सामान' के आयात और निर्यात पर निषेध

'हथियारों और संबंधित सामान' के लिए नीति जो कि आईटीसी (एचएस) के अध्याय 93 में दी गई है, के बावजूद इराक से/को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात 'निषिद्ध' है। तथापि, इराक सरकार को हथियार और संबंधित सामग्री के निर्यात की अनुमति खाता उत्पादन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी।

2.16क: इराक और लेवंट में इस्लामिक स्टेट [आईएसआईएल देश के रूप में भी ज्ञात], अल नुसरा फ्रंट [एएनएफ] और अल कायदा से जुड़े व्यक्ति, समूह, उपक्रम तथा फर्म के साथ व्यापार पर निषेध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प सं० 2199 [2015] (संकल्प का पूर्ण पाठ <http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm> पर उपलब्ध है) के अनुपालन में, इराक और लेवंट में इस्लामिक स्टेट [आईएसआईएल], अल नुसरा फ्रंट [एएनएफ] और अल कायदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, अन्य व्यक्ति, समूह, उपक्रम तथा फर्म के साथ सांस्कृतिक (प्राचीन कालीन वस्तुओं सहित), वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व की वस्तुओं के अलावा तेल तथा परिशोधित तेल उत्पाद, माड्यूलर रिफाइनरी और संबंधित सामग्रियों का व्यापार निषिद्ध है।

2.17 कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध

कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को, मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात चाहे कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, का विवरण विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट—I में दिया गया है:

2.18 ईरान से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात/निर्यात

(क) ईरान को निम्नलिखित दस्तावेजों में उल्लिखित किसी मद सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231(2015) के अनुलग्नक—ख में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन अनुमत होगा:

(i) आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी9/भाग-1 में और आईएनएफसीआईआरसी/254/ आरईवी.7/भाग-2 (आईईईए दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें जैसा कि आईईईए द्वारा समय-समय पर अद्यतनकृत किया गया हो।

(ii) एस/2006/263(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें जैसा कि सुरक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर अद्यतन किया गया है।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्प/ दस्तावेज और आईईईए दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट (www.un.org/Docs/sc) और आईईईए की वेबसाइट (www.iaea.org) पर उपलब्ध है।

2.19 सोमालिया से चारकोल के आयात पर रोक

सोमालिया से चारकोल का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात निषिद्ध है, चाहे ऐसे चारकोल की उत्पत्ति सोमालिया [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2036 (2012)] में हुई हो या नहीं हुई हो। चारकोल के आयातक सीमा-शुल्क कार्यालय को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि खेप की उत्पत्ति सोमालिया में नहीं हुई है।

राज्य व्यापार उद्यमों के द्वारा आयात/निर्यात:

2.20 राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)

(क) विपणन बोर्डों सहित राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) सरकारी और गैर-सरकारी उद्यम हैं जो निर्यात और/या आयात संबंधी माल का व्यापार करते हैं। कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी(एच एस) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित राज्य व्यापार उद्यमों की सूची परिशिष्ट-2 में है।

(ख) ऐसा राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं, ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।

(ग) तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल, एसटीई के जरिए अनन्य व्यापार हेतु अधिसूचित, के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है।

विशिष्ट देशों के साथ व्यापार:

2.21 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी स्कीम बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

2.22 माल लाने-ले-जाने की सुविधा

भारत से अथवा भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी।

2.23 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीम बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधान, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।

माल की विशिष्ट श्रेणियों का आयात

2.24 नमूनों का आयात

नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.65 द्वारा शासित होगा।

2.25 उपहारों का आयात

आईटीसी(एच एस) के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों का आयात मुक्त होगा। अन्य मामलों में महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किसी प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातों की अनुमति होगी।

2.26 यात्री असबाब

(क) वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों की शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है।

(ख) ऐसी मर्दों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी प्राधिकार पत्र के बिना यात्री असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है।

(ग) विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, प्राधिकार पत्र के बिना, अपने यात्री असबाब के रूप में, निर्यात के लिए आवश्यक ड्राइंग, पैटर्न्स, लेबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ड्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।

2.27 विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात

आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, पुर्जे और अनौपचारिक, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण, टेक्नोलॉजी में गुणवत्ता सुधार अथवा उन्नयन अथवा मानकीकरण के लिए किसी प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है।

2.28 विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात

विदेश में परियोजनाएँ पूरी हो जाने के बाद, परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो।

2.29 प्रोटो टाइप्स का आयात

वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) को नई/पुराने प्रोटोटाइप्स/पुराने नमूनों का आयात शुल्क के भुगतान पर बिना प्राधिकार पत्र के किया जा सकता है, जो उत्पादन कार्य में लगें हैं या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र है कि वे उत्पाद विकास या अनुसंधान के लिए जैसा भी मामला हो, प्रोटो टाइप की जरूरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुस्यू स्व घोषणा करके आयात कर सकते हैं।

2.30 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से आयात

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी अधिसूचना (ओं) के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा या डाक के माध्यम से आयात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों का आयात विदेश व्यापार नीति/ आईटीसी(एचएस), 2017 के अनुसार विनियमित होगी।

पुराने माल के लिए आयात नीति

2.31 पुरानी वस्तुएं

क्रम सं०	पुराने माल की श्रेणियाँ	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
I	पुराने पूंजीगत माल		
(क)	(i) निजी कम्प्यूटर्स/लैपटॉप्स उनके नवीकृत/दुरुस्त पूर्ण सहित (ii) फोटोकॉपियर मशीनें/डिजिटल बहुकार्य प्रिन्ट और कार्पिंग मशीनें (iii) एयर कंडीशनर्स (iv) डीजल जेनरेटिंग सेट	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति
(ख)	पूंजीगत माल के नवीकृत/दुरुस्त पुर्जे	मुक्त	सनदी अभियन्ता के इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन कि ऐसे पुर्जों का मूल पुर्जे के न्यूनतम 80% का शौ जीवनकाल है।
(ग)	अन्य सभी पुराने पूंजीगत माल (उपर्युक्त (क) और (ख) को छोड़कर)	मुक्त	
II	पूंजीगत माल को छोड़कर पुराने माल	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति।

धात्विक छीजन और स्क्रेप की आयात नीति:**2.32 धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात**

(क) किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रेप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूतित वेस्ट/स्क्रेप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या प्रयुक्त हुआ बारूद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, शामिल नहीं होगा जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 में उल्लेख है।

(ख) धात्विक छीजन और स्क्रेप जिसका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, और टुकड़े रूप में; बिना टुकड़े और सम्पीड़ित तथा ढीले रूप में आयात की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 में निर्धारित किए गए हैं।

2.33 एसईजेड से स्क्रेप/अपशिष्ट को हटाना

एसईजेड यूनिट/डेवलपर/को-डेवलपर को देय सीमा शुल्क का भुगतान कर किसी प्राधिकार पत्र के बिना विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण कार्यकलाप के दौरान सृजित किसी भी प्रकार के धात्विक अपशिष्ट और स्क्रेप सहित किसी भी अपशिष्ट या स्क्रेप को डीटीए में निपटान करने हेतु अनुमत किया जा सकता है।

आयात से संबंधित अन्य प्रावधान**2.34 पट्टा वित्त प्रबन्धन के अधीन आयात**

पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति आवश्यक नहीं है।

2.35 विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन

(क) जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निर्धारित तरीके से विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी/बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

(ख) स्वदेशी प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक को प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-2 में यथानिर्दिष्ट स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.36 आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मर्दों, हथियारों और गोला-बारूद, खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे बांडेड गोदामों में रख सकता है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहाँ कहीं जरूरी हो, प्राधिकार-पत्र के मद्दे, घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी की जा सकती है। ऐसे माल पर ऐसी वस्तुओं की, निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार गोदाम में रखे गए माल की निकासी की जाएगी।

2.37 खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित वस्तुओं हेतु विशेष प्रावधान

डी टी ए बिक्री के प्रयोजन हेतु पब्लिक बांडेड गोदाम में खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित चमड़े का आयात किया जा सकता है तथा उनकी अनबिकी मर्दों को निर्यात शुल्क की लागू दर का भुगतान करने पर ऐसे बांडेड गोदाम से पुनः निर्यात किया जा सकता है।

2.38 महासागर में बिक्री

भारत में आयात हेतु खुले समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।

निर्यात:**2.39 मुक्त निर्यात**

जब तक ये निर्यात आई.टी.सी.(एच एस) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी वस्तुओं का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है।

2.40 हटा दिया गया है।**2.41 सहायक विनिर्माताओं हेतु लाभ**

सहायक विनिर्माता को प्राप्त होने वाले किसी लाभ (विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.58 में यथा परिभाषित) को प्राप्त करने के लिए सहायक विनिर्माता तथा व्यापारी निर्यातक दोनों के नामों का संबंधित निर्यात दस्तावेजों विशेषतः एआरई-1/एआरई3/पोत लदान बिल/निर्यात बिल/एयरवे बिल पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.42 तीसरा पक्ष निर्यात

अध्याय 9 में यथा परिभाषित तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात (मान्य निर्यात को छोड़कर) की अनुमति विदेश व्यापार नीति के तहत होगी। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे पोत लदान बिलों पर विनिर्माण निर्यातक/विनिर्माता तथा तृतीय पक्ष निर्यातक/निर्यातकों दोनों के नामों का उल्लेख किया जाएगा। बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी), निर्यात आदेश और बीजक तृतीय पक्ष निर्यातक के नाम में होने चाहिए।

विशिष्ट श्रेणियों का निर्यात:**2.43 नमूनों का निर्यात**

नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.66 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

2.44 उपहारों का निर्यात

किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में, खाद्य मदों सहित, 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा। तथापि, निर्यात की आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार-पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता।

2.45 यात्री असबाब का निर्यात

(क) वास्तविक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर निर्यात किया जा सकता है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना ज़रूरी होगा। तथापि, सरकारी तैनाती पर विदेश जाने वाले भारत सरकार के अधिकारियों को अपने नितान्त व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपना व्यक्तिगत असबाब, खाद्य सामग्री (मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध) अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। पैरा के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी असबाब नियमावली के अधधीन होंगे।

(ख) उन मदों के नमूने जो विदेश व्यापार नीति के तहत अन्यथा निर्यात योग्य हैं, बिना प्राधिकार पत्र के यात्री असबाब के रूप में भी निर्यात किए जा सकते हैं।

2.46 निर्यात हेतु आयात

I. (क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी रूप में या वस्तुतः उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि आयात या निर्यात की जाने वाली मद आईटीसी(एचएस) में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित न हो।

(ख) पूंजीगत माल (नया और पुराने सहित) सहित माल का निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है बशर्ते:

- (i) आयातक सीमाशुल्क विभाग के बांड के तहत माल को स्वीकृत कराता है;
- (ii) माल मुक्त रूप से निर्यात किए जाने योग्य है अर्थात् 'प्रतिबंधित'/निषिद्ध नहीं है जो राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से किए जाने वाले विशेष व्यापार अथवा आईटीसी(एचएस) की निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित किसी शर्त/ आवश्यकता के अधीन है।

(iii) निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित माल में आयात हेतु 'प्रतिबंधित' माल (निषिद्ध मदों को छोड़कर) शामिल होगा।

(घ) मुक्त रूप से आयात योग्य तथा निर्यात योग्य पूंजीगत माल का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन किए जाने पर निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है।

(ङ.) उपर्युक्त के बावजूद माल जिनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, का उन मदों के सिवाय जोकि निर्यात की निषिद्ध या स्कोमेट सूची में हैं, उसी या काफी हद तक उसी रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधधीन पुनः निर्यात किया जा सकता है जबकि ऐसे माल निर्यात हेतु "प्रतिबंधित" सूची में हैं:

- (i) माल भारतीय मूल के नहीं हों;
- (ii) आयातित माल सीमा शुल्क के पर्यवेक्षण के अधीन बाण्डेड गोदाम में रखे जाएंगे;
- (iii) निर्यात किए जाने वाले माल को घरेलू खपत हेतु मंजूरी नहीं दी गई है;
- (iv) माल का निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अधीन होगा।

II. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे आयातित माल को निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान किए जाने के मद्दे ही दी जाएगी जब तक डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो।

(ख) ऐसे माल को अधिसूचित देशों (वर्तमान में केवल ईरान) में निर्यात करने की अनुमति भारतीय रुपये में भुगतान किए जाने के मद्दे की जाएगी जो न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन के अधीन है।

(ग) तथापि, ईरान को निर्यात हेतु खाद्य सामग्री, दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों अर्थात् आईटीसी (एचएस) के अध्याय 2 से 4, 7 से 11, 15 से 21, 23, 30 तथा आईटीसी (एचएस) के अध्याय-90 के शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के अंतर्गत मर्च न्यूनतम मूल्य संवर्धन की आवश्यकता के अधीन नहीं होंगी। तथापि ईरान को होने वाला इन मर्चों का आयात विदेश व्यापार नीति 2015-20 और आईटीसी (एचएस) 2017 की अन्य सभी शर्तों, यदि लागू हों, के अधीन होगा। आईटीसी (एचएस) 0407, 0408 के अंतर्गत शामिल पक्षी के अंडे तथा आईटीसी (एचएस) 1006 के अंतर्गत शामिल चावल उपर्युक्त II (क) के अनुसार इस छूट के अंतर्गत नहीं हैं।

(घ) उपर्युक्त I (ड.) और II (क), (ख) और (ग) के अनुसार इस छूट के अंतर्गत किया जाने वाला निर्यात किसी निर्यात-लाभ को प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

2.47 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात

पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमत है। तथापि ऐसी मर्चों का आयात/निर्यात किया जाना विदेश व्यापार नीति/आईटीसी (एचएस), 2017 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2.48 प्रतिस्थापन माल का निर्यात

निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात हेतु अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित/स्कोमेट मर्चों के तौर पर उल्लिखित न हो। यदि निर्यात का मर्च 'प्रतिबंधित' /स्कोमेट के अधीन है तो निर्यातक को प्रतिस्थापन हेतु निर्यात लाइसेन्स की आवश्यकता होगी।

2.49 मरम्मत किए गए माल का निर्यात

निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर, कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये गये तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान की प्राधिकार-पत्र के बिना और सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी। उस सीमा तक निर्यातक लौटाए गए माल पर लिए गए लाभ/प्रोत्साहन को वापस करेगा। यदि मर्च आयात के लिए प्रतिबंधित है तो निर्यातक को आयात लाइसेन्स की आवश्यकता होगी।

तथापि, कंपनियों/फर्मों तथा वास्तविक उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा ऐसे खराब हिस्सों/पुर्जों का पुनः निर्यात करना अनिवार्य नहीं होगा यदि इन्हें विशेष रूप से मूल कारण का पता लगाने, परीक्षण और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयात किया गया है।

2.50 अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात

संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स के वारंटी स्पेयर्स (देशी अथवा आयातित) या कोई अन्य माल, (आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित मर्चों को छोड़कर) का मुख्य उपकरण के साथ अथवा बाद में निर्यात किया जा सकता है किन्तु यह ऐसे माल की वारंटी अवधि के भीतर ही हो बशर्ते कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो।

2.50क उपयोग हेतु खराब और अनुपयुक्त पाए गए आयातित माल का पुनः निर्यात:

सीमा शुल्क निकासी के बाद खराब पाए गए या विनिर्देशनों अथवा शर्तों के अनुसार नहीं पाए गए आयातित माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार वापस निर्यात किया जा सकता है।

2.51 निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डीटीए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जा सकती है।

(ख) ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के हकदार होंगे। ऐसे अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

आयात/निर्यात हेतु भुगतान और प्राप्ति

2.52 निर्यात संविदाओं का कोटिकरण

(क) सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी।

(ख) तथापि, विशेष निर्यातों के मद्दे निर्यात प्राप्तियां रूपों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रूप से परिवर्तनीय वॉस्ट्रो खाते के जरिए हों। इसके अतिरिक्त वॉस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे हो। इस सौदे के कारण खरीदार को अपने अप्रवासी बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रूप में गिना जाएगा।

(ग) संविदाओं (जिनके लिए भुगतान एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे) को एसीयू डालर के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा। तथापि, एसीयू के प्रतिभागी आरबीआई की अधिसूचनाओं के अनुसार एसीयू डालर या एसीयू में अपनी लेनदेन निष्पादित कर सकते हैं। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के मद्दे निर्यात ठेकों और बीजकों का भारतीय रूपों में नामकरण किया जा सकता है।

2.53 ईरान को निर्यात-विदेश व्यापार नीति के लाभों/प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनने के लिए भारतीय रूपों में वसूली

उरोक्त पैरा 2.52(क) में निहित प्रावधानों के अलावा ईरान को किए गए विशेष निर्यातों से भारतीय रूपों में प्राप्त निर्यात आय पर विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्यात लाभ प्रोत्साहन उपलब्ध होगा जो मुक्त परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के समतुल्य होगी।

2.54 निर्यात आय की गैर वसूली

(क) यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे निर्यातों के लिए उठाए गए सभी लाभों/प्रोत्साहनों का वापस करना होगा और उसके विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ख) यदि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर (अप्रत्याशित घटना) की वजह से निर्यात आय प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो वह प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.87 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त न हुई राशि को बट्टे-खाते डालने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क कर सकता है।

(ग) बीमा कवर के जरिए प्राप्त राशि विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ हेतु पात्र होगी। ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.85 में डाल दी गई है।

2.54क: निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए)

(i) निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की नीति संबंधी साधन हैं। ईसीए बीमा, गारंटी और प्रत्यक्ष ऋण के द्वारा निर्यात को सहायता प्रदान करती है। निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) जैसे भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लि० (ईसीजीसी) निर्यात को और निर्यात क्रेडिट ऋण को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करती है। निर्यातकों को ईसीजीसी द्वारा दिए गए कवर की देखरेख करती है, क्रेता के दिवालिएपन या चूक के कारण अथवा राजनीतिक जोखिम के कारण भुगतान असफल होने से उत्पन्न हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। निर्यातक ऐसे कवर के द्वारा मौजूदा बाजारों की रक्षा के अलावा अपने बाजारों का विविधीकरण करते हैं। ईसीजीसी परियोजना निर्यात सहित मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) निर्यात को भी सहायता देता है। एक्जिम बैंक एमएलटी की क्रेडिट लाइन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ईसीए है।

(ii) ईसीजीसी क्रेता के दिवालिएपन या चूक के कारण निर्यात व्यापार में निर्यातकों की हानि की क्षतिपूर्ति करता है। इसके अलावा पोतलदान कर दिए जाने के बाद युद्ध, अचानक आयात प्रतिबंध, कानून या आज्ञाप्ति के प्रख्यापन जैसे राजनीतिक जोखिम के कारण हानि को भी कवर किया जाता है। पोतलदान कर दिए जाने के बाद पाटन-रोधी के कुछ उपाय या गैर-प्रशुल्क अवरोध राजनीतिक जोखिम के अधीन आएं। ऐसे मामले में ईसीजीसी द्वारा निर्यातक के हित की रक्षा की जाती है।

निर्यात संवर्धन परिषदें

2.55 आरसीएमसी जारी करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करना।

(क) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं जिनकी स्थापना भारतीय निर्यातों का संवर्धन और विकास करने के लिए की गई है। प्रत्येक परिषद एएनएफ के परिशिष्ट 2न के अनुसार उत्पादों/परियोजनाओं/सेवाओं के एक विशिष्ट समूह के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

(ख) ईपीसी अपने सदस्यों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। ईपीसी के लिए अपने सदस्यों को आरसीएमसी जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में चिन्हित करने के मानदंड प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 2.92 में दिए गए हैं।

2.56 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी)

कोई भी व्यक्ति,

(क) जो आईटीसी (एचएस) में प्रतिबंधित मदों के रूप में सूचीबद्ध आयात/निर्यात (मदों के अतिरिक्त) के लिए प्राधिकार पत्र

अथवा

(ख) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डीजीएफटी की वेबसाइट पर आयातक निर्यातक प्रोफाइल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत अथवा अपलोड करना होगा जब तक कि इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार नीति के तहत विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो। मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र (सी आर ई एस) और कॉयर् बोर्ड द्वारा जारी कॉयर् के उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र को इस नीति के तहत प्रयोजनों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर सी एम सी) के रूप में माना जाएगा।

नीतिगत व्याख्या और छूटें**2.57 नीतिगत व्याख्या**

(क) नीतिगत व्याख्या, अथवा प्रक्रिया-पुस्तक के प्रावधान, परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों अथवा आईटीसी(एचएस) के आयात/निर्यात के लिए किसी मद के वर्गीकरण से संबंधित सभी मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय की सहायता करने और सलाह देने के लिए एक नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) का गठन किया जा सकता है। पीआईसी की रचना निम्नानुसार होगी:-

- (i) महानिदेशक, विदेश व्यापार: अध्यक्ष
- (ii) मुख्यालय के सभी अपर महानिदेशक विदेश व्यापार: सदस्य
- (iii) नीतिगत मामलों को बनाने वाले मुख्यालय में कार्यरत सभी संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार: सदस्य
- (iv) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (पीआरसी/पीआईसी): सदस्य-सचिव
- (v) अध्यक्ष द्वारा सह-चयनित संबंधित मंत्रालय/विभाग का कोई अन्य व्यक्ति/प्रतिनिधि

2.58 नीति/प्रक्रिया से छूट

विदेश व्यापार महानिदेशालय जनहित में ऐसे आदेश जारी कर सकता है अथवा ऐसी छूट, रियायत, उपाय प्रदान कर सकता है जोकि वह विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान अथवा किसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा श्रेणी पर व्यापार पर विपरीत प्रभाव और वास्तविक कठिनाइयों के आधार पर उपयुक्त समझता है। ऐसी छूट प्रदान करते समय, विदेश व्यापार महानिदेशालय समिति से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह उपयुक्त मानता हो।

क्रम सं०	विवरण	समिति
(क)	उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानदण्ड समितियाँ
(ख)	पूँजीगत माल (सीजी) और ईपीसीजी स्कीम के तहत लाभों का संबंध	ईपीसीजी समितियाँ
(ग)	अन्य सभी मामले	नीतिगत छूट समिति(पीआरसी)

2.59. शिकायत निवारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई

(क) सरकार व्यापार और उद्योग जगत से शिकायतों के तीव्र और शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.58 में व्यापार पर वास्तविक कठिनाईयों और विपरीत प्रभाव के आधार पर नीति और प्रक्रिया में छूट प्रदान करने का प्रावधान है। यदि कोई आयातक/निर्यातक नीतिगत छूट संबंधी समिति (पीआरसी) द्वारा लिए गए किसी निर्णय या विदेश व्यापार महानिदेशालय में किसी प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय/आदेश से असंतुष्ट है तो परिशिष्ट-2 ट के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) हेतु महानिदेशक के समक्ष विशिष्ट अनुरोध करना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय संबंधित मानदण्ड समिति, ईपीसीजी समिति अथवा नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) से विचार विमर्श करने के पश्चात् छूट पर विचार कर सकता है और व्यक्तिगत सुनवाई के अनुसरण में सूचित निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के संबंधित प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय कार्रवाई चाहे वह पहली अवस्था में हो अथवा अपीलीय अवस्था सहित किसी कार्यवाही में लिए गए निर्णय/आदेश पर लागू नहीं होगा।

2.60 बंदोबस्त आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमा शुल्क और ब्याज का निपटान

ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए जिन्होंने ऐसे कारण, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और रुण इकाइयों के विलयन, अभिग्रहण और पुनर्वास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए राजस्व विभाग में बंदोबस्त आयोग को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

उदगम होने वाले माल का स्व-प्रमाणन

2.61 उदगम के प्रमाण-पत्र पर स्वप्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम

(i) फिलहाल विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों(एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत उदगम के प्रमाणपत्र परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ख के अनुसार नामित एजेंसियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। सौदा लागत को कम करने के उद्देश्य से स्वप्रमाणन की एक वैकल्पिक प्रणाली शुरू की जा रही है।

(ii) विनिर्माता जो कि स्तर धारक भी हैं अनुमोदित निर्यातक स्कीम के भी पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक अपने विनिर्मित माल को प्रचलित विविध पीटीए/एफटीए/सीईसीए/ सीईपीए के तहत तरजीही समझौते को पास करने के उद्देश्य से भारत में बनाया हुआ दर्शाने के लिए स्वप्रमाणित करने के हकदार होंगे। स्वप्रमाणन केवल उसी माल के लिए अनुमत होगा जोकि विनिर्माताओं को जारी औद्योगिक उद्यम संबंधी ज्ञापन (आईईएम)/औद्योगिक लाइसेंस (आईएल)/आशय-पत्र (एलओआई) के अनुसार हो।

(iii) परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च के साथ पठित प्रक्रिया-पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.109 के विवरणों के अनुसार डीजीएफटी द्वारा अपेक्षित अवसंरचना, क्षमता और प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्व-प्रमाणन के लिए प्राधिकृत निर्यातकों के रूप में स्तरधारकों की पहचान की जाएगी।

(iv) दण्ड प्रावधानों के साथ स्कीम का विवरण परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च में दिया गया है और केवल तभी लागू होगा जब भारत स्कीम को अपने सहभागी/सहभागियों के साथ एक विशिष्ट समझौते के रूप में शामिल करता है और इसे डीजीएफटी द्वारा उपयुक्त रूप से अधिसूचित किया जाता है।

2.62 यूरोपीय संघ सामान्यीकृत अधिमानता प्रणाली (ईयू-जीएससी) के लिए माल के उदगम का प्रमाणपत्र

निर्यातक पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत यूरोपीय संघ (ईयू) की स्व-प्रमाणन स्कीम के अनुसार अपने माल के उदगम संबंधी विवरण को स्वप्रमाणित कर सकते हैं जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.104(ग) में दिया गया है।

अध्याय-3

भारत से निर्यात संबंधी स्कीम**3.00 उद्देश्य**

इस अध्याय के तहत स्कीमों का उद्देश्य अवसंरचनात्मक खामियों एवं उनसे जुड़ी लागतों को पूरा करने हेतु निर्यातकों को प्रतिफल देना है।

3.01 भारत से निर्यात संबंधी स्कीम

वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित क्रमशः दो स्कीमें होंगी:

- (i) भारत से वाणिज्यिक-वस्तु के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)
- (iii) भारत से सेवाओं का निर्यात स्कीम (एसईआईएस)

3.02 प्रतिफलों की प्रकृति

एमईआईएस और एसईआईएस के अन्तर्गत प्रतिफल के रूप में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाएगी। इनके तहत आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई वस्तुएं और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगी। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों का निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जा सकता है:

- (i) डीओआर अधिसूचना के अनुसार, परिशिष्ट 3(क) में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर पूंजीगत वस्तुएं सहित निविष्टियों या वस्तुओं के आयात के लिए सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1), 3(3), 3(5) में विनिर्दिष्ट मूल सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान।
- (ii) निविष्टियों या वस्तुओं की घरेलू प्राप्ति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान।
- (iii) हटा दिया गया है।
- (iv) इस नीति के पैरा 3.18 के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1), 3(3), 3(5) में विनिर्दिष्ट मूल सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान।

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)**3.03 उद्देश्य**

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) का उद्देश्य अधिसूचित वस्तुओं/उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देना है।

3.04 एमईआईएस के अन्तर्गत पात्रता

परिशिष्ट 3ख में यथा सूचीबद्ध आईटीसी (एचएस) कोड के साथ अधिसूचित बाजारों को अधिसूचित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात को एमईआईएस के तहत प्रतिफल प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न अधिसूचित उत्पादों (आईटीसी-एचएस कोड वारे) पर प्रतिफल का दर (रें) की सूचियाँ भी परिशिष्ट 3ख में होंगी। प्रतिफल के परिकलन का आधार जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात का प्राप्त एफओबी मूल्य अथवा मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पोतलदान बिलों में दिए गए निर्यात का एफओबी मूल्य, जो भी कम हो, होगा।

3.05 ई-कामर्स प्रयोग करने वाले कूरियर या विदेश के डाक कार्यालयों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात

- (i) परिशिष्ट 3ग की अधिसूचना के अनुसार ई-कामर्स का उपयोग करते हुए कूरियर अथवा विदेश के डाक कार्यालयों के माध्यम से 25000 रुपये प्रति खेप की एफओबी मूल्य तक की वस्तुओं का निर्यात एमईआईएस के अंतर्गत प्रतिफल प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- (ii) यदि ई-कामर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए निर्यात का मूल्य 25000 ₹ प्रति खेप से अधिक है तो, एमईआईएस प्रतिफल केवल 25000 ₹ के एफओबी मूल्य तक सीमित होगा।
- (iii) ऐसी वस्तुएं नई दिल्ली, मुंबई और चैन्नई में स्थित विदेश डाक कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल विधि में निर्यात की जा सकती है।

(iv) कूरियर विनियमों के अधीन ऐसे माल का निर्यात, राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों में उपयुक्त संशोधनों के अनुसार दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में स्थित विमानपत्तनों के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मैनुअल विधि द्वारा अनुमत किया जाएगा। राजस्व विभाग कूरियर टर्मिनलों पर ईडीआई विधि का कार्यान्वयन फास्ट-ट्रैक आधार पर करेगा।

3.06 एमईआईएस के अन्तर्गत अपात्र श्रेणियाँ

एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट हकदारी के लिए निम्नलिखित निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र अपात्र होंगे:

- (i) एसईजेड इकाइयों को डीटीए इकाइयों से आपूर्ति की गई हो।
- (ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के तहत आयात की गई वस्तुओं का निर्यात।
- (iii) पोतांतरण के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का उद्गम तो तृतीय देशों में हुआ है लेकिन भारत से पोतांतरण किया गया हो।
- (iv) मान्य निर्यात।
- (v) डीटीए इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद।
- (vi) निर्यात उत्पाद जो कि न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन हो।
- (vii) एफटीडब्ल्यूजेड में इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात।

भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)

3.07 उद्देश्य

भारत से सेवा निर्यात की स्कीम का उद्देश्य भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना और इष्टतम बनाना है।

3.08 पात्रता

(क) भारत में स्थित, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को एसईआईएस के अन्तर्गत प्रतिफल दिया जाएगा। केवल इस नीति के पैरा 9.51(i) और पैरा 9.51(ii) के अनुसार दी गई सेवाएं ही पात्र होंगी। अधिसूचित सेवाएं और प्रतिफल की दरें परिशिष्ट 3घ में सूचीबद्ध की गई हैं।

(ख) ऐसे सेवा प्रदाता, जिनके पास गत वित्त वर्ष में 15,000 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निवल मुक्त विदेशी मुद्रा आय हो, वे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए पात्र होंगे। व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं और एकल स्वामित्व के लिए गत वित्त वर्ष में 10,000/- अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निवल मुक्त विदेशी मुद्रा आय का मानदंड होगा।

(ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं पर अर्जित सेवा शुल्क के लिए, भारतीय स्मरणों में किया गया भुगतान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य विदेशी मुद्रा में प्राप्ति माना जाएगा। ऐसी सेवाओं की सूची परिशिष्ट 3ड. में दर्शाई गई है।

(घ) योजना के लिए निवल विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार परिभाषित की गई है: निवल विदेशी मुद्रा = विदेशी मुद्रा की सकल आय घटा कुल खर्च/भुगतान/वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रेषण।

(ड.) यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता और साथ ही साथ सेवा प्रदाता भी है तो विदेशी मुद्रा आय और कुल खर्च/भुगतान/प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए विचारणीय होगा।

(च) योजना के अधीन प्रतिफल का दावा करने के लिए, सेवा प्रदाता ऐसे दावे के प्रतिफल के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करते समय सक्रिय आईईसी धारक होना चाहिए।

3.09 एसईआईएस के तहत अपात्र श्रेणियाँ

अधिसूचित सेवाएं प्रदान किए जाने वाले सेवा क्षेत्र से भिन्न सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा प्रेषण की गणना हकदारी के लिए नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अन्य साधनों से अर्जित विदेशी मुद्रा जैसे इक्विटी या ऋण भागीदारी, दान, ऋण की अदायगी इत्यादि और अन्य साधनों से प्राप्त विदेशी मुद्रा जो सेवा देने से संबंधित नहीं है, पात्र नहीं होगी।

3.10 एसईआईएस के तहत हकदारी

पात्र सेवाओं के सेवा प्रदाता अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर (परिशिष्ट 3घ में दी गई) अधिसूचित दरों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए हकदार होंगे।

3.11 एमईआईएस और एसईआईएस के लिए क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रेषण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा को निर्यात के मूल्य के परिकलन के लिए भी ध्यान में रखा जाएगा।

3.12 स्कीमों (एमईआईएस तथा एसईआईएस) की प्रभावी तिथि

स्कीमों इस नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी अर्थात् इस नीति की अधिसूचना की तिथि को अथवा बाद में किए गए निर्यात/प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमईआईएस/एसईआईएस के तहत प्रतिफल देय होंगे।

3.13 विशेष प्रावधान

- (क) सरकार जनहित में, निर्यात उत्पादों या सेवाओं या बाजारों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जो शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की हकदारी के परिकलन के पात्र नहीं होंगे।
- (ख) सरकार इस अध्याय के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पर प्रतिबंध लगाने/ अधिकतम दर लगाने/दर परिवर्तित करने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है।
- (ग) सरकार परिशिष्ट 3क की वस्तुओं को भी अधिसूचित कर सकती है जिसे आयात के मामले में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- (घ) इस अध्याय के तहत किसी भी समय सरकार किसी भी प्रकार की वस्तु (वस्तुओं) के अधिकतम मूल्य को निर्धारित कर सकती है अथवा प्रति आईईसी धारक कुल लाभ को सीमित कर सकती है।

भारत से निर्यात स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) के लिए सामान्य प्रावधान**3.14 परिवर्ती व्यवस्था**

इस नीति की अधिसूचना की तिथि तक निर्यात किए गए माल के लिए अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, जो कि पूर्ववर्ती विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए अन्यथा पात्र थीं और ऐसे माल के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के अधीन इस नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि को अथवा इसके पश्चात स्क्रिप लागू/जारी किया गया है, उस समय विद्यमान हकदारी, हस्तान्तरणीयता, स्क्रिप के प्रयोग की नीति और पात्रता, और वस्तुओं के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उस समय लागू अन्य किसी शर्त ऐसी स्क्रिप के लिए लागू होगी।

3.15 सेनवैट/शुल्क वापसी

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद अथवा डेबिट के माध्यम से अदा किए गए सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों या अधिसूचनाओं के अनुसार सेनवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद या डेबिट के माध्यम से अदा किए गए मूल सीमाशुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों अथवा अधिसूचनाओं के अनुसार शुल्क वापसी के रूप में भी समायोजित किया जाएगा।

3.16 पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत आयात

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.34 के प्रावधानों में पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।

3.17 निर्यात निष्पादन का अन्तरण

- (क) एक आईईसी धारक से दूसरे आईईसी धारक को निर्यात निष्पादन के अन्तरण की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार पोतलदान बिल जिसमें आवेदक का नाम हो, की आवेदक के निर्यात निष्पादन/कारोबार में गणना तभी की जाएगी जब विदेश से निर्यात आय की वसूली आवेदक के बैंक खाते में हुई हो और यह ई-बीआरसी/एफआईआरसी से प्रमाणित हो।
- (ख) तथापि, एमईआईएस लाभ का दावा या तो सहायक विनिर्माता (कम्पनी/फर्म जिसने सीधे विदेश से विदेशी मुद्रा अर्जित की है से डिसक्लेमर सहित) द्वारा या कम्पनी/फर्म जिसने विदेश से सीधे विदेशी मुद्रा अर्जित की है, द्वारा किया जा सकता है।

3.18 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों के माध्यम से सीमाशुल्क और शुल्क के भुगतान की सुविधा

(क) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमाशुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है। ऐसा उपयोग/प्रयोग उन वस्तुओं के संबंध में होगा जो इन संबंधित स्कीमों के तहत आयात करने के लिए अनुमत है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद में करना होगा।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.49 के तहत विदेश व्यापार नीति के अधीन संयोजन शुल्क के भुगतान के लिए, विदेश व्यापार नीति के अधीन आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए यदि कोई हो और निर्यात दायित्व में मूल्य में आने वाली कमी के भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का भी उपयोग किया जा सकता है।

3.19 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

(क) जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रचालन में होगी जिससे डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक महीने कम्प्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर और डीजीएफटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रत्येक स्कीम के तहत प्रत्येक आरए के लिए 10% प्रतिशत आवेदनों को चुनेगी जहाँ पहले से प्रत्येक स्कीम के तहत स्क्रिप और स्तर धारक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। आरए उसके बाद इन सभी चुने गए मामलों में आगे विस्तार से जाँच करने के लिए मूल दस्तावेजों को मांग सकता है। यदि ऐसी जांच पर कोई असंगति और/अथवा अतिरिक्त दावा पाया जाता है, तो आवेदक इस असंगति को सुधारने के और/अथवा स्क्रिप जारी करने की तिथि से एक महीने के भीतर सीमाशुल्क विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष में स्क्रिप जारी करने की तिथि से एक मास के भीतर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28क(क) के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की दर के साथ दावों की नकद वापसी करने के दायित्व के अधीन होगा। तथापि स्क्रिप का वास्तविक धारक ऐसे अतिरिक्त दावे की वापसी, आंशिक रूप से प्रयुक्त अथवा पूर्ण रूप से अप्रयुक्त स्क्रिप का अभ्यर्पण करके बिना ब्याज के कर सकता है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी लेंडिंग प्रमाण पत्र, (जहां कहीं नीति के लिए अपेक्षित हो) एएनएफ के साथ संलग्न अनुलग्नक अथवा किसी अन्य दस्तावेज जिसे स्क्रिप जारी करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय डिजिटल रूप से अपलोड किया गया हो अथवा आवेदन के संबंध में या निर्यात से संबंधित कोई अन्य निर्यात दस्तावेज जैसे निर्यात बीजक का मूल प्रमाण मांग सकता है। ऐसे दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत न करने पर आवेदक प्रदान किए गए प्रतिफल को स्क्रिप जारी करने की तिथि से सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28क(क) में निर्धारित ब्याज की दर के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवेदक को आईटीसी एचएस कोड के तहत मद विवरण का गलत उल्लेख करता हुआ पाया जाता है तो एफटी (डीआर) अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। आवेदक इन दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों इत्यादि को स्क्रिपों के जारी करने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों की अवधि या आरएमएस के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई जांच के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, संभाल कर रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.20 स्तर धारक

(क) स्तर-धारक व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्टता हासिल की है और देश के विदेश व्यापार में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। स्तर-धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल भारत के निर्यातों में योगदान दें अपितु नए उद्यमकर्ताओं को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें।

(ख) आयात-निर्यात कोड (आईईसी) संख्या वाले माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक एक स्तर-धारक के रूप में पहचान प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्तर-धारक की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। एक आवेदक को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में दर्शाए अनुसार मौजूदा और गत तीन वित्तीय वर्षों के (रत्न एवम् आभूषण क्षेत्र के लिए वर्तमान और पिछले दो वित्तीय वर्षों के (निष्पादन को स्तर धारक के रूप में मान्यता के लिए विचार किया जाएगा) दौरान निर्यात निष्पादन प्राप्त कर लेने पर स्तर-धारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय के एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(ग) मान्य निर्यात के लिए, भारतीय रुपयों में निर्यातों के एफओआर मूल्य को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को यथा लागू, सीबीईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) स्तर प्रदान करने के लिए, चार वर्षों में कम से कम दो वर्षों के लिए निर्यात निष्पादन आवश्यक है।

3.21 स्तर श्रेणी

स्तर श्रेणी	निर्यात निष्पादन एफओबी/एफओआर मूल्य के लिए (परिवर्तित मूल्य के रूप में) (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)
एक स्टार निर्यात कम्पनी	3
दो स्टार निर्यात कम्पनी	25
तीन स्टार निर्यात कम्पनी	100

स्तर श्रेणी	निर्यात निष्पादन एफओबी/एफओआर मूल्य के लिए (परिवर्तित मूल्य के रूप में) (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)
चार स्टार निर्यात कम्पनी	500
पाँच स्टार निर्यात कम्पनी	2000

3.22 दोहरा तरजीह प्रदान करना

(क) निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आईईसी धारकों द्वारा निर्यात स्तर प्रदान करने के लिए निर्यात निष्पादन की गणना करने के लिए दोहरा तरजीह प्रदान किया जाएगा:-

- (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।
- (ii) आईएसओ/बीआईएस युक्त विनिर्माण इकाइयाँ।
- (iii) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में स्थित इकाइयाँ
- (iv) कृषि-निर्यात क्षेत्र में स्थित इकाइयाँ।

(ख) दोहरी तरजीह केवल एक स्टार निर्यात कम्पनी स्तर श्रेणी प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगी। दोहरी तरजीह के ऐसे लाभ अन्य श्रेणियों नामतः दो स्टार निर्यात कम्पनी, तीन स्टार निर्यात कम्पनी, चार स्टार निर्यात कम्पनी और पाँच स्टार निर्यात कम्पनी को स्तर पहचान प्रदान करने के लिए लागू नहीं होंगे।

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में से एक पोटलदान केवल एक बार दोहरा लाभ प्राप्त कर सकता है।

3.23 स्तर प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें

(क) एक आईईसी धारक का निर्यात निष्पादन अन्य आईईसी धारक को स्थानांतरित करना अनुमत नहीं किया जाएगा। इसलिए, दावा-परित्याग पर आधारित निर्यात निष्पादन की गणना अनुमत नहीं की जाएगी।

(ख) पुनः निर्यात के आधार पर किए गए निर्यातों की गणना पहचान के लिए नहीं की जाएगी।

(ग) स्कोमैट मर्जों सहित प्राधिकार-पत्र के तहत मर्जों का निर्यात, निर्यात निष्पादन की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

3.24 स्तर-धारकों के विशेषाधिकार

एक स्तर-धारक निम्नानुसार विशेषाधिकारों का पात्र होगा:-

(क) आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी को स्व-घोषणा के आधार पर प्रदान किया जा सकता है;

(ख) मानदण्ड समिति द्वारा निविष्टि उत्पादन मानदण्डों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के अंदर निर्धारित किया जा सकता है; निविष्टि उत्पादन मानदंड के संबंध में विशेष स्कीम विनिर्दिष्ट स्तर धारक के लिए डीजीएफटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(ग) विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि इन्हें विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रिया-पुस्तक में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(घ) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों पर आवश्यक विचार-विमर्श से छूट हालांकि प्रेषण/प्राप्तियाँ बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी;

(ङ.) दो स्टार और इससे ऊपर की निर्यात कंपनियों को राजस्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्यात गोदामों की स्थापना करने हेतु अनुमत किया जाएगा।

(च) तीन स्टार और इससे ऊपर की निर्यात कंपनियाँ सीबीईसी (वेबसाइट: www.cbec.gov.in) के दिशानिर्देशों के अनुरूप मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी।

(छ) स्तर-धारक तरजीही व्यवहार और संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी खेपों की सुपुर्दगी में प्राथमिकता के हकदार होंगे।

(ज) विनिर्माता जो कि स्तर-धारक (तीन सितारा/चार सितारा/पाँच सितारा) भी हैं अपने विनिर्मित माल (अपने आईईएम/आईएल/एलओआई के अनुसार) को विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहयोग सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत तरजीही प्रबंध के लिए पात्र होने के उद्देश्य से भारत से प्रवृत्त करने के रूप में स्व-प्रमाणित करने में सक्षम होगा। तत्पश्चात स्कीम को शौ स्तर धारकों के लिए लागू किया जा सकता है।

(झ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.108 (घ) के अनुसार विनिर्माता निर्यातक जो कि स्तर-धारक भी हैं यह स्व-प्रमाणित करने के लिए पात्र होंगे कि उनका माल भारत में तैयार होता है।

(ञ) निर्यात प्रोत्साहन के लिए स्तर धारक निःशुल्क लागत पर स्वतंत्र रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात (रत्न और आभूषण, सोने की वस्तुएं और बहुमूल्य धातु को छोड़कर) करने के पात्र होंगे बशर्ते एक करोड़ रुपए या पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2% जो भी कम हो, की वार्षिक सीमा होगी। फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा दवा उत्पादों के निर्यात के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति की 2% की वार्षिक सीमा होगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ पीएचओ, के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों, टीके और जीवन रक्षक दवा की आपूर्तियों के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 8% तक की वार्षिक सीमा होगी। ऐसी निःशुल्क आपूर्तियां शुल्क वापसी या किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन अन्य निर्यात प्रोत्साहन की पात्र नहीं होंगी।

अध्याय - 4

शुल्क विमुक्ति/छूट स्कीम

4.00 उद्देश्य

इस अध्याय के तहत स्कीमें निविष्टियों की पुनःपूर्ति अथवा शुल्क छूट सहित निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात को सक्षम बनाती हैं।

4.01 स्कीम

(क) शुल्क छूट स्कीम

शुल्क छूट स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) (जिसमें वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र सम्मिलित है)
- शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए)

(ख) शुल्क छूट स्कीम।

राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित शुल्क वापसी स्कीम (डीबीके)

4.02 नीति और प्रक्रिया की अनुप्रयोज्यता

इस अध्याय के तहत प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से प्रभावी नीति और प्रक्रिया के अनुसरण में जारी किया जाएगा।

4.03 अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र उन निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति हेतु जारी किया जाता है, जो कि निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से सम्मिलित हैं (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए)। इसके अतिरिक्त ईंधन, तेल, उत्प्रेरकों जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग/प्रयुक्त किए जाते हैं, भी अनुमत होंगे।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्नलिखित आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए जारी किया जाता है:

(i) अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार (प्रक्रिया पुस्तक में उपलब्ध);

अथवा

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर

अथवा

(iii) मानदंड समिति द्वारा मानक का आवेदक विशिष्ट पूर्व निर्धारण।

अथवा

(iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.07क के अनुसार स्व-अनुसमर्थन स्कीम के आधार पर।

4.04 मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

आईटीसी(एचएस) के अध्याय-9 के तहत शामिल मसालों का शुल्क मुक्त आयात केवल तेल अथवा ओलियोरेजिन्स की पौण/घौण/घिसना/अनुर्वरता/उत्पादन जैसे कार्यकलापों के लिए अनुमत होगा। मात्र सफाई, श्रेणीकरण, पुनर्पैकिंग आदि के लिए प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा।

4.04क परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम।

निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए इस योजना हेतु जारी की गई सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसार, परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत फैब्रिक के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी, जो निर्यात और आयात के, निम्नलिखित नियम और शर्तों के अधीन होगी:

- (i) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) या मानदंडों के पूर्व निर्धारण के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।
- (ii) निविष्टि के रूप में केवल अस्तर सहित संबद्ध फैब्रिकों के आयात हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। इस प्राधिकार पत्र के तहत किसी अन्य निविष्टि, पैकिंग सामग्री, ईंधन, तेल और उत्प्रेरक के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) निर्यातक गैर-फैब्रिक निविष्टियों के लिए इस स्कीम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित शुल्क वापसी की समग्र औद्योगिक दर के लिए पात्र होंगे। एफटीपी के पैरा 4.08 के मूल्य वर्धन मानदंड के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऐसी किसी अन्य निविष्टि का मूल्य जिस पर शुल्क वापसी के लाभ का दावा किया जाता है या दावा किए जाने का आशय है, किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 22% के बराबर होगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.09 के अनुसार होगा।
- (iv) जहां निर्यातक क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकरण (ब्रांड दर) द्वारा निर्धारित और नियत शुल्क वापसी का दावा करना चाहता है, तो वह प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में की जाने वाली घोषणाओं के संबंध में एफटीपी के पैरा 4.15 का पालन करेगा और ब्रांड दर हेतु दावा के तहत निर्यात करेगा। ऐसे मामलों में मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.08 के अनुसार होगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.09 के अनुसार होगा।
- (v) प्राधिकार पत्र और आयातित फैब्रिक वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा। निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद भी यह हस्तांतरणीय नहीं होगा। हालांकि आयात किया गया फैब्रिक पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचना देकर जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियत कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से क्षेत्र आधारित छूट के लिए पात्र क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों को छोड़कर)। प्राधिकार पत्र के अमान्यकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vi) आयात किया जाने वाला फैब्रिक आयात पूर्व शर्तों के अधीन होगा और इसे वास्तविक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाएगा (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए)। केवल वास्तविक निर्यात ही निर्यात दायित्व को पूरा करेगा।
- (vii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.02, 4.05 (क), 4.13 (i), 4.13 (ii), 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.21 (i), 4.21 (ii), 4.21 (iii), 4.21 (v), 4.22(i), और 4.24 के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत न हों।

4.05 पात्र आवेदक/निर्यात/आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माणकर्ता निर्यातकों या व्यापारी निर्यातक जो सहायक विनिर्माताओं से संबद्ध है, को जारी किया जा सकता है।

(ख) गैर उल्लंघनीय (एनआई) प्रक्रिया निर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र (प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.18 में यथानिर्दिष्ट) केवल विनिर्माणकर्ता निर्यातकों के लिए जारी होगा।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्न के लिए जारी किया जाएगा:

- (i) वास्तविक निर्यात (एसईजेड को किए निर्यात सहित);
- (ii) अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ; और/अथवा
- (iii) इस विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.02(ख), (ग), (ड), (च) और (छ) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए माल की आपूर्ति।
- (iv) ऐसे विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर 'स्टोर्स' की आपूर्ति इस शर्त के अधीन होगी कि आपूर्ति की गई मर्दों के संबंध में विशिष्ट मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड हैं।

4.06 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

- (i) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र केवल मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) में अधिसूचित मदों के लिए जारी होगा, और यह विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.03(ख)(ii) के तहत तदर्थ मानदण्डों के मामलों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- (ii) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र सिओन के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर निविष्टि की कोई भी मद परिशिष्ट 4ज में आती है।

4.07 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त

- (i) निर्यातक जिनका विगत में निर्यात निष्पादन है (न्यूनतम पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में), वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के पात्र होंगे।
- (ii) आयातों को सीआईएफ मूल्य के अनुसरण में वास्तविक निर्यात के एफओबी मूल्य के 300% और/अथवा विगत वित्तीय वर्ष में मान्य निर्यात के लिए अथवा एक करोड़ रु० जो भी अधिक हो, हकदारी होगी।

4.07क स्व-अनुसमर्थन स्कीम

- (i) जहां किसी निर्यात उत्पाद के लिए कोई सिओन/मान्य तदर्थ मानदंड नहीं है और जहां सिओन को अधिसूचित किया गया है किन्तु निर्यातक विनिर्माण प्रक्रिया में अतिरिक्त निविष्टि का उपयोग करना चाहता है तो पात्र निर्यातक स्वघोषणा और स्व-अनुसमर्थन के आधार पर इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है तथा ऐसे मामलों को मानदंडों के अनुसमर्थन हेतु मानदंड समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस स्कीम के तहत निर्धारित प्रपत्र में सनदी अभियंता के प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन किया जा सकता है।
- (ii) इस स्कीम के तहत सनदी अभियंता जिसे विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और सम्बद्ध अधिनियमों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में दंडित नहीं किया गया है, का प्रमाणपत्र ही प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) इस स्कीम को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित की जाएगी।
- (iv) निर्यातक (विनिर्माता या व्यापारी) जिसके पास सीबीईसी के साथ सामान्य प्रत्यायन कार्यक्रम के अंतर्गत आईओ प्रमाण पत्र है, इस स्कीम को चुनने के लिए पात्र है।
- (v) यह स्कीम निम्नलिखित निर्यात उत्पादों के लिए उपलब्ध नहीं होगी:
- क) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-1 से 24, और अध्याय-71 के तहत शामिल सभी मदें;
- ख) जैव प्रौद्योगिकी मदें और संबंधित उत्पाद; तथा
- ग) स्कोमेट मद।
- (vi) यह स्कीम निम्नलिखित निविष्टियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी:
- क) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-15 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और अध्याय-12 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन;
- ख) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज;
- ग) पशु की सींग, खुर और अन्य कोई अंग;
- घ) वन्यजीव उत्पाद, अंग और उनके अपशिष्ट;
- ड.) शहद;
- च) 30 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क के साथ सभी मदें;
- छ) आईटीसी (एचएस) कोड के अध्याय-7 और 8 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के फल/बादाम/सब्जियां।
- ज) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के शीर्षक 2515, 2516, 3301, 3302, 3303, 6801 और 6802 के अंतर्गत आने वाली मदें
- झ) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाली मदें
- ञ) एसीटिक एनहाईड्राइड, एफेड्राइन और स्यूडो एफेड्राइन
- ट) विटामिन

- ठ) जैव प्रौद्योगिकी मर्दे और संबंधित उत्पाद
- ड) कीटनाशक, चूहा नाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, एन्टी स्प्राउटिंग उत्पाद और पौधा वृद्धि विनियामक, डिस्इन्फेक्टेंट और सभी आकार, किस्म और ग्रेडों के इसी तरह के उत्पाद
- ढ) सभी किस्म का अपशिष्ट/कचरा और
- ण) पुरानी वस्तुएं
- (vii) आयातित निविष्टि पूर्व-आयात शर्त के अधीन होंगे तथा इन्हें निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से (अपशिष्ट हेतु सामान्य अनुमति देने पर) शामिल किया जाएगा। अवैधिकरण/एआरओ के अंतर्गत स्थानीय अधिप्राप्ति किए जाने के मामले में निविष्टियों की निर्यात मद के विनिर्माण से पूर्व अधिप्राप्ति की जाएगी तथा निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल किया जाएगा।
- (viii) जब भी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न उपोत्पादों और पुनः प्राप्ति योग्य अपशिष्ट का मूल्य सीआईएफ मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो तो मुख्य निविष्टि की तदनुसूची मात्रा को पात्रता से इस हद तक कम किया जाएगा कि इसकी अस्वीकृत मात्रा का मूल्य विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न उपोत्पादों और पुनः प्राप्ति योग्य अपशिष्ट के मूल्य के बराबर हो।
- (ix) महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति विनिर्माता की लेखा परीक्षा कर सकता है। लेखा परीक्षा की आवृत्ति और पद्धति का निर्धारण विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में किया जाएगा। लेखा परीक्षा समय पर पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित खाताबही/अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विनिर्माता को आवश्यक सुविधा, जानकारी और सहायता प्रदान करनी होगी। उत्पादन और उपभोग संबंधी दस्तावेजों/ऑकड़ों की अनुपलब्धता को मिथ्या घोषणा और छलपूर्ण कार्यकलापों में शामिल होना माना जाएगा तथा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के तहत दण्डित किया जाएगा।
- (x) महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति छानबीन/पूछताछ/जाँच-पड़ताल के किसी भी चरण पर मामले के स्वरूप और जटिलता तथा सरकार के राजस्व को देखते हुए यदि उसे यह लगता है कि मानदण्डों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया है अथवा अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो, विशेष लेखा परीक्षा तब भी की जा सकती है, चाहें विनिर्माता की लेखापरीक्षा पहले भी की जा चुकी हो।
- (xi) यदि लेखा परीक्षा से मिथ्या घोषणा और अथवा ऐसी निविष्टियों के दावे की घटना का पता लगता है जिनका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया गया है अथवा उपयोग की गई निविष्टियों की माँग की तुलना में अतिरिक्त मात्रा का पता लगने पर यथा संशोधित विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 और/अथवा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक, विनिर्माता और चार्टर्ड इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- (xii) उन मामलों में जहाँ सनदी अभियन्ता ने पूर्ण विचार-विमर्श नहीं किया है या जानबूझकर गलत घोषणा करते हुए उसका पक्षकार बन गया है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले संस्थान के उपनियमों के तहत यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, 'इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)' को भी भेजे जाएंगे।
- (xiii) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लिए लागू सभी प्रावधान इस स्कीम के लिए भी लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के लिए असंगत न हों।

4.08 मूल्यवर्धन

इस अध्याय के प्रयोजनार्थ मूल्यवर्धन (रत्न और आभूषण क्षेत्र के अलावा जिसके लिए मूल्यवर्धन विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.38 में निर्धारित किया गया है) निम्नवत होगा:

मूल्य वर्धन = ए-बी X100, जहाँ पर

बी

ए = किए गए निर्यात का एफओबी मूल्य/प्राप्त की गई आपूर्ति का एफओआर मूल्य

बी = प्राधिकार-पत्र द्वारा शामिल निविष्टियों का सीआईएफ मूल्य तथा साथ में प्रयुक्त की गई अन्य कोई निविष्टियाँ जिस पर डीबीके लाभ का दावा किया गया है अथवा दावा किया जाना है।

4.09 न्यूनतम मूल्यवर्धन

(i) अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत प्राप्त किए जाने हेतु न्यूनतम मूल्य वर्धन 15 % है।

(ii) निर्यात उत्पाद जहाँ पर मूल्यवर्धन 15% से कम हो सकता है, को परिशिष्ट 4घ में दिया गया है।

- (iii) हटा दिया गया है।
- (iv) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ सं0 4.61 में दिया गया है।
- (v) चाय के आयात के मामले में, न्यूनतम मूल्यवर्धन 50% होगा।

4.10 अनिवार्य पुर्जों का आयात

अनिवार्य पुर्जों का आयात जिन्हें परिणामी उत्पाद सहित निर्यात/ आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, को प्राधिकार-पत्र के सीआईएफ मूल्य के 10% की सीमा तक शुल्क मुक्त अनुमत किया जाएगा।

4.11 स्व-घोषणा आधार पर आयात की अपात्र श्रेणियाँ

(क) निम्नलिखित उत्पादों का आयात स्व-घोषणा आधार पर अनुमत नहीं होगा:-

- (i) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-15 के तहत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और अध्याय-12 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन।
- (ii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज।
- (iii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-9 और 12 के तहत वर्गीकृत सभी 30% से अधिक मूल सीमा-शुल्क सहित हल्की काली मिर्च (हल्की बैरी) के अलावा सभी मसाले
- (iv) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय-8 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के फल/सब्जियाँ जिनके ऊपर 30% से अधिक शुल्क है।
- (v) सींग, खुर और पशु का अन्य कोई अंग
- (vi) शहद
- (vii) अपरिष्कृत संगमरमर, ब्लॉक्स/स्लेब्स और
- (viii) अपरिष्कृत ग्रेनाइट
- (ix) भेषज उद्योग में प्रयोग किए जाने के अलावा विटामिन।

(ख) विटामिन सहित, परफ्यूम, परफ्यूमरी यौगिकों और विविध संभरण अंशों के निर्यात के लिए, प्रक्रिया-पुस्तक, के पैराग्राफ 4.07 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदकों को मानदण्ड समिति के पास प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.06 के तहत आवेदन करना होगा।

(ग) जहाँ पर प्रौद्योगिकी मदों और संबंधित उत्पादों का निर्यात और/अथवा आयात शामिल है, प्राधिकार-पत्र क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के तहत प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केवल एक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सौंपने पर जारी किया जाएगा।

4.12 निविष्टियों की गणना

- (i) जहाँ पर सिओन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैकल्पिक निविष्टि को अनुमत करता है जब तक कि मात्रा के साथ विशिष्ट निविष्टि को (जिसे निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कर लिया गया है) पोतलदान बिल में दर्शाया/शामिल नहीं कर लिया जाता और ऐसे पृष्ठांकन में जहाँ निविष्टियाँ, विनिर्दिष्ट मात्रा के भीतर और संबद्ध प्रविष्टि बिल के विवरण से मेल नहीं खाती हैं, संबंधित प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, प्राधिकार-पत्र में प्रयुक्त (अथवा प्रयोग की जाने वाली) निविष्टि का नाम/विवरण पोतलदान बिल में पृष्ठांकित नाम/विवरण से पूर्णतया मिलना चाहिए।
- (ii) इसके अतिरिक्त, यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के सामने कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है, तो आयात हेतु अनुमेय ऐसी निविष्टियों की मात्रा निविष्टियों के ऐसे समूह के सामने समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होंगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप में प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों का अनुपात मात्रा के साथ पोतलदान बिलों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

- (iii) निर्यात दायित्व के निर्वहन (ईओडीसी) के समय अथवा विप्रेषण के समय क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल उन निविष्टियों को अनुमति देगा जो पोतलदान बिल में विशिष्ट रूप से दर्शाई गई हैं।
- (iv) उपर्युक्त प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) को की जाने वाली आपूर्तियों और मान्य निर्यात के तहत की गई आपूर्तियों के लिए भी लागू होगा। उम्मीद किए गए ब्यौरे को संगत निर्यात बिल, एआरई-3, केन्द्रीय उत्पाद प्रमाणित बीजक/आयात दस्तावेज/जीएसटी नियमों के अंतर्गत विहित निर्यात हेतु कर संबंधी बीजक में दर्शाना होगा।

4.13 कतिपय मामलों में आयात पूर्व शर्त

- (i) डीजीएफटी इस अध्याय के तहत अधिसूचना द्वारा निविष्टि हेतु आयात-पूर्व शर्तें अधिरोपित कर सकता है।
- (ii) आयात-पूर्व शर्त के अधीन आयात मर्दों को परिशिष्ट-4अ में सूचीबद्ध किया गया है अथवा ये मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) के अनुसार होंगी।
- (iii) अपंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात हेतु आयात-पूर्व शर्त अधिरोपित की जाएगी।

4.14 छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क जहाँ भी लागू हो, के भुगतान से छूट प्राप्त है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ग), (घ) और (छ) के तहत शामिल आपूर्तियों के तहत आयात लागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात को भी राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यथा प्रदत्त सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले क्रमशः संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त है, और ऐसे आयात पूर्व-आयात शर्त के अधीन होंगे। वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत आयात को समेकित कर और क्षतिपूर्ति उप-कर से केवल 31.03.2018 तक छूट प्राप्त है।

4.15 शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निश्चित और निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वापसी निर्यात उत्पाद में उपयोग की गई शुल्क प्रदत्त आयातित अथवा स्वदेशी निविष्टियों (जो मानदण्डों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं) के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन हेतु, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में शुल्क प्रदत्त निविष्टियों का ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना होगा। आवेदन में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रिम प्राधिकार-पत्र की शर्त में ऐसी प्रदत्त निविष्टि शुल्कों के ब्यौरे को स्पष्ट रूप से पृष्ठंकित भी करना होगा।

4.16 अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित सामग्री 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त के अधीन होगी। यह निर्यात दायित्व पूरा किए जाने के पश्चात भी हस्तांतरणीय नहीं होगी। तथापि प्राधिकार पत्र धारक के पास निर्यात दायित्व के पूरा हो जाने पर शुल्क मुक्त निविष्टि से विनिर्मित उत्पाद का निपटान करने का विकल्प होगा।

(ii) निर्यातित दायित्व के पूरा होने के पश्चात् भी यदि निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवैट/इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, तो इस अग्रिम प्राधिकार पत्र से आयातित माल का उपयोग या तो समान कारखाने के भीतर अथवा बाहर (सहायक के विनिर्माता द्वारा) शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जाएगा। इसके लिए, प्राधिकार पत्र धारक निर्यातक के विकल्प पर निर्यात दायित्व निपटान प्रमाणपत्र हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते समय या तो संबंधित क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(iii) विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट/रद्दी का निपटान जैसा कि अनुमत है, निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने के कहीं पहले लागू शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है।

4.17 आयात के लिए वैधता अवधि और इसका विस्तार

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात के लिए वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार होगी।

4.18 उन मर्दों के आयात/निर्यात किए जाने की पात्रता जो निषिद्ध/प्रतिबंधित/एसटीई मर्द हैं।

(i) किसी मर्द के निर्यात अथवा आयात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के तहत उस स्थिति में नहीं दी जाएगी यदि वह मर्द क्रमशः निर्यात अथवा आयात के लिए निषिद्ध हो। किसी निषिद्ध मर्द के निर्यात की अनुमति

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत दी जा सकती है बशर्तें इसे पृथक रूप से इसमें दी गई शर्तों के अधीन इस प्रकार अधिसूचित किया गया हो।

(ii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मर्दों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए प्रमाणपत्र के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि, ये मर्दें ए.आर.ओ. अथवा अवैधीकरण पत्र के मद्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक को समुद्री मार्ग के माध्यम से बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों को भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार उद्यमों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक द्वारा आयात के लिए “अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)” जारी करने की अनुमति है। प्राधिकार पत्र धारक को उन “अनापत्ति प्रमाणपत्र” के मद्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य व्यापार उद्यम को प्रस्तुत करनी होगी और राज्य व्यापार उद्यम, ऐसे आयातों के अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे और इसकी एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय को भेजेंगे।

(iii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा निर्यात के लिए आरक्षित मर्दें संबंधित राज्य व्यापार उद्यम से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत निर्यात की जा सकती हैं।

(iv) प्रतिबंधित मर्दों का आयात अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत अनुमत होगा।

(v) तथापि, प्रतिबंधित/स्कोमैट मर्दों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की सभी शर्तों अथवा अपेक्षाओं जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के तहत होगा।

4.19 विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति

अग्रिम प्राधिकार पत्र वहां भी उपलब्ध होगा जहां विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ या सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन के परिकलन हेतु निःशुल्क निविष्टि के अनुमानित मूल्य को आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में जोड़ा जाएगा। तथापि, निर्यात लाभ की प्राप्ति ऐसी निविष्टि के अनुमानित मूल्य को निकाल देने के बाद की धनराशि के समतुल्य होगी।

4.20 निविष्टियों की घरेलू प्राप्ति

- (i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र धारक आयात के बदले स्वदेशी आपूर्तिकर्ता/राज्य व्यापार उद्यम/ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी से सीधे निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्राप्ति अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र के मद्दे की जा सकती है।
- (ii) जब घरेलू आपूर्तिकर्ता दूसरे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को परिणामी उत्पाद की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के माध्यम से निविष्टि हेतु शुल्क मुक्त सामग्री प्राप्त करना चाहता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी अमान्यकरण पत्र जारी करेगा।
- (iii) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम निर्गम आदेश जारी करेगा जो विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू आपूर्तिकर्ता को मान्य निर्यात प्रणाली के द्वारा शुल्क वापस लेने में सक्षम बनाता है।
- (iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र के साथ ही या उसके बाद अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र जारी कर सकता है।
- (v) डीटीए के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र प्राप्त किए बिना एसईजेड यूनिटों से निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
- (vi) हटा दिया गया है।
- (vii) अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र की वैधता प्राधिकार पत्र की वैधता की सहमियादी (को-टर्मिनस) होगी।

4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा

- (i) यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो निर्यात लाभ मुक्त रूप से परिवर्तनशील मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। निर्यात लाभ प्राप्त करने या नहीं करने से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2.53 और 2.54 में दिए गए हैं।
- (ii) हटा दिया गया है।
- (iii) एसईजेड यूनिटों को किए गए निर्यात को निर्यात दायित्व के भुगतान हेतु ध्यान में रखा जाएगा बशर्तें कि एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से भुगतान की प्राप्ति हुई हो।

- (iv) एसईजेड विकासकर्ताओं/सह-विकासकर्ताओं को किए गए निर्यात को भारतीय रुपए में भुगतान होने के बावजूद निर्यात दायित्व के भुगतान हेतु भी ध्यान में रखा जा सकता है।
- (v) प्राधिकार पत्र धारक के लिए एसईजेड नियमावली, 2006 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार एसईजेड यूनिट/विकासकर्ता/ सह-विकासकर्ता को किए गए निर्यात के लिए निर्यात बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.22 निर्यात दायित्व अवधि और इसका विस्तार

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि और इसका विस्तार प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित अवधि होगी।

4.23 हटा दिया गया है।

4.24 शुल्क मुक्त/छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात माल का पुनः आयात

अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात माल को उसी रूप में अथवा काफी हद तक उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते राजस्व विभाग द्वारा ऐसा उल्लेख किया गया हो। प्राधिकार पत्र धारक ऐसे पुनः आयात के बारे में पुनः आयात की तारीख से एक मास के अन्दर उस क्षेत्रीय प्राधिकरण को भी सूचित करेगा जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया था।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम (डीएफआईए)

4.25 डीएफआईए स्कीम

(क) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निविष्टि, के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन में खपत/उपयोग किए जाने वाले तेल और उत्प्रेरक को भी आयात की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 और 4.24 के प्रावधान डीएफआईए पर भी लागू होंगे।

(ग) डीएफआईए स्कीम खांड के आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

4.26 छूट दिए जाने वाले शुल्क

(i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र में केवल मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

(ii) हटा दिया गया है।

(iii) शुल्क वापसी सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और स्थिर की गई दर के अनुसार शुल्क प्रदत्त की गई निविष्टियों के लिए उपलब्ध होगी, निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त वे निविष्टियाँ चाहे आयातित हों अथवा स्वदेशी। तथापि, सिओन में अविनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए यदि शुल्क-वापसी का दावा किया गया है तो आवेदक को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन-पत्र में शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए और आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरणों के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के शर्त पत्र में, शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए।

4.27 पात्रता

- (i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निर्यात के पश्चात ऐसे उत्पादों के लिए जारी किया जाएगा जिनके लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को अधिसूचित किया गया है।
- (ii) व्यापारी निर्यातक द्वारा निर्यात प्रलेख अर्थात् पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित निर्यात हेतु कर बीजक पर निर्यात उत्पाद के सहायक उत्पादक का नाम और पते का उल्लेख करना अपेक्षित होगा।
- (iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iv) ऐसी निविष्टि के लिए कोई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो आयात-पूर्व शर्त के अधीन हो अथवा जहां सिओन 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त निर्धारित करता हो तथा/अथवा परिशिष्ट-4अ ऐसी निविष्टि के लिए आयात-पूर्व शर्त निर्धारित करता हो।

4.28 न्यूनतम मूल्य संवर्धन

न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन की प्राप्ति किया जाना अपेक्षित होगा।

4.29 डीएफआईए की वैधता एवं अंतरण

- (i) डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात शुरू करने से पूर्व आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- (ii) निर्यात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग और फाइल संख्या सृजित किए जाने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा करना होगा।
- (iii) निर्यात आपूर्ति करते समय आवेदक निर्यात प्रलेखों अर्थात् पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति के लिए कर बीजक पर फाइल सं. इंगित करेगा।
- (iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार जहां पर सिसोन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैकल्पिक निविष्टि के उपयोग को अनुमत करता है, वहां विशिष्ट निविष्टि को उसकी मात्रा (जिसे निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया गया है) के साथ संबंधित पोतलदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर-बीजक में दर्शाया/पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। ऐसी जेनेरिक निविष्टि/वैकल्पिक निविष्टि के मददे समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में इन निविष्टियों की वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई मात्रा के अनुपात में प्राधिकार-पत्र में आयात के लिए ही इन निविष्टियों को अनुमत किया जा सकता है।
- (v) इसके अतिरिक्त यदि किसी सिसोन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के मददे कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है तो आयात हेतु अनुमय ऐसी निविष्टियों की मात्रा ऐसी निविष्टियों के समूह के मददे समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई और पोतलदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर-बीजक में घोषित इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई नई निविष्टियों का अनुपात पोत लदान बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर-बीजक में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक सिसोन और प्रत्येक पत्तन हेतु अलग डीएफआईए जारी किया जाएगा।
- (vii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.37 में दिए गए उल्लेख के अनुसार डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात एक ही पत्तन से किया जाएगा।
- (viii) क्षेत्रीय प्राधिकरण हस्तांतरणीय डीएफआईए को इसे जारी किए जाने की तिथि से 12 मास की वैधता के साथ जारी करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा आगे कोई वैधता प्रदान नहीं की जाएगी।

4.30 शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत संवेदनशील मदें

(क) निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में निर्यातक द्वारा पोतलदान बिल में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशिष्टता संबंधी घोषणा प्रदान करना अपेक्षित होगा:

“स्टेनलेस स्टील सहित मिश्रधातु स्टील, कॉपर मिश्रधातु, कृत्रिम रबड़, बियरिंग्स, सॉल्वेंट, परफ्यूम/खाद्य तेल/सुगंध युक्त रसायन, सर्फैक्टेंट, संबंधित वस्त्र, मार्बल, पॉलीप्रोपिलिन से बनी वस्तुएं, कागज और कागज बोर्ड से बनी वस्तुएं, कीटनाशक सीसा इन्गाट, जिंक इन्गाट, सिट्रिक एसिड, संबंधित ग्लास फाइबर रिइन्फार्समेंट (ग्लास फाइबर, चाण्ड/ स्ट्रेंडिड मैट, रॉविंग वोवन सर्फैसिंग मैट), संबंधित सिंथेटिक रेजिन (अन्सेचूरेटिड पालीस्टर रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सि इथाइल सेल्यूलोज), लाइनिंग सामग्री”

(ख) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करते समय क्षेत्रीय प्राधिकरण प्राधिकार पत्र में इन निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशेषीकरण का उल्लेख करेगा।

रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों के लिए स्कीम**4.31 निविष्टि का आयात**

रत्न एवं आभूषण के निर्यातक निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लेवी योग्य एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर) निविष्टियों का आयात/को प्राप्त कर सकते हैं।

4.32 निर्यात की मदें

निम्नलिखित मदें, यदि उनका निर्यात किया जाता है, सुविधाओं के लिए पात्र होंगी:

- (i) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों को छोड़कर) चाहे वे सामान्य अथवा जड़े हुए हों, जिनमें 8 कैरेट या अधिक सोना जिसकी अधिकतम सीमा 22 कैरेट हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण अथवा वस्तुओं सहित स्वर्ण आभूषण;
- (ii) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, चांदी की वस्तुएं, चांदी की स्ट्रिप्स और वस्तुओं सहित चांदी के आभूषण;
- (iii) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक प्लैटिनम हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण और वस्तुओं सहित प्लैटिनम आभूषण।

4.33 योजनाएं

योजनाएं निम्नवत हैं:

- (i) नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/पुनःपूर्ति;
- (ii) रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र;
- (iii) उपभोज्यों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र;
- (iv) कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र।

4.34 नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/पुनःपूर्ति

माउंटिंग्स और फाइनिशिंग्स सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के निर्यातक, नामित एजेंसी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में अग्रिम रूप से अथवा निर्यात के बाद पुनःपूर्ति के रूप में, निर्यात उत्पाद की निविष्टि के रूप में सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

यदि निर्यातक/विनिर्माता निर्यातित उत्पाद संबंधी निम्नलिखित में कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे बहुमूल्य धातु की कोई पुनःपूर्ति प्राप्त नहीं होगी।

- (क) विनिर्माता द्वारा निविष्टियों और सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया गया है।
- (ख) तैयार माल अवस्था संबंधी छूट अधिसूचना सं0.19/2004 सीई (एनटी) दिनांक 06.09.2004 के तहत प्राप्त की गई है।
- (ग) बहुमूल्य धातु अथवा बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में अधिसूचना सं0 21/2004-सीई (एनटी) दिनांक 06.09.2004 के तहत निविष्टि चरण छूट प्राप्त की गई है।
- (घ) विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19(2) के तहत बहुमूल्य धातु अथवा बहुमूल्य धातु की वस्तुएं प्राप्त की गई हैं।
- (ङ.) निर्यातक द्वारा निविष्टियों अथवा सेवाओं पर सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय-5 के तहत निविष्टि कर क्रेडिट प्राप्त किया गया है: अथवा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के तहत आईटीसी की वापसी अथवा आईजीएसटी की वापसी प्राप्त की गई है।
- (ii) निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के क्रमशः पैरा 4.60 और 4.61 में यथा उल्लिखित अपशिष्ट मानदंडों और न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

4.35 रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र

- (i) निर्यातक प्रक्रिया-पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण से रत्नों के लिए परिशिष्ट-4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा।
- (ii) रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात के अधीन जारी किया जा सकता है जिसमें नामित एजेंसी (एफटीपी का पैराग्राफ 4.41) और विदेशी खरीदार (एफटीपी का पैराग्राफ 4.45) द्वारा की गई आपूर्ति के अधीन किया गया आयात शामिल है।

(iii) जड़े हुए सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और तत्संबंधी वस्तुओं के मामले में, रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र का मूल्य स्वीकार्य अपशिष्ट सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम का मूल्य घटाने के बाद निर्यात के शेष पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य पर होगा। पुनःपूर्ति दर और आयात की मद प्रक्रिया-पुस्तक आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 4छ के अनुसार होगी।

4.36 उपभोज्यों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र

(i) विगत वर्ष के निर्यातों के मूल्य के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर कीमती धातुओं (सोने और प्लैटिनम के अलावा) से बने हुए आभूषण के लिए उपभोज्यों, टूल्स और अन्य मदों नामतः टैग्स एवं लेबल्स, कार्ड पर सुरक्षा सेंसर, स्टेपल कयर, पोली बैग (सीमा-शुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित) और विगत वर्ष के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों और सोने और चांदी से बने हुए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए गए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर को छोड़कर) आयात के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात कार्यनिष्पादन दर्शाते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है। तथापि, रोडियम के तैयार किए हुए चांदी के आभूषणों पर ऐसे आभूषणों के लिए एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत की हकदारी होगी। यह प्राधिकार-पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

(ii) उम्मीर दिए गए उपभोज्यों के आयात के लिए आवेदन-पत्र एएनएफ 4ज में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.37 कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र

(क) इनके शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के

तहत लगाए गए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर को छोड़कर) आयात के लिए 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त के साथ आयात-पूर्व आधार पर अग्रिम प्राधिकार-पत्र प्रदान किया जाएगा:

(i) 0.995 तक की शुद्धता का सोना और 8 कैरेट या अधिक के माउंटिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स और फाईंडिंग्स;

(ii) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स जिनमें भार के स्तर में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो ।

(iii) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लैटिनम और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स जिनमें भार के स्तर में 50 प्रतिशत से अधिक प्लैटिनम हो ।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई जायेगी जिसे प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।

(ग) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.38 और प्रक्रिया पुस्तक, के पैरा 4.61 के अनुसार मूल्य संवर्धन होगा।

4.38 मूल्यवर्धन

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 में दिए गए हैं। इसका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:-

ए - बी

वी.ए = ----- X 100 जहाँ

बी

ए= प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का एफओआर मूल्य

बी=निविष्टियों का मूल्य (घरेलू स्रोतों से प्राप्ति सहित), जैसे निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/ चांदी/प्लैटिनम का अंश तथा रत्न आदि जैसी अन्य मदों के मूल्य सहित अनुमत अपशिष्ट। जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी मूल्य में शामिल किया जाएगा ।

4.39 छीजन मानदंड

सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरात के लिए विनिर्माण हानि अथवा छीजन, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.60 के अनुसार ग्राह्य होगी।

4.40 डीएफआईए की अनुपलब्धता

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

4.41 नामित एजेंसियां

- (i) निर्यातक नामित एजेंसी से स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। ईओयू के निर्यातक और एसईजेड की यूनिट क्रमशः विदेश व्यापार नीति के अध्याय-6 के प्रावधानों/एसईजेड नियमावली से अभिशासित होंगे।
- (ii) नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), एसटीसीएल लि0, एमएमटीसी लि0, डायमण्ड इण्डिया लि0 (डीआईएल)।
- (iii) विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के तहत नामित अभिकरणों द्वारा सोने के आयात के संबंध में किसी प्रावधान के बावजूद, नामित अभिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किसी चार सितारा और पांच सितारा हाऊस द्वारा सोने का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है तथा नामित अभिकरण प्रमाण पत्र की बकाया वैधता अवधि के दौरान उन्हें सोने का आयात करने की अनुमति स्वयं विनिर्माण के प्रयोजन हेतु केवल एक निविष्ट के रूप में तथा निर्यात करने के लिए प्राप्त है।
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य एजेंसी को नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत कर सकता है।
- (v) नामित एजेंसी (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और ईओयू और एसईजेड स्कीमों के तहत संचालित रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) द्वारा बहुमूल्य धातु के आयात के लिए प्रक्रिया और उनकी निगरानी प्रणाली, प्रक्रिया पुस्तक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, शोधन हेतु स्वर्ण छीजन का निर्यात तथा मानक स्वर्ण छड़ों का आयात कर सकता है।

4.42 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात

निम्नलिखित एजेंसी का उनके द्वारा प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के प्रयोजन के लिए उनकी प्रयोगशालाओं हेतु हीरे आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसे प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के साथ पुनः निर्यातित किया जाएगा:

- 1 जैमोलोजिकल इन्स्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) मुम्बई, महाराष्ट्र
- 2 भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, गुजरात
- 3 इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डायमंड ग्रेडिंग एण्ड रिसर्च इंडिया, प्राईवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, इंडिया
- 4 एचआरडी डायमंड इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया
- 5 इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्रा0लि0, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई

4.43 कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का प्रमाणन/ ग्रेडिंग और पुनः आयात के लिए निर्यात

0.25 कैरेट और ऊपर के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 में दी गई है।

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ कटे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ ₹ के निर्यात की वार्षिक कुल बिक्री हो) अथवा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत के प्राधिकृत कार्यालय/अभिकरण विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 मास की अवधि के अंदर शून्य शुल्क की पुनः आयात की सुविधा दी गई है। ऐसी शून्य शुल्क की पुनः आयात सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

4.45 विदेशी खरीदारों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर निर्यात

- (i) जहां निर्यात आदेश नामित किए गए अभिकरणों/स्तर धारकों/तीन वर्षों के अनुभव वाले ऐसे निर्यातकों को दिया जाता है जिनकी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक औसत कुल बिक्री 5 करोड़ रुपये की हो, इसमें विदेशी खरीदार प्रभार मुक्त सोने/चांदी/प्लेटिनम/मिश्र धातुओं, विनिर्माण और निर्यात हेतु सोने/चांदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग्स की अग्रिम आपूर्ति कर सकते हैं।
- (ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति अग्रिम रूप से भी की जा सकती है तथा इसमें निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अधीन मरम्मत/पुनः निर्माण तथा निर्यात हेतु फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स/पुर्जों सहित अर्द्ध-तैयार गहने शामिल हो सकते हैं। निर्यात के ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.60 के अनुसार अपव्यय मानदंड लागू होंगे।
- (iii) निर्यात नामित अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके सहायकों अथवा स्तर धारकों/निर्यातकों के माध्यम से किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात निवल आधार पर किया जाएगा।

4.46 निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात

- (i) वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से नामित एजेन्सियाँ और उनके सहयोगी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुमोदन से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।
- (ii) स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने तथा ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात की भी अनुमति है बशर्ते ये प्रक्रिया पुस्तक, में दी गई शर्तों के अधीन हों।

4.47 निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा आयात पार्सल को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने-ले जाने की अनुमति दी जा सकती है

4.48 डाक द्वारा निर्यात

विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा निर्यात भी शामिल है, आभूषण के पार्सल भार के रूप में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

4.49 निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम

तराशे और पॉलिश किए गए हीरों, तराशे और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों, बिना तराशे गए और बिना जड़े गए कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आयात और पुनर्निर्यात के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र/डीटीए में निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं, जो डीटीए इकाइयों द्वारा 5% के न्यूनतम मूल्यवर्द्धन के अधीन होंगे।

4.49(क) विशेष अधिसूचित क्षेत्र

समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की आरबीआई की अधिसूचना सं० 116 द्वारा यथा अधिसूचित कंपनी द्वारा कच्चे हीरे के आयात, नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात सीमाशुल्क विभाग के पर्यवेक्षणाधीन, एसएनजेड के परिचालक द्वारा प्रशासित विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) में खेप अथवा एकमुश्त आधार पर अनुमत होगा। कच्चे हीरे (अनबिके) के आयात/नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात की प्रक्रिया सीबीईसी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

4.50 हीरे और जवाहरात संबंधी डॉलर खाते

- (क) अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए गए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/रहित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्में तथा कम्पनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्नों से जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों के आयात या निर्यात में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 3 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार हो, नामजद हीरा डॉलर खातों (डी डी ए) के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती हैं।
- (ख) ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इसका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा-
 - (i) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों का आयात/खरीद;
 - (ii) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,
 - (iii) विदेशी/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर ऋणों की चुकौती, और

(iv) निर्यातक के रुपये खाते में हस्तांतरण। इस हीरा डॉलर खाता(डी डी ए) स्कीम के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक में दिये गये हैं।

(ग) गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की डीडीए धारक को आपूर्ति करने, भुगतान डालर में लेने तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलने की अनुमति है। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों और रंगीन रत्नों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई आपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व की पूर्ति के रूप में माना जाएगा और/या उसे प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र का हक प्रदान करेगा।

4.51 परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमन के अनुसार परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी। पुनः निर्यात के मामले में, निर्यातक नियमानुसार शुल्क वापसी का हकदार होगा।

4.52 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, के पैरा 4.91 के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषणों का पुनः आयात करने की अनुमति होगी।

4.53 खेप आधार पर निर्यात और आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषणों के निर्यात और आयात की अनुमति होगी।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम

5.0 उद्देश्य

ईपीसीजी स्कीम का उद्देश्य भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत माल के आयात को सुविधाजनक बनाना है।

5.01 ईपीसीजी स्कीम

(क) ईपीसीजी स्कीम में शून्य सीमाशुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन-पश्च के लिए पूंजीगत माल के (परिशिष्ट 5 च में नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर) आयात की अनुमति दी गई है। वास्तविक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के तहत आयातित पूंजीगत माल को उस पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यथा प्रदत्त सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की क्रमशः उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर से केवल 31.03.2018 तक छूट प्राप्त है। वैकल्पिक रूप से प्राधिकार पत्र धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल प्राप्त कर सकते हैं। ईपीसीजी स्कीम के लिए निम्नलिखित पूंजीगत माल शामिल होंगे।

- (i) सीकेडी/एसकेडी की शर्त सहित अध्याय 9 में यथा परिभाषित पूंजीगत माल;
- (ii) कम्प्यूटर प्रणाली और साफ्टवेयर जो आयात किए जा रहे पूंजीगत माल का भाग है;
- (iii) स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाई, जिग्स, फिक्चर्स औजार और

रिफैक्ट्रीज और

(iv) प्रारंभिक प्रभार और बाद के प्रभार के लिए कैटेलिस्ट।

(ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित परियोजना आयात के लिए पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि के बाद 6 वर्षों तक पूरा किए जाने वाले पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्कों, करों और उपकरों के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की शर्तों के अधीन किया जाएगा।

(घ) आयात के लिए प्राधिकार पत्र, प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 18 महीने तक वैध रहेगा। ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) यदि ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातों पर एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर नकद रूप में अदा किया गया है तो, एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न उठाया गया हो।

(च) हटा दिया गया है।

(छ) हटा दिया गया है।

(ज) ईपीसीजी स्कीम के तहत मदों, जो आयात के लिए प्रतिबंधित हैं, का आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) की एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) से अनुमोदन के बाद ही अनुमत होगा।

(झ) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाला माल निर्यात हेतु प्रतिबंधित है तो ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को डीजीएफटी मुख्यालय की एक्जिम सुविधा समिति से निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

5.02 कवरेज

(क) ईपीसीजी स्कीम में सहायक विनिर्माता(ओं) के साथ या उनके बिना विनिर्माता निर्यातक, सहायक विनिर्माता (ओं) और सेवा प्रदाता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक शामिल हैं। तथापि, सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के मामले में सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्ट्री/परिसर में पूंजीगत वस्तुओं के संस्थापन से पहले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) का नाम पृष्ठांकित किया जाएगा। सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) में कोई बदलाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी इस बदलाव के बारे में क्षेत्राधिकार के मौजूदा सीमा-शुल्क प्राधिकारी के साथ-साथ बदले गए सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) और प्राधिकार पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग को सूचित करेगा।

(ख) विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम में वह सेवा प्रदाता भी शामिल है, जो डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात विशिष्ट शहर में स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेशन द्वारा एक सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी) के तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नामित/प्रमाणित है:-

(i) सामान्य सेवा के प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए निर्यात में संबंधित पोत लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के ब्यौरे शामिल होंगे तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ता ब्यौरों के वीथ में सूचित करना होगा।

(ii) ऐसे निर्यात को अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों(सीएसपी/प्रयोक्ता का) से संबंधित विशिष्ट निर्यात दायित्वों को पूरा करने हेतु गिना नहीं जाएगा; तथा

(iii) बचाए गए शुल्क की राशि के बराबर की बैंक गारंटी प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सीएसपी के विकल्प पर, किसी भी प्रयोक्ता द्वारा अथवा सीएसपी द्वारा बैंक गारंटी दी जा सकती है।

5.03 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति होने तक और ईओडीसी प्रदान कि जाने पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

5.04 निर्यात दायित्व(ईओ)

निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा ऐसे माल जो कि उसके द्वारा अथवा उसके सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाता है/ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र प्रदान किया जा चुका है के द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।

(ख) स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.13(क) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर बढ़ाई गयी समयावधि सहित समग्र निर्यात-दायित्व अवधि के भीतर आवेदक द्वारा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उक्त तथा उसी तरह के उत्पादों के किए गए निर्यातों के औसत स्तर से अधिक होगा। यह औसत उक्त और उसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के निर्यात निष्पादन का गणितीय माध्य होगा।

(ग) पूंजीगत माल के स्वदेशी प्रापण के मामले में, विशिष्ट निर्यात दायित्व पैरा 5.01 में निर्धारित निर्यात दायित्व के 25 प्रतिशत से कम होगा।

(घ) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत अग्रिम प्राधिकार- पत्र, डीएफआईए, शुल्क वापसी स्कीम अथवा प्रोत्साहन स्कीम के तहत पोतलदान, ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

(ड.) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे। तथापि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.02 (क), (ख), (ड.), (च) और (ज) में यथा उल्लिखित आपूर्तियां भी विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे।

(च) निर्यात दायित्व डीटीए को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।

(छ) प्राधिकार पत्र धारक द्वारा आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त स्म से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्वहन के लिए माने जाएंगे।

(ज) परिशिष्ट 5घ. में यथा अधिसूचित ऐसी सेवाओं के लिए स्म्यों में प्राप्त की गई अदायगी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए मानी जाएगी।

5.05 हटा दिया गया है।

5.06 कृषि इकाइयों के मामले में एल्यूटी/बॉण्ड/बीजी

विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी, जो भी लागू हो, कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को प्रदत्त ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए दी जा सकती है बशर्ते ईपीसीजी प्राधिकार पत्र में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (ओं) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया हो।

5.07 स्वदेशी स्म से पूंजीगत माल प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं घरेलू विनिर्माता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा और जैसा कि मान्य निर्यात श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी नियमों के तहत प्रदान किया जाए। ऐसी घरेलू प्राप्ति की ईओयू से भी अनुमति दी जाएगी और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.09 (क) में उल्लिखित उक्त ईओयू द्वारा सकारात्मक एनएफई को पूरा करने के उद्देश्य से इन आपूर्तियों को गिना जाएगा।

5.08 निर्यात दायित्व की गणना

सीधे आयात के मामले में, निर्यात दायित्व को वास्तविक स्म से बचाई गई शुल्क राशि के संदर्भ में माना जाएगा। घरेलू प्रापण के मामले में, निर्यात दायित्व को एफओआर मूल्य पर बचाए गए काल्पनिक सीमाशुल्क के संदर्भ में माना जाएगा।

5.09 समय से पहले निर्यात दायित्व पूरा करने हेतु प्रोत्साहन

निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार-पत्र धारक ने अब तक प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक तथा औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा कर लिया हो तो बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र को विमुक्त कर दिया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.21 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर शीघ्र निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाया गया है।

5.10 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए पैरा 5.01 में यथानिर्धारित निर्यात दायित्व का 75% होगा। पैरा 5.04 में यथानिर्धारित औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.29 में दी गई है।

5.11 उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिटों के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व यथालागू पैरा 5.01 में यथा उल्लिखित निर्यात दायित्व का 25% होगा। पैरा 5.04 में यथा उल्लिखित लगाया गया, औसत निर्यात दायित्व यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5.12 पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स)

(क) पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) उन निर्यातकों के लिए उपलब्ध होंगी जो नकद स्म से लागू शुल्कों, करों और उपकरों के पूर्ण नकद भुगतान से पूंजीगत माल आयात करना चाहते हैं और इस योजना का विकल्प चुनते हैं।

(ख) पूँजीगत माल पर अदा किए गए मूल सीमा शुल्क पर, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के रूप में छूट होगी।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत विशिष्ट निर्यात दायित्व लागू विशिष्ट ई ओ का 85% होगा। तथापि औसत निर्यात दायित्व अपरिवर्तित रहेगा।

(घ) शुल्क छूट पूरे किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में होगी।

(ड.) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी स्क्रिप्स के उपयोग के लिए किए गए सभी प्रावधान पश्च निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के लिए भी लागू होंगे।

(च) मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत नहीं हों।

अध्याय - 6

निर्यातानुमुखी यूनिटें (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एसटीपी) और बाँयो टेक्नोलोजी पार्क (बीटीपी)

6.00 भूमिका और उद्देश्य

(क) अपने सारे माल के उत्पादन और सेवाओं (डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यातानुमुख यूनिट (ई.ओ.यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी) योजना, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एसटीपी) योजना या बायो टेक्नोलोजी पार्क (बीटीपी) स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री-मेकिंग, री-कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में, साफ्टवेयर तैयार करने, कृषि जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर, पशु पालन, बायोटेक्नोलोजी, फूलों की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन में लगी हो सकती हैं। इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

(ख) इन स्कीमों का उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ाना, निर्यात उत्पादन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है।

6.01 माल का निर्यात तथा आयात

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है, सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एचएस) में निषिद्ध हैं। तथापि, सोने के आभूषण, आंशिक रूप से तराशे गए आभूषण चाहे सादा हो अथवा जड़ित हो और संबंधित वस्तुओं सहित जिनमें 8 कैरेट और इससे अधिक 22 कैरेट की अधिकतम सीमा तक सोना हो, को ही अनुमति दी जाएगी।

(ख) विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमईटी) का निर्यात आई टी सी (एचएस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा। ईओयू के संबंध में अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा एक निषेध वस्तु के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसे कच्चे माल का आयात किया गया हो तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से ऐसे कच्चा माल की अधिप्राप्ति न की गई हो।

(ग) निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोशर/साहित्य, पम्फलेट, होर्डिंग, कैटलॉग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्षों के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की भी अनुमति होगी।

(घ) (i) निर्यात अभिमुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट, डीटीए अथवा डीटीए में बाण्डेड गोदामों/भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूँजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात और/या खरीद कर सकती है बशर्ते कि ये नीचे पैरा (ii) और (iii) में दी गई शर्तों के अधीन आई टी सी (एचएस) में आयात की निषिद्ध मदें न हो। किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए अपेक्षित कोई अनुमति लागू होगी। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण/लीज पर पूँजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृत कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूँजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा।

(ii) डीटीए में बाण्डेड माल गोदाम से अथवा भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से आयात और/अथवा खरीद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में उस पर प्रभार्य सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की

धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क यदि कोई हो, के भुगतान के बिना होगी। ऐसे आयात और/अथवा खरीद राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) और 3(9) के तहत प्रभार्य एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर के बिना होगी और यह छूट केवल दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध होगी।

- (iii) डीटीए से जीएसटी के तहत शामिल की गई वस्तुओं की अधिप्राप्ति लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने पर होगी। डीटीए से ईओयू को की गई आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध होगी, जो जीएसटी नियमावली और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण के अध्वधीन होगी। ईओयू डीटीए से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के तहत आने वाली उत्पाद शुल्क प्रभार्य वस्तुएं भी लागू उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना खरीद सकते हैं।
- (ड.) निर्यातोन्मुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी। तथापि, क्रोम ओर/क्रोम कंसट्रेट, के संबंध में इन मदों की निर्यात नीति में यथानिर्धारित राज्य व्यापार व्यवस्था निर्यात अभिमुख इकाइयों के लिए लागू होगी।
- (घ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी इकाइयां केन्द्रीय सुविधा बनाने के लिए कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ऊपर पैरा 6.01 (घ) (ii) और पैरा 6.01 (घ) (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों/करों के भुगतान के साथ या भुगतान के बिना डीटीए से आयात/खरीद सकती हैं। सॉफ्टवेयर ईओयू/डीटीयू इकाइयों सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं।
- (छ) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यातोन्मुख यूनिटों के परिसर के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ज) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/ प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिटों को ऋण अथवा सम्पूर्ण खरीद के आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात रिलीज करने की तारीख से 90 दिन के अन्दर करना होगा।
- (झ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें, भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन सेवा यूनिटों के अलावा राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्को रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रूसी संघ को निर्यात कर सकती हैं।
- (ञ) स्पेयर्स/संघटकों की खरीद और निर्यात के 5 प्रतिशत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर उन्हीं करारकर्ता/खरीददार को निर्यात वस्तुओं के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि एन एफ ई और प्रत्यक्ष कर लाभों के लिए इनका आकलन नहीं किया जाएगा।
- (ट) अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभूषण के अलावा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन बोर्ड किन्हीं अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

6.02 पुराना पूंजीगत माल

पुराने पूंजीगत माल का बिना किसी कालावधि सीमा के उपर्युक्त पैरा 6.10 (घ) (ii) के तहत यथा प्रदत्त शुल्क/करों के भुगतान के साथ या बगैर आयात किया जा सकता है।

6.03 पूंजीगत माल के पट्टे

- (क) पार्टियों के बीच में हुए पक्के करार के आधार पर कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से पूंजीगत माल उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों/करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट पूंजीगत आयात करने/ खरीदने के लिए संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

- (ख) एक निर्यातोनमुख यूनिट/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी.टी.पी. /सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित शर्तों के मद्दे पूंजीगत वस्तुओं को बेच सकता है और उसे एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से पट्टे पर वापस ले सकता है:-
- (i) यूनिट को परिसंपत्तियों की बिक्री और पट्टे पर वापसी का लेन-देन करने के लिए सीमाशुल्क क्षेत्राधिकारी उप/सहायक आयुक्त से अनुमति लेनी होगी और बेचे जाने वाली या पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुओं का पूरा विवरण और एनबीएफसी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- (ii) बेचे जाने वाली और पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुएं यूनिट के परिसर से नहीं हटाई जाएंगी।
- (iii) यूनिट की निवल विदेशी मुद्रा सकारात्मक होनी चाहिए जब यह एनबीएफसी के साथ बिक्री एवं पट्टे पर वापसी के लेन देन को शुरू करती है।
- (iv) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 के साथ पठित अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन या व्यतिक्रम जिसके तहत इन वस्तुओं का आयात किया गया है या इन्हें खरीदा गया है, के मामले में इन वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए यूनिट और एन बी एफ सी द्वारा एक संयुक्त वचनबद्धता देनी होगी और इन वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार सीमाशुल्क के पास रहेगा जिनके पास सीमाशुल्क (सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं की संपत्ति को जब्त करना) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (ख) के प्रावधान के तहत यूनिट से सरकार को बकाया देय राशि की वसूली के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर प्रथम अधिकार रहेगा ।

6.04 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। इसके अलावा परिशिष्टों एवं एएनएफ के परिशिष्ट 6 ख के क्षेत्र विशेष के लिए प्रावधानों जहाँ उच्च मूल्य संवर्धन और अन्य शर्तें दी गई हैं, का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचित रूप से गिना जाएगा। जब भी कोई यूनिट परमिट पत्र में शामिल किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध/प्रतिबंध के कारण एनएफई प्राप्त करने में असमर्थ है, तो निवल विदेशी मुद्रा आय की गणना के लिए पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त तरीके से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जब कभी एक इकाई बाजार की प्रतिकूल स्थिति अथवा इकाई के कार्य पर बुरा असर डालने वाली किसी वास्तविक समस्या के कारण निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) को प्राप्त नहीं कर पाती है तो अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा की गणना हेतु पाँच वर्ष की ब्लॉक अवधि को एक वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। एनएफई की गणना की विधि का विस्तृत विवरण प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 6.10 में दिया गया है।

6.05 आवेदन व अनुमोदन/अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता:

- (क) (i) प्रक्रिया पुस्तक में विवरण के अनुसार, इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी/अनुमोदन बोर्ड (बीओए) जो भी मामला हो, के द्वारा ईओयू की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। ईओयू के प्रशासन का विवरण और डीसी की शक्तियाँ प्रक्रिया पुस्तक में दी गई हैं।
- (ii) इकाई ईएचटीपी/एसटीपी योजना के अधीन होने के मामले में, इस अध्याय के संबंधित पैरा के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन/अनुमति, डीसी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी और बीओए के स्थान पर अंतर्मंत्रालयी स्थायी समिति द्वारा जारी की जाएगी।
- (iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर डीजीएफटी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) अधिसूचित किया जाएगा। बीटीपी में इकाई के मामले में, इस अध्याय के संबंधित प्रावधान के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
- (iv) अनुमोदन होने पर ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई को अनुमति पत्र (एलओपी)/आशय पत्र (एलओआई) डीसी/नामित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अनुमति पत्र/एलओआई की वैधता प्रक्रिया पुस्तक में दी जाएगी।
- (ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.1 में प्रावधानों के अनुसरण में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा।
- (ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को सुनिश्चित करने में असफल होने पर अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को पूरा न कर सकने पर वह किसी अन्य कानून/नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके

अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों/नियमों के अधीन दण्ड के भागी होंगे और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा निरस्त हो जाएगा।

6.06 पूँजी निवेश मानदण्ड

जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश हो उन पर ही ई.ओ.यू. के रूप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, यह, मौजूदा यूनिटों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी और हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/जलकृषि/पशुपालन/सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं, ब्रास हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में ईओयू पर लागू नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

6.07 आवेदन एवं अनुमोदन

(क) हटा दिया गया है।

(ख) हटा दिया गया है।

(ग) हटा दिया गया है।

(घ) हटा दिया गया है।

6.08 तैयार उत्पाद/अस्वीकृत माल/अपशिष्ट/स्क्रेप/शेष और उप-उत्पाद की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के समस्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। तथापि विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को अपवाद के रूप में अनुमत किया जाता है:-

(क) (i) रत्न और आभूषण यूनिटों के अतिरिक्त यूनिटें एलओपी (जिनमें ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग के दौरान होने वाले उप-उत्पाद खारिज अस्वीकृत, अपशिष्ट और स्क्रेप उत्पाद शामिल हैं।) में निर्दिष्ट अपने द्वारा विनिर्मित माल बेच सकती हैं जोकि उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, और/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर, साथ ही ऐसी तैयार वस्तुओं (उपोत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल के उत्पाद, विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्क्रेप सहित) के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर प्राप्त छूट, यदि कोई हो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल सहित सकारात्मक एनएफई की पूर्ति की शर्त पूरी करने पर, डीटीए में एफटीपी के अधीन स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हो। काली मिर्च या काली मिर्च उत्पाद, मार्बल और अन्य वस्तुएं जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, की डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

(ii) पैकेजिंग/लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/पल्वेराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/ मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमतः कार्य से जुड़ी यूनिटों के मामले में ऐसी डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii)(क) एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ईओयू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से किया गया हो।

(iii)(ख) डीटीए को बिक्री फर्मास्युटिकल उत्पादों (बल्क औषधि सहित) के पंजीकरण आवश्यकता के भी अधीन होगी।

(iv) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए में लाई गई वस्तुओं के विनिर्माण या संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा।

(v) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों द्वारा डीटीए सेल उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, और/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान और साथ ही ऐसी तैयार वस्तुओं (उपोत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल, के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्क्रेप सहित) के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर प्राप्त छूट, यदि कोई हो, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के अधीन होगी। सीमाशुल्क की यह रिवर्सल, मानदंड समिति (जहां सियोन मानदंड तय न हों) द्वारा प्रचलित सियोन मानदण्ड या तय मानदण्ड के अनुसार होगा।

(vi) ऐसी डीटीए बिक्री, डीटीए में स्वीकृत किए गए माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग होने वाले माल पर, एफटीपी के अनुसार ईओयू/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की एफटीपी के अध्याय-7 के अधीन की वापसी की शर्त के अधीन होगी।

(ख) साफ्टवेयर यूनिटों सहित सेवाओं के लिए, डीटीए में किसी भी स्तर में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत और/अथवा अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटों, डीटीए में पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती हैं बशर्ते कि सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया हो। यूनिट को, ऐसे आभूषणों में प्रयोग किए गए इनपुट पर देय के रूप में, यदि कोई सीमाशुल्क छूट ली गई हो, तो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रयोज्य सीमाशुल्क के रिवर्सल सहित लागू जीएसटी/क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एलओपी में विशिष्ट रूप से निषिद्ध न हो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ निविष्टियों पर यदि छूट ली गई हो, तो उत्पाद शुल्क यदि लागू हो, तथा/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकरण का भुगतान कर डीटीए में 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर अस्वीकृत माल बेचा जा सकता है। निर्यात के 5 प्रतिशत एफओबी मूल्य तक अस्वीकृत माल की बिक्री एनएफई प्राप्त करने के अधीन नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रेप/अपशिष्ट/अवशेषों की बिक्री यथा लागू शुल्क और/या कर और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर शुल्क छूट योजना के तहत सिकोन अधिसूचना के अनुसार डीटीए में की जा सकती है। स्क्रेप/अपशिष्ट/अवशेषों की ऐसी बिक्री, सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी उन मदों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास आयुक्त छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है और इस अवधि के भीतर मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित कर सकती है। तदर्थ मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित न कर दे। स्क्रेप/अपशिष्ट/अवशेषों का निर्यात भी किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रेप/अपशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नैट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा। "शुल्क/कर नहीं" अभिव्यक्ति में जीएसटी कानून के अधीन लागू कर और उपकर शामिल नहीं होगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को भी डीटीए में बेचा जा सकता है बशर्ते कि यदि इनपुट्स पर लाभ लिए गए हैं, तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, तथा/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के अधीन हो।

(ज) हटा दिया गया है।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डीटीए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से गिनी जाएगी।

(ञ) हटा दिया गया है।

(ट) नये ईओयू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति होगी जो प्रथम वी के लिए अनुमानित निर्यातों के 50% से अधिक नहीं होगी, सिवाय भेषज यूनिटों में जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी।

(ठ) हटा दिया गया है।

(ड) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र हेतु स्वीकृत विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य के 2 प्रतिशत तक की जाने वाली पुर्जों/कलपुर्जों की अधिप्राप्ति को बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उसी खेप प्राप्तकर्ता/खरीदार को आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। सीमा शुल्क छूट, यदि ली गई हो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान किए जाने पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र संबंधी स्वीकृति दी जा सकती है।

6.09 अन्य आपूर्तियां

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों से प्राप्त निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी। ऐसी आपूर्तियों में 'मार्बल' शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि मार्बल की ऐसी आपूर्ति अन्तःयूनिट आपूर्ति हो जैसा कि नीचे उप-पैरा (ग) में बताया गया है:-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क छूट के तहत डीएफआईए/विमुक्ति योजना/ईपीसीजी स्कीम के धारकों के संबंध में डीटीए में की गई आपूर्तियां। तथापि, प्रिटिंग क्षेत्र की ईओयू (या अन्य कोई क्षेत्र जिसे प्रक्रिया पुस्तक में अधिसूचित किया जा सके) वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, जहां पर अग्रिम प्राधिकार पत्र के धारक/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार धारक के लिए मूल सीमाशुल्क और सीवीडी शून्य है या अन्यथा छूट मुक्त है।

- (ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के मद्दे डीटीए में की गई आपूर्तियाँ।
- (ग) अन्य निर्यातोन्मुख इकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलोजी पार्क/एसईजेड इकाई को आपूर्ति, बशर्ते ऐसे माल की खरीद के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.01 के अन्तर्गत अनुमति हो।
- (घ) विदेश व्यापार नीति और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदामों और मुक्त व्यापार तथा गोदाम क्षेत्रों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।
- (ङ.) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्तियाँ, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, जैसी प्रक्रिया पुस्तक में व्यवस्था है।
- (च) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्ति।
- (छ) निर्यात के लिए डीटीए यूनिट को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हैंगरों जैसे मदों की आपूर्तियाँ।
- (ज) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-20029/18/2001-पीपी दिनांक 28-01-2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002 (यहाँ पीडीएस स्कीम के रूप में निर्दिष्ट) के तहत सब्सिडाइज्ड मूल्यों पर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू तेल कम्पनियों को ईओयू रिफाइनरी में उत्पादित एलपीजी की सप्लाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी:-

- (i) एलपीजी की केवल ऐसी मात्रा की सप्लाई मान्य होगी जिसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्यात की स्वीकृति न दी हो और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एलपीजी की निकासी की जानी हो; और
- (ii) वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त पीडीएस स्कीम के तहत सप्लाई के लिए एलपीजी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी हो।

6.10 अन्य के माध्यम से निर्यात

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट, अपने द्वारा विनिर्मित माल/विकसित साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

6.11 डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी

- (क) डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों को निर्यात हेतु उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली निविष्टियों की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी। डीटीए आपूर्तिकर्ता उनके निर्यात दायित्व यदि कोई हो, का निर्वहन करने के अलावा विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के अंतर्गत संबंधित पात्रता के हकदार होंगे। डीजीटी से ईओयू को ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी जीएसटी नियमावली और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण के अधीन आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध होगी।
- (ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (ग) इसके अलावा, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होगी :-
- (i) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति। 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सी एस टी की वापसी में देशी पर देय होगा यदि पूरा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर मामले का निपटान नहीं किया जाता है। (जैसा प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.10(ख) में दिया गया है)
 - (ii) डीटीए से भारत में विनिर्मित ऐसी वस्तुओं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आती है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।
 - (iii) हटा दिया गया है।
 - (iv) हटा दिया गया है।

6.12 अन्य हकदारियाँ

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैं:

- (क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट
- (ख) निर्यात आय की वसूली 09 महीनों के भीतर करनी होगी।
- (ग) यूनिटों को ईईएफसी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन रखने की अनुमति होगी।
- (घ) यूनिटों को आयात करते समय या डीटीए में जॉब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का
 - (i) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का है;
 - (ii) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है; और
 - (iii) यूनिट ने :-

1. सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा/निर्यात दायित्व जहाँ भी लागू है, प्राप्त कर लिया है।

2. धोखा/सांठगांठ/जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को छुपाना या उनके किसी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम के दांडिक प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, वित्त अधिनियम 1994 सेवाकर या सहयोगी अधिनियम या उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा, के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस या पुष्टिकृत मांग जारी नहीं की है।

(ड.) एस ई जेड यूनिटों की तरह आटोमैटिक स्ट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी।

(च) हटा दिया गया है।

(छ) इकाई अनुमोदन समिति निर्यातोन्मुखी इकाइयों के मध्य मामला दर मामला आधार पर निवेदनों पर विचार करके अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साझा उपयोग पर विचार कर सकती है तथा यह अपनी सिफारिश पर विचार किए जाने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगी। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय इकाइयों के निवल विदेशी मुद्रा के दायित्व में परिवर्तन नहीं होगा। ईएचटीपी/ एसटीपी की इकाइयों को ऐसी सुविधाएं आईएमएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि निर्यातोन्मुखी इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयों के बीच सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13 अन्तर यूनिट हस्तांतरण

(क) निर्यातोन्मुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से अन्य ईओयू/ईएच टीपी/एसटीपी/बीटीपी/ यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की लागू जीएसटी और/अथवा क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के आवागमन की निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी इकाइयों के संबंधित विकास आयुक्त और संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी:

(i) ईओयू आपूर्तिकर्ता सामान्य वाणिज्यिक दस्तावेजों जैसे कर बीजक और वितरण चालान, अन्य ईओयू को आपूर्ति किए गए ऐसे तैयार माल (उप उत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल के उत्पादन, विनिर्माण, प्रक्रिया अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्कैप सहित) के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क की राशि पर प्राप्त की गई सीमा शुल्क में छूट की राशि संबंधी दस्तावेजों पर पृष्ठांकन करेगा। प्रापक ईओयू ऐसी पृष्ठांकित सीमा शुल्क राशि का डीटीए में ऐसे तैयार माल की स्वीकृति से पूर्व ऊपर पैरा 6.08 में यथा प्रदत्त सीमा शुल्क के रिवर्सल के अपने दायित्व के अलावा और इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचनाएँ/परिपत्र/दिशानिर्देश में यथा प्रदत्त राशि का भुगतान करेगा।

(ii) माल की प्राप्ति पर, प्रापक ईओयू अपने क्षेत्राधिकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी को और आपूर्तिकर्ता ईओयू के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी को कर बीजक की पृष्ठांकित प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

(ख) लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड यूनिटों को हस्तांतरित किया जा सकता है या ऋण पर दिया जा सकता है। ऐसी हस्तांतरित वस्तुओं को लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर दूसरी इकाई द्वारा मूल इकाई को वापस भी किया जा सकता है यदि मामला अस्वीकृति अथवा किसी अन्य कारण का हो।

(ग) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की एक यूनिट द्वारा अन्य यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, वस्तुओं के मूवमेंट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति शुल्क के भुगतान पर की जाएगी।

(i) आपूर्तिकर्ता ईओयू प्रचलित वाणिज्यिक दस्तावेज पर पृष्ठांकन करेगा, जैसे कि कर बीजक और वितरण चालान, अन्य ईओयू को आपूर्ति किए गए ऐसे माल पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत छूट के रूप में लाभ उठायी गई प्रभार्य सीमाशुल्क राशि। प्राप्तकर्ता ईओयू डीटीए में ऐसी वस्तुओं अथवा ऐसी वस्तुओं से विनिर्मित या उत्पादित तैयार माल की निकासी से पहले ऐसे पृष्ठांकित सीमाशुल्क और लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकरण का भुगतान करेगा।

(ii) माल की प्राप्ति पर, प्रापक ईओयू अपने क्षेत्राधिकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी को और आपूर्तिकर्ता ईओयू के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी को कर बीजक की पृष्ठांकित प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों का समूह जो केन्द्रीय रूप से निविष्टियों की प्राप्ति करते हैं ताकि भारी छूट प्राप्त की जाए तथा/अथवा यातायात तथा संभार तंत्र की लागत को कम किया जाए और/अथवा कुशल आपूर्ति शृंखला को कायम रखा जा सके को इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर माल और सेवाओं के अंतर इकाई हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार प्राप्त निविष्टियों का आयात करने के बाद उन्हें किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जाता है तो एनएफई की गणना के प्रयोजनार्थ इस प्रकार हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य को अंतर्वाह और इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाली यूनिट के लिए आउटफ्लो माना जाएगा।

6.14 उप-ठेके

(क) (i) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें, जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर जॉब वर्क के जरिये डी टी ए को उत्पादन प्रक्रिया का उप-ठेका दे सकती हैं जिनमें डीटीए में यूनिटों द्वारा जॉब वर्क के जरिये माल के रूप या स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है।

(ii) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डीटीए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक ही उप ठेके पर दे सकती हैं।

(ख) (i) ईओयू यूनिटों को डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्त माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए गए शुल्क को वापस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी। तथापि, शुल्क वापसी की यह ब्रांड दर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 2017 के अनुसार होगी तथा सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV के तहत शामिल पात्र मदों के संबंध में) तक सीमित होगी।

(ii) ऊपर पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत यथा प्रदत्त शुल्कों और/अथवा करों के भुगतान के साथ या इसके बगैर जॉब वर्क के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए।

(iii) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू की जा सकती है।

(iv) 'ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी एकक विदेशों में उत्पादन प्रक्रिया के अंश का उप ठेका दे सकते हैं और एलओपी में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती उत्पादों को विदेश भेज सकते हैं। विदेशी उप ठेकेदार परिसर से माल का निर्यात करते समय किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब माल को देश में वापस लाया जाएगा, सम्बंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जायेगी।'

(ग) जॉब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्कैप/वेस्ट/रेमनन्ट को या तो जॉब वर्कर के कार्य स्थल से सौदा मूल्य पर ऊपर पैरा 6.08 के तहत यथा प्रदत्त लागू शुल्क और/अथवा करों के भुगतान पर हटाया जा सकता है या सीमा शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नैट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नैट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ईओयू इकाइयों द्वारा अन्य ईओयू या एसईजैड या डीटीए में इकाइयों में उपठेका/विनिमय प्रक्रिया पुस्तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

6.15 प्रयोग न किए गए माल की बिक्री

क) यदि कोई निर्यातानुमुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की यूनिट डीटीए से आयातित या खरीदे गए माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो

- (i) इन्हें अन्य ईओयू/ईएचटीपी /एसटीपी/बीटीपी/एसईजैड/इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है; या
- (ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करते हुए लागू शुल्कों तथा /अथवा करों और क्षतिपूर्ति कर का भुगतान करके सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य डीटीए में निपटान कर सकती है। इसके अलावा आयात के समय सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य यदि कोई सीमा शुल्क छूट प्राप्त की गई हो वह भी देय होगी तथा आयात प्राधिकार पत्र को प्रस्तुत करना होगा; अथवा
- (iii) किया गया निर्यात ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मदों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा।

(ख) पूंजीगत माल और स्पेयर्स जो अप्रचलित हो गए/अतिरिक्त हैं उन्हें अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजैड इकाइयों को हस्तांतरण या निर्यात किया जा सकता है अथवा लागू जीएसटी तथा क्षतिपूर्ति उपकर तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के भुगतान के बाद डीटीए में निपटान किया जा सकता है। डीटीए में निपटान की स्थिति में मूल्यहास का लाभ केवल तब उपलब्ध होगा जब इकाई ने लागू मूल्य हास को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो। पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोग्य वस्तुएं, कलपुर्जे, विनिर्मित माल, संसाधित या पैकिंग किया गया और स्कूप/अपशिष्ट /रैमनेन्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नैट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नैट करने पर जीएसटी कानून के तहत लागू करों को छोड़कर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पथरों पर उपर्युक्त वर्णित नष्ट करना लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी।

6.16 रिकंडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना

(क) निर्यातानुमुख यूनिटों को रिकंडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए यूएसी की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क), (ख), (ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

(ख) ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को रिकंडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए आईएमएससी की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क), (ख), (ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.08, 6.09, 6.10, 6.13, 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

6.17 आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) वस्तुओं के प्रतिस्थापन/मरम्मत के निर्यात/आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान रूप से लागू होंगे। इन प्रावधानों के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई और किन्हीं कारणों से स्वीकार न की गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचना देते हुए मरम्मत/ बदलने के लिए वापस लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी स्म से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके कोई हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं, लौटाए और प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं अथवा नैट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलों में वस्तुएं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं अथवा भारत में उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं/स्वदेशी संभरकों से वापस लायी जा सकती है। यूनिट विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारत में अधिकृत एजेन्टों से मुफ्त प्रतिस्थापन (प्रदत्त शुल्क) ले सकती है बशर्ते कि खराब हिस्से का पुनः निर्यात किया गया हो या नैट किया गया हो। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती रत्नों और कीमती धातुओं पर विनिर्देशित लागू नहीं होगा।

6.18 ईओयू योजना से बहिर्गमन

(क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से, निर्यातानुमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। ऐसा बहिर्गमन लागू उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के भुगतान तथा लागू आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर और लागू औद्योगिक नीति के तहत होगा।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व पूरा नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन, के समय उसे जुर्माना देना होगा।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित एजेंसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों के लिए मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के तहत पूंजीगत माल पर लागू शुल्क तथा कर और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करके विकास आयुक्त द्वारा किसी भी समय स्कीम को छोड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है। यह ईओयू स्कीम के तहत सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा मानदण्ड की पूर्ति, ईपीसीजी स्कीम के तहत पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मानक शर्तों के अधीन होगा।

(ङ.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लिखित में सूचित करना होगा। यूनिट निकासी के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगी। सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर शुल्क दायित्वों की पुष्टि करेंगे बशर्त अनुमत मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए इकाई ने सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो। शुल्क के भुगतान तथा सभी बकाया राशि का भुगतान कर देने के पश्चात् यूनिट सीमाशुल्क प्राधिकारियों से बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क द्वारा जारी बेबाकी प्रमाण-पत्र के आधार पर यूनिट अन्तिम स्तर से निकासी के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम निकासी आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र और विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गए अन्तिम आदेश के बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगी। तथापि वे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं। चूंकि गणना और देय राशि विवादग्रस्त है और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/बीजी द्वारा किस्त प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाएगी।

(च) जिन मामलों में यूनिट लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क/जीएसटी का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डीटीए यूनिट के रूप में स्थापित होती है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में निकासी के पश्चात् डीटीए में ऐसी पूंजीगत वस्तुएँ ले जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार जहाँ ई पी सी जी योजना के तहत डीटीए यूनिट ने पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात् ईओयू में परिवर्तित होती हैं, यूनिट से डीटीए तक ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को निकासी के समय ले जाते समय पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

(छ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार के तहत एक बार के विकल्प के रूप में निकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है। यह सकारात्मक एन एफ ई मानदण्ड की पूर्ति के अधीन होगा।

(ज) कच्चे माल, पूंजीगत माल इत्यादि की अधिप्राप्ति के संबंध में कोई शुल्क लाभ न लेने वाली एसटीपी/ईएचटीपी इकाई का अनुबंध तोड़ने/बाहर करने के लिए त्वरित (फास्ट ट्रेक) सुविधा देने हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है।

6.19 परिवर्तन

(क) मौजूदा डीटीए यूनिटें किसी निर्यातानुमुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन भी कर सकती हैं।

(ख) विद्यमान ईएचटीपी/एसटीपी यूनिटें, ईओयू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने अथवा विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें यथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

(ग) वर्तमान डीटीए इकाईयाँ जिनके संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवेश किया गया हो अथवा जो 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि का वार्षिक निर्यात करती हों के ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में परिवर्तित करने हेतु आवेदनों को निर्णय लेने हेतु अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के समक्ष रखा जाएगा।

6.20 एन एफ ई की निगरानी

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

6.21 प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन यात्राओं/ विदेश में शो-रूमों/ शुल्क मुक्त दुकानों के जरिये निर्यात

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को निम्नलिखित की अनुमति है:

- (i) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी करने/उनमें शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना ।
- (ii) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से लाना/ले जाना ।
- (iii) विदेशों में स्थापित अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/बिक्री हेतु माल का निर्यात करना।
- (iv) विदेशों में स्थापित अनुमोदित दुकानों में या उनके वितरकों/ एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/विक्रय।
- (v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो-रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना करना ।

6.22 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से लाना ले जाना जिसमें विदेश जाने वाले यात्रियों के जरिए सामान ले जाना शामिल है

रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाईयों के अलावा यूनिटों के लिए आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हों । भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रत्न एवं आभूषण ई ओ यू का प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत ढुलाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 किग्रा. तक प्रारंभिक रूप में सोने का आयात कर सकता है।

6.23 डाक/कूरियर द्वारा निर्यात/आयात

निःशुल्क नमूनों सहित माल का सीमा शुल्क प्रक्रिया के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाने या कूरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

6.24 ईओयू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त की शक्तियाँ

ईओयू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त की शक्तियों का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है।

6.25 रूण यूनिटों का पुनर्स्थान

उपयुक्त प्राधिकाशी द्वारा यूनिट को रूण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनर्स्थान या अधिग्रहण के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

6.26 ईएचटीपी/एसटीपी का अनुमोदन

हटा दिया गया है।

6.27 बीटीपी का अनुमोदन

हटा दिया गया है।

6.28 मालगोदाम सुविधाएं

हटा दिया गया है।

अध्याय 7**मान्य निर्यात****7.00 उद्देश्य**

कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए, में घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना।

7.01 मान्य निर्यात

(i) इस विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन हेतु मान्य निर्यात का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित पैराग्राफ 7.02 में यथा उल्लिखित माल की आपूर्ति 'मान्य निर्यात' के रूप में मानी जाएगी बशर्ते कि माल का भारत में विनिर्माण हुआ हो।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रयोजन हेतु जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर 'मान्य निर्यात' में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 147 के तहत अधिसूचित आपूर्तियों को ही शामिल किया जाएगा। जीएसटी के लाभ तथा ऐसे लाभों हेतु लागू शर्तें जीएसटी परिषद और संबंधित नियमों और अधिसूचनाओं के यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

7.02 आपूर्ति की श्रेणियाँ

एक विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों (क) से (घ) और मुख्य/उप-ठेकेदार द्वारा श्रेणियों (ड.) से (ज) के तहत माल की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' माना जाएगा।

क. विनिर्माता द्वारा आपूर्ति:

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के अधीन माल की आपूर्ति;

(ख) निर्यातोन्मुख यूनितों (ईओयू)/साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एसटीपी)/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क (ईएचटीपी)/बायोटेक्नोलोजी पार्क (बीटीपी) को माल की आपूर्ति।

(ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अधीन पूंजीगत माल की आपूर्ति।

(घ) हटा दिया गया है।

ख. मुख्य/उप-ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति

(ड.) (i) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जहाँ पर विधिक समझौते सीमाशुल्क को शामिल किए बगैर निविदा मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

(ii) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल और उपकरणों (टर्नकी संविदाओं के लिए एकल उत्तरदायित्व) की आपूर्ति और संस्थापन जिनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हों और विदेशों में विनिर्मित माल के लिए सुपुर्दगी पर चुकाया गया शुल्क (डीडीपी) के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

(iii) आपूर्तियाँ उन एजेंसियों/निधियों की प्रक्रिया के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के तहत इस पैराग्राफ में शामिल होंगी।

(iv) मान्य निर्यात लाभ के लिए इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट 7क** में दी गई है।

च(i) किसी परियोजना अथवा किसी प्रयोजन के लिए माल की आपूर्ति जिसके लिए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.3.2012 की पूर्व अधिसूचना सं० 12/2012-सीमाशुल्क द्वारा वित्त मंत्रालय ने इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन (बीसीडी और सीवीडी दोनों को छोड़कर) शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान की थी जो सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क विभाग दिनांक 30.06.2017 के तहत शून्य मूल सीमा शुल्क को छोड़कर जारी है और उक्त नई अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब आईसीबी की प्रक्रिया के तहत आपूर्ति की जाती है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 50/2017-सीमा शुल्क विभाग दिनांक 30.06.2017 की क्रम सं० 598 पर सूची 31 में यथाविनिर्दिष्ट किसी मेगा विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक माल की आपूर्ति इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन मान्य निर्यात लाभ की पात्र होंगी बशर्ते कि ऐसी मेगा विद्युत परियोजना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो।

(iii) यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से सम्बद्ध किया गया हो अथवा यदि परियोजना प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा दी गयी हो तो मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए आईसीबी शर्त अनिवार्य नहीं होगी।

(छ) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं छूट अधिनियम) 1947 की धारा 3 के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्र को या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उनके सरकारी उपयोग के लिए माल की आपूर्ति अथवा उक्त संयुक्त राष्ट्र या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति। ऐसे संगठन और ऐसी आपूर्तियों के लिए लागू शर्तों की सूची समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 11.11.1997 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना सं० 84/97—सीमा शुल्क विभाग में दी गई है। इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की एक सूची परिशिष्ट-7ख में दी गई है।

(ज) परमाणु विद्युत परियोजनाओं को प्रदत्त माल की आपूर्ति:

(i) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 30.06.2017 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना सं० 50/2017—सीमा शुल्क विभाग की क्रम सं० 602 की सूची 32 में यथा विनिर्दिष्ट तथा इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन किसी परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए ऐसे माल की आवश्यकता होती है।

(ii) परियोजना की 440 मे०वा० या उससे अधिक क्षमता होनी चाहिए।

(iii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आवश्यक है जो परमाणु उर्जा विभाग में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(iv) निविदा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (एनसीबी) या आईसीबी के द्वारा आमंत्रित की जाती है।

7.03 मान्य निर्यात के लिए लाभ

प्रक्रिया पुस्तक और एएनएफ-7क में दी गयी शर्तों के अनुसार मान्य निर्यात के स्म में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित में से कोई/सभी लाभ दिए जाएंगे :-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए

(ख) बीसीडी हेतु मान्य निर्यात शुल्क वापसी।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची-4 में उल्लिखित उत्पाद कर योग्य वस्तुओं हेतु अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी बशर्ते आपूर्ति मान्य निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत पात्र हो और इसमें कोई छूट प्राप्त न हो।

7.04 आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता का लाभ

पैरा 7.02 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियाँ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो			
	पैरा 7.03(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र	पैरा 7.03(ख) शुल्क वापसी	पैरा 7.03(ग) अंतिम उत्पाद शुल्क	
(क)	हाँ (अमान्यकरण पत्र के अधीन अंतरवर्ती आपूर्तियों के लिए)	हाँ (एआरओ के मद्दे)	हाँ	
(ख)	हाँ	हाँ	हाँ	
(ग)	हाँ	हाँ	लागू नहीं	
(घ)	हटा दिया गया है	हटा दिया गया है	हटा दिया गया है	
(ङ.)	हाँ	हाँ	लागू नहीं	
(च)	हाँ	हाँ	हाँ, केवल पैरा 7.08 (iii) (क) हेतु	
(छ)	हाँ	हाँ	लागू नहीं	

पैरा 7.02 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियाँ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो			
(ज)	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं

7.05 अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए शर्त

(i) माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ग) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवैट क्रेडिट/ छूट प्राप्त न की हो।

(ii) हटा दिया गया है।

(क) हटा दिया गया है।

(ख) हटा दिया गया है।

(ग) हटा दिया गया है।

(घ) हटा दिया गया है।

7.06 मान्य निर्यात की शुल्क वापसी के लिए शर्तें

आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं :

उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली निविष्टियों की मूल सीमा शुल्क के रूप में शुल्क-वापसी मूल सीमा शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ब्रांड दर आधार पर की जाएगी।

7.07 मान्य निर्यात लाभों के लिए सामान्य शर्तें

(i) पैरा 7.02 में सूचीबद्ध कम्पनियों को आपूर्ति सीधे की जाएगी। तृतीय पक्षकार की आपूर्ति लाभ/छूट हेतु पात्र नहीं होगी।

(ii) सभी मामलों में, आपूर्ति सीधी नामोदिष्ट परियोजनाओं/ एजेंसियों/इकाइयों/अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को की जाएगी। उप संविदाकार, तथापि, नामोदिष्ट परियोजना/ एजेंसियों के बजाए मुख्य संविदाकार को सीधे आपूर्ति कर सकता है। ऐसे मामलों में भुगतान मुख्य-संविदाकार द्वारा उप-संविदाकार को किया जाएगा न कि परियोजना प्राधिकारी द्वारा।

(iii) किसी भारतीय उप-संविदाकार द्वारा किसी भारतीय अथवा विदेशी मुख्य संविदाकार को नामोदिष्ट परियोजनाओं/एजेंसियों की साइट के लिए स्वदेशी विनिर्मित माल की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के लिए भी पात्र होगी बशर्ते उप-संविदाकार का नाम मुख्य संविदा में या तो मूल रूप से अथवा बाद में (परन्तु ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख के पहले) दर्शाया गया हो।

7.08 विनिर्दिष्ट आपूर्तियों पर लाभ

(i) मान्य निर्यात लाभ केवल पैरा 7.02(ड.) के तहत 'सीमेंट' की आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।

(ii) मान्य निर्यात लाभ 'इस्पात' की आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध होगा ;

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक/ईओयू संबंधी निविष्टियों के रूप में।

(ख) उप-पैरा 7.02(ड.) के अनुसार बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधि पोषित एजेंसियों को।

(iii) 'ईंधन' की (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची 4 के अंतर्गत शामिल पात्र ईंधन मदों के मामले में) आपूर्ति करने पर मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होगा बशर्ते आपूर्ति निम्नलिखित को की जाए:

(क) समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना सं० 50/2017-सीमा शुल्क विभाग दिनांक 30.06.2017 में क्रम सं० 44 के तहत और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन तथा विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(च) में शामिल पेट्रोलियम प्रचालन हेतु सूचीबद्ध परियोजनाएं।

(ख) ई ओ यू;

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक।

7.09 ब्याज का दायित्व

अपूर्ण/अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी में देरी होने पर 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा बशर्ते क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान नहीं किया गया हो।

7.10 जोखिम प्रबंधन और आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र

क) एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी जिसमें डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक माह कम्प्यूटर सिस्टम यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए 10 मामलों का चयन करेगा जहाँ पर इस अध्याय के लिए लाभ पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। सभी मण्डलों के मण्डलीय अपर महानिदेशक के कार्यालय में संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार की अध्यक्षता में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा ऐसे मामलों की जाँच की जाएगी। टीम न केवल अपने कार्यालय के ऑडिट दावों के लिए उत्तरदायी होगी अपितु मण्डल के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी क्षेत्रीय प्राधिकरणों के दावों के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी भी किसी मामले की आंतरिक लेखा परीक्षा/बाह्य लेखा परीक्षा अभिकरण/अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अथवा अपनी ओर से स्वयं पुनः आकलन कर सकता है, जिसमें कोई दोषपूर्ण/अपात्र भुगतान किया गया हो/दावा किया गया हो। क्षेत्रीय अधिकारी वसूली योग्य राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

7.11 दण्डनीय कार्रवाई

यदि दावे को तथ्यों की गलत घोषणा/गलत बयानी के साथ दायर किया गया है तो ऊपर पैरा 7.10(ख) के तहत वसूली किए जाने के अतिरिक्त आवेदक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों इसके नियमों और आदेशों के तहत दण्डनीय कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.12 परिवर्ती पैरा

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में उल्लिखित मान्य निर्यात लाभ दिनांक 30.06.2017 तक लागू एफटीपी 2015-20 के प्रावधानों के अनुसार 30.06.2017 तक की गई आपूर्तियों पर उपलब्ध होंगे। दिनांक 30.06.2017 के बाद की गई आपूर्ति के संबंध में नए प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय - 8**गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद****8.00 उद्देश्य**

निर्यातकों को निर्यात के संवर्धन हेतु विदेश में देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। विदेशी खरीदारों के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा जब भी कोई शिकायत अथवा व्यापार संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, तो सौहार्दपूर्ण तरीके से यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाना होता है। आयातकों को भी कई शिकायतें हो सकती हैं।

ऐसी शिकायतों या व्यापार संबंधी विवादों के निपटान हेतु प्रयास के रूप में और देश के व्यापारिक माहौल में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है जिससे ऐसी शिकायतों और विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके।

8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाए:

(क) भारत के निर्यातकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की घटिया गुणवत्ता के संबंध में विदेशी खरीदारों से प्राप्त शिकायतें।

(ख) आपूर्ति किए गए उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध आयातकों की शिकायतें; तथा

(ग) अनैतिक वाणिज्यिक सौदे संबंधी ऐसी शिकायतें जिन्हें मुख्यतः इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है, जैसे आदेश की पुष्टि के पश्चात् माल की आपूर्ति न किया जाना/आंशिक आपूर्ति, जिस माल पर सहमति हुई है, उससे भिन्न माल की आपूर्ति, भुगतान न किया जाना, सुपुर्दगी अनुसूचियों का पालन न किया जाना आदि।

8.02 आयातक/निर्यातक का दायित्व

(क) विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली 1993 के नियम 11 में अपेक्षित है कि किसी माल के किसी सीमाशुल्क पत्तन में आयात होने अथवा वहाँ से निर्यात होने पर चाहे वह शुल्क के लिए दायी हो अथवा नहीं, इस माल का स्वामी प्रविष्टि बिल अथवा पोतलदान बिल अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज पर माल का मूल्य,

मात्रा और विवरण अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर प्रस्तुत करेगा तथा माल के निर्यात की स्थिति में यह प्रमाणित करेगा कि माल की गुणवत्ता और विनिर्देश जैसा कि दस्तावेजों में वर्णित है, खरीदार अथवा परेषिती के साथ की गई निर्यात संविदा की शर्तों के अनुसार है तथा उसके अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है। तथा इस कथन की सच्चाई की घोषणा प्रविष्टि बिल अथवा पोतलदान बिल अथवा किसी अन्य दस्तावेज में करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन होने पर निर्यातक दंडिक करवाई हेतु दायी होगा।

(ख) कतिपय निर्यात वस्तुओं को उनके निर्यात से पूर्व अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान-पूर्व निरीक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है। 1984 में यथासंशोधित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत ऐसे निर्यातक जो इन मानकों तथा/अथवा अधिनियम के इन उत्पादों के लिए यथा निर्धारित उपबंधों का पालन नहीं करते हैं, के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जा सकती है।

8.03 चूककर्ता निर्यातकों/ आयातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली में प्रावधान

यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के तहत चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जो निम्नानुसार है:

(क) अधिनियम की धारा 8 में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उसमें दिए गए कारणों के लिए आयातक/ निर्यातक कोड सं० को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ख) अधिनियम की धारा 9(2) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए वित्तीय या आर्थिक लाभ देने वाले लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज देने या नवीकरण करने से मना करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) धारा 9(4) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए आर्थिक या वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(घ) अधिनियम की धारा 11(2) में उन मामलों में वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान है जिनमें कोई व्यक्ति अधिनियम, नियमावली या उसके अन्तर्गत दिए गए आदेश अथवा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयात या निर्यात करता है या उसको बढ़ावा देता है या ऐसा करने का प्रयास करता है।

8.04 शिकायतों/विवादों की निगरानी हेतु तंत्र

(क) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी)

शिकायतों और विवादों की बढ़ रही संख्या को प्रभावी रूप से निपटारा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति' (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा।

(ख) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति का गठन

विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा और यह गठन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ग) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति के कार्य

यह समिति (सीक्यूसीटीडी) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाली गुणवत्ता संबंधी शिकायतों तथा व्यापार संबंधी अन्य शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए जिम्मेवार होगी। यह समिति शिकायत मिलने के अधिमानतः तीन महीने के भीतर आयातकों, निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं की शिकायतों का निपटारा और समाधान करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति (सीक्यूसीटीडी) निर्यात संवर्धन परिषदों/फियो/ पण्य बोर्डों या किसी अन्य एजेंसी जोकि इन विवादों के निपटारे के लिए आवश्यक हो, की सहायता ले सकती है।

8.05 सीक्यूसीटीडी के तहत कार्रवाई

गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति की कार्यवाही केवल समाधान स्वरूप की है और पीड़ित पक्ष चाहे विदेशी क्रेता हो या भारतीय आयातक हो, अन्य चूककर्ता पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

8.06 शिकायतों और व्यापार विवादों से निपटने की प्रक्रिया

ऐसी शिकायतों या व्यापार विवादों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा ऐसी गुणवत्ता शिकायतों और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक में दी गई है।

8.07 सुधारात्मक उपाय

क्षेत्रीय प्राधिकरण स्तर की समिति यह मूल्यांकन करने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी या किसी तकनीकी प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है कि मानकों, विनिर्माण/ डिजाइन खामियों आदि जिसके लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं, को पूरा नहीं करने में कोई तकनीकी असफलता रही है या नहीं।

8.08 नोडल अधिकारी

महानिदेशक, विदेश व्यापार विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने हेतु 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यालय में कम से कम संयुक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी को नियुक्त करेंगे।

अध्याय - 9**परिभाषाएं**

	विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:-
9.01	“उपांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।
9.02	“अधिनियम” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) (एफ टी डी एण्ड आर) एक्ट)।
9.03	“वास्तविक प्रयोक्ता” का अर्थ है उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो अपने परिसर में आयातित माल के उपयोग के लिए प्राधिकृत है जिसका कोई स्थायी डाक पता हो।
	(क) “वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी स्वयं की औद्योगिक यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा जाबिंग यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करता है जिसका स्थायी डाक पता हो।
	(ख) “वास्तविक प्रयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो:- (i) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, जिसका स्थायी डाक पता हो; या (ii) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अस्पताल, जिसका स्थायी डाक पता हो; या (iii) अन्य सेवा उद्योग जिसका स्थायी डाक पता हो,

9.04	“ए ई जैड” का अर्थ है परिशिष्टों और आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2फ में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।
9.05	“अपील” वह आवेदन है जो कि अधिनियम के खण्ड 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वे आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जमा किए जाते हैं ।
9.06	“आवेदक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।
9.07	“प्राधिकार-पत्र” का अर्थ है विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि अधिनियम के भाग 2(छ) में बताया गया है।
9.08	<p>“पूँजीगत माल” का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है । इसमें पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रशीतन उपकरण, उर्जा सृजित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, परीक्षण, अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं ।</p> <p>पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है ।</p>
9.09	“सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य अथवा कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो ।
9.10	“संघटक” का अर्थ है उप संयोजन या संयोजन का वह तत्व जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए । संघटक में दूसरे संघटक के उपैंगी या उपकरण भी शामिल हैं ।
9.11	“उपभोज्य” का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो । विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जिन मदों का अधिक मात्रा में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।
9.12	“उपभोक्ता माल” का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे ।

9.13	<p>“प्रतिसंतुलन व्यापार” (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो ।</p> <p>“प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड)” के अन्तर्गत निर्यात/ आयात की अनुमति एस्करो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। निर्यात और आयात का संतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है ।</p>
9.14	<p>“विकासकर्ता” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसा ही अन्य निजी या सरकारी उपक्रम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, वित्तीय सहायता, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है, इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल है।</p>
9.15	<p>“विकास आयुक्त” का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त ।</p>
9.16	<p>“घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र” (डीटीए) का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी से बाहर है ।</p>
9.17	<p>हटा दिया गया है ।</p>
9.17क	<p>विदेश व्यापार नीति (2015–20) (एफटीपी) के तहत भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात स्कीम के उद्देश्य हेतु “ई-कॉमर्स” का अर्थ वेबसाइट पर दिए गए वस्तुओं के निर्यात को खरीदार के लिए इंटरनेट के माध्यम से पहुँच योग्य बनाना है। जबकि एमईआईएस के तहत यथा विनिर्दिष्ट, वस्तुओं का प्रेषण कूरियर या डाक मोड के माध्यम से किया जाएगा, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर खरीदे गए वस्तुओं के लिए भुगतान, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र (आर बी आई/2015–161185) [ए.पी. (डीआईआर सरिज) परिपत्र सं० 16 दिनांक 24 सितम्बर 2015] के अनुसार किया जाएगा ।</p>
9.18	<p>“ई.ओ.यू.” का अर्थ है निर्यातोन्मुखी एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो ।</p>
9.19	<p>“उत्पाद शुल्क देय माल” का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन हो ।</p>
9.20	<p>समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथा-परिभाषित ‘निर्यात’</p>
9.21	<p>“निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, या निर्यात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।</p>

9.22	निर्यात दायित्व का अर्थ है:- प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा में शामिल निर्यात उत्पाद अथवा उत्पाद का क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।
9.23	मदों के लिए आयात/निर्यात के संदर्भ में आने वाले "मुक्त" से तात्पर्य है माल जिसे देश में आयात किए जाने अथवा देश से निर्यात किये जाने के लिए किसी प्राधिकार-पत्र/लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
9.24	"विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति जो कि अधिनियम के भाग-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है।
9.25	समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथापरिभाषित "आयात"।
9.26	"आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, या आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
9.27	"आई टी सी (एच एस)" का अर्थ निर्यात और आयात मदों के 8 अंकों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है।
9.28	"जाबिंग" का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्यवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो।
9.29	"लाइसेंसिंग वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जो वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।
9.30	"प्रबंधित होटल" से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार में प्रबंधित होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा।
9.31	<p>"विनिर्माण" का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, री-कन्डीशनिंग, मरम्मत, री-मेकिंग, री-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन री-इन्जीनिरिंग।</p> <p>विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए विनिर्माण में कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।</p>

9.32	“विनिर्माता निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है ।
9.33	“व्यापारी निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो ।
9.34	“एन सी” का अर्थ उन मामलों में जहाँ पर सिओन मौजूद नहीं है और विदेश व्यापार महानिदेशालय में अधिसूचित किए जाने के लिए सिओन की सिफारिश करते हैं, तदर्थ निविष्टि-उत्पादन मानदंड के अनुमोदन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदंड समिति से है ।
9.35	“अधिसूचना” का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।
9.36	“आदेश” का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश ।
9.37	“पुर्ज” का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो । पुर्जा एक संघटक, स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है ।
9.38	“व्यक्ति” का अर्थ है कोई व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, निगम अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों सहित अन्य कोई वैध व्यक्ति ।
9.39	“नीति” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) ।
9.40	“निर्धारित” का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा विदेश व्यापार नीति अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश के तहत निर्धारित से है ।
9.41	“प्रतिबंधित” आईटीसी(एचएस) में अथवा अन्यत्र आने वाली किसी मद की आयात/निर्यात नीति को दर्शाता है, जिसका आयात/निर्यात अनुमत नहीं है।
9.42	“सार्वजनिक सूचना” का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.55 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है ।
9.42क	“परियोजना निर्यात” का अर्थ आस्थगित भुगतान शर्तों और टर्नकी परियोजनाओं के निष्पादन और संयुक्त रूप से विदेशों के सिविल निर्माण अनुबंधों पर अभियांत्रिकी सामानों के निर्यात को दर्शाता है । परियोजना के निर्यात में शामिल होगा (i) सिविल निर्माण अनुबंध; (ii) आस्थगित भुगतान शर्तों पर पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति सहित टर्नकी अभियांत्रिकी अनुबंध (iii) प्रक्रिया और अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएं; और (iv) परियोजना निर्माण मदे (इस्पात और सीमेंट को छोड़कर)

9.43	“कोटा” से तात्पर्य है एक विशिष्ट प्रकार के माल की मात्रा जिसे अतिरिक्त शुल्क लगाए बगैर अथवा प्रतिबंधों के बगैर आयात करने के लिए अनुमत किया गया हो।
9.44	“कच्ची सामग्री” का अर्थ है: मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है। ये सामग्री कच्ची/प्राकृतिक/ अपरिष्कृत/अविनिर्मित अथवा विनिर्मित अवस्था में हो सकती हैं।
9.45	“क्षेत्रीय प्राधिकारी” का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत एक प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी ।
9.46	“पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र” (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है ।
9.47	“प्रतिबंधित” एक मद के आयात अथवा निर्यात नीति को दर्शाने वाला एक पद है, जिसे केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालयों से एक प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद देश में आयात अथवा देश से बाहर निर्यात किया जा सकता है।
9.48	“नियमों” का अर्थ है एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।
9.49	“स्कोमेट” विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, पदार्थों, उपस्करों और प्रौद्योगिकियों के दोहरे प्रयोग की मदों के लिए नामकरण है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत दोहरे प्रयोग की मदों और प्रौद्योगिकियों का निर्यात विनियमित है। यह प्राधिकार-पत्र के तहत या तो प्रतिबंधित है या अनुमत है।
9.50	“सेवाओं” में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है ।
9.51	“सेवा प्रदाता” का अर्थ है वह व्यक्ति जो:- (i) भारत से किसी और देश के लिए “सेवा” प्रदान करता है, (विधि 1-सीमा पार व्यापार) (ii) भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई “सेवा” की आपूर्ति करता है, (विधि 2-विदेश व्यापार खपत) (iii) भारत से किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है। (विधि 3-वाणिज्यिक उपस्थिति) (iv) भारत में वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से किसी अन्य देश में “सेवा” की आपूर्ति (विधि 4-वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति)
9.52	“शिप” का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्र तट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है, इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं ।

9.53	“सिओन” का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित, मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों से है ।
9.54	“स्पेयर्स” का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। स्पेयर्स में संघटक या सहायक उपकरण शामिल हैं।
9.55	“विनिर्दिष्ट” का तात्पर्य अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।
9.56	“स्तर धारक” का आशय उस निर्यातक से है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक/विकास आयुक्त ने निर्यात सदन/दो सितारा व्यापार सदन /तीन सितारा व्यापार सदन/चार सितारा व्यापार सदन/पाँच सितारा व्यापार सदन के स्तर में मान्यता दी है ।
9.57	“भंडार” से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएँ हैं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपस्करों का अन्य सामान है, चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो ।
9.58	(क) “सहायक विनिर्माता” वह व्यक्ति है जो एक विशिष्ट प्राधिकार-पत्र के तहत व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक के लिए माल/उत्पाद या माल/उत्पाद के किसी हिस्से/उपभागी/ पुर्जों का विनिर्माण करता है। (ख) ईपीसीजी स्कीम के लिए “सहायक विनिर्माता” ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रांगण/फैक्टरी में ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत पूंजीगत माल आयात/प्राप्त किया जाता है।
9.59	विदेश व्यापार नीति के प्रयोजनार्थ राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई), वे इकाईयाँ हैं जिन्हें विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 (क) के अनुसार निर्यात और/अथवा आयात के विशिष्ट अधिकार/विशेष अधिकार प्रदान किए गए हों।
9.60	“तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात” का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक (निर्यातकों) की ओर से किया गया निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख करना होगा। बैंक वसूली प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा प्रपत्र, निर्यात आदेश और बीजक, तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए ।
9.61	“सौदा मूल्य” की परिभाषा राजस्व विभाग की सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली में यथा परिभाषित की गई है ।
9.62	“वन्य प्राणी” का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में यथा परिभाषित है ।

परिशिष्ट—I**2.17 कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध निर्यात पर निषेध:**

(क) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) को निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या निर्यात निषिद्ध है:

- (i) परम्परागत हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर में यथा परिभाषित कोई बैटल टैंक, आर्मर्ड कम्बैट वाहन, बड़ी क्षमता की आर्टिलरी प्रणाली, कम्बैट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल या मिसाइल प्रणाली या कलपूर्ज सहित संबंधित सामग्री;
- (ii) छोटे हथियार और हल्के हथियार और उससे संबंधित सामग्री सहित सभी हथियार और संबंधित सामग्री;
- (iii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दस्तावेजों में यथा उल्लिखित सभी मदें, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी,
 1. एस/2006/853*;
 2. एस/2006/853/कोर.1;
 3. एस/2009/364 का भाग ख;
 4. संकल्प 2094 (2013) का अनुलग्नक—III;
 5. एस/2016/1069;
 6. आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव. 12/भाग—1 का अनुलग्नक—क (आईएईए दस्तावेज);
 7. आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव. 9/भाग—2 का अनुलग्नक (आईएईए दस्तावेज);
 8. एस/2014/253;
 9. एस/2016/308;
 10. संकल्प 2321 (2016) का अनुलग्नक— III; और
 11. केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई मदें, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी जिनसे कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के परमाणु—संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी या अन्य व्यापक नर संहार संबंधी हथियारों के कार्यक्रमों में योगदान हो सकता है;
- (iv) संकल्प 2094 (2013) के अनुलग्नक— IV, संकल्प 2270 (2016) के अनुलग्नक— IV और संकल्प 2321 (2016) के अनुलग्नक— IV में विनिर्दिष्ट मदों सहित किन्तु इन्हीं मदों तक सीमित नहीं, विलासिता संबंधी माल;
- (v) खाद्य पदार्थ या दवाई को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित मदें जो कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के सशस्त्र बलों की प्रचालनात्मक क्षमताओं के विकास में योगदान दे सकती हैं। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 8(क) और (ख) में निर्धारित छूट के अधीन है।

आयात पर निषेध:

(ख) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क)(i), (क)(ii), (क)(iii), और (क)(iv) की मदों का कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष प्रापण या आयात, चाहे कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, निषिद्ध है।

क्षेत्रीय निषेध (निर्यात)

(ग) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य को निम्नलिखित मदों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या निर्यात निषिद्ध है:

- (i) मामला—दर—मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम में यथा अनुमोदित मामले को छोड़कर नए हेलीकॉप्टर और वेसल्स;
- (ii) वायुयान गैसोलीन, नाथ्वा प्रकार का जेट ईंधन, केरोसिन प्रकार का जेट ईंधन और केरोसिन—प्रकार के राकेट ईंधन सहित वायुयान ईंधन। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 31 और संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अधीन है;
- (iii) संघनन और प्राकृतिक गैस द्रव्य;

- (iv) परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 14 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (v) कच्चा तेल। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 15 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

क्षेत्रीय निषेध (आयात)

- (घ) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रापण या आयात निषिद्ध है:
- (i) कोयला, लोहा और लौह अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 8 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (ii) सोना, टाइटेनियम अयस्क, वेनेडियम अयस्क और पृथ्वी के दुर्लभ खनिज;
- (iii) तांबा, निकेल, चांदी और जस्ता;
- (iv) मामला—दर—मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम में यथा अनुमोदित को छोड़कर मूर्तियां; और
- (v) समुद्री खाद्य पदार्थ (मछली, क्रेस्टेशन, मोलस्क और सभी स्वरूप के अन्य जलीय अकशेरुकी सहित)। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 9 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (vi) सीसा और सीसा अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 10 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;
- (vii) वस्त्र (कपड़े और आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्ण परिधान उत्पाद सहित किन्तु उन तक सीमित नहीं)। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 16 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

व्याख्या:

- (क) यूएनएससी का अर्थ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है;
- (ख) आईईए का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है;
- (ग) समिति का अर्थ संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 के अनुसार स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति से है; और
- संकल्प, जैसा भी मामला हो, का संदर्भ कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य संबंधी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों यथा 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2231(2016), 2356(2017), 2371(2017) और 2375(2017) से है।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
ईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआरई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
ईओ	प्राधिकृत इकानामिक ऑपरेटर
ईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश

आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोगकर्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्य वर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र

सीजी	पूँजीगत माल
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	सम्पूर्णता खराब हुए
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता

सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	काउंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
डीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईईसी	इलेक्ट्रॉनिक आयातक-निर्यातक कोड
ईसीए	इलेक्ट्रॉनिक-सह-अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण

ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईजीएम	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एक्जिम	निर्यात आयात
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी(आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएण्डजेईपीसी	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय; मानक संगठन
आईईए	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईएमएससी	आंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय; मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	निर्यात और आयात मर्दों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	क्रेडिट का पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रेप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी

एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी
एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरपीए	स्मृति अदायगी क्षेत्र
एस/बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्गेनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत स्कीम से सेवा निर्यात
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम

एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार क्षेत्र
एसयूवी	स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	व्यापार सदन
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता क्रियाकलाप

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2017

No. 41/2015-2020

S.O. 3813 (E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the revised Foreign Trade Policy, 2015-2020. This Foreign Trade Policy shall come into force w.e.f. 5-12-2017.

Effect of this Notification : The revised and updated Foreign Trade Policy, 2015-2020, is hereby notified

[F. No. 01/94/180/332/AM15/PC4/Vol.II]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General

CHAPTER 1**LEGAL FRAMEWORK AND TRADE FACILITATION****A. LEGAL FRAMEWORK****1.00 Legal Basis of Foreign Trade Policy (FTP)**

The Foreign Trade Policy, 2015-20, (as updated) w.e.f. 05.12.2017 is notified by Central Government, in exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) [FT (D&R) Act], as amended.

1.01 Duration of FTP

The Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, (as updated) w.e.f. 05.12.2017 incorporating provisions relating to export and import of goods and services, shall come into force with effect from the date of notification and shall remain in force up to 31st March, 2020, unless otherwise specified. All exports and imports made upto the date of notification shall, accordingly, be governed by the relevant FTP, unless otherwise specified.

1.02 Amendment to FTP

Central Government, in exercise of powers conferred by Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, as amended from time to time, reserves the right to make any amendment to the FTP, by means of notification, in public interest.

1.03 Hand Book of Procedures (HBP) and Appendices & Aayat Niryat Forms (AANF)

Director General of Foreign Trade (DGFT) may, by means of a Public Notice, notify Hand Book of Procedures, including Appendices and Aayat Niryat Forms or amendment thereto, if any, laying down the procedure to be followed by an exporter or importer or by any Licensing/Regional Authority or by any other authority for purposes of implementing provisions of FT (D&R) Act, the Rules and the Orders made there under and provisions of FTP.

1.04 Specific provision to prevail over the general

Where a specific provision is spelt out in the FTP/Hand Book of Procedures (HBP), the same shall prevail over the general provision.

1.05 Transitional Arrangements

- (a) Any License / Authorisation / Certificate / Scrip / instrument bestowing financial or fiscal benefit issued before commencement of FTP, 2015-20 (as updated) w.e.f. 05.12.2017 shall continue to be valid for the purpose and duration for which it was issued, such License/Authorisation/ Certificate / Scrip / any instrument bestowing financial or fiscal benefit Authorisation was issued, unless otherwise stipulated.
- (b) In case an export or import that is permitted freely under FTP is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted, notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated. This is subject to the condition that the shipment of export or import is made within the original validity period of an irrevocable commercial letter of credit, established before the date of imposition of such restriction and it shall be restricted to the balance value and quantity available and time period of such irrevocable letter of credit. For operationalising such irrevocable letter

of credit, the applicant shall have to register the Letter of Credit with jurisdictional Regional Authority (RA) against computerized receipt, within 15 days of the imposition of any such restriction or regulation.

B. TRADE FACILITATION & EASE OF DOING BUSINESS

1.06 Objective

Trade facilitation is a priority of the Government for cutting down the transaction cost and time, thereby rendering Indian exports more competitive. The various provisions of FTP and measures taken by the Government in the direction of trade facilitation are consolidated under this chapter for the benefit of stakeholders of import and export trade.

1.07 DGFT as a facilitator of exports/imports

DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. Focus is on good governance, which depends on efficient, transparent and accountable delivery systems. In order to facilitate international trade, DGFT consults various Export Promotion Councils as well as Trade and Industry bodies from time to time.

1.08 Niryat Bandhu - Hand Holding Scheme for new export / import entrepreneurs

- (a) DGFT is implementing the Niryat Bandhu Scheme for mentoring new and potential exporter on the intricacies of foreign trade through counselling, training and outreach programmes.
- (b) Considering the strategic significance of small and medium scale enterprises in the manufacturing sector and in employment generation, 'MSME clusters' have been identified, based on the export potential of the product and the density of industries in the cluster, for focussed interventions to boost exports.
- (c) Outreach activities shall be organized in a structured way with the help of Export Promotion Councils as 'industry partners' and other willing 'knowledge partners' in academia and research community to achieve the objective of Niryat Bandhu Scheme. Further, in order to ensure optimum utilization of resources, efforts would be made to associate all the stakeholders, including Customs, ECGC, Banks and concerned Ministries.

1.09 Citizen's Charter

DGFT has in place a Citizen's Charter, giving time schedules for providing various services to clients. Time line for disposal of an Application is given in Para 9.10 of HBP.

1.10 Online Complaint Registration and Monitoring System

An EDI Help Desk is available to assist the exporters in filing online applications on the DGFT portal and resolving other EDI related issues. For assistance an email may be sent at dgftedi@nic.in or Toll Free number 1800111550 can be used. Help Desk facility is also operational at the 4 DGFT Zonal Offices (details at <http://dgft.gov.in>). An Online Complaint registration and monitoring system allows users to register complaint and receive status/ reply online (details are at <http://dgft.gov.in>).

1.11 Issue of e-IEC (Electronic-Importer Exporter Code)

- (a) Importer Exporter Code (IEC) is mandatory for export/import from/to India as detailed in paragraph 2.05 of this Policy. DGFT issues Importer Exporter Code in electronic form (e-IEC). For issuance of e-IEC an application can be made on DGFT (<http://dgft.gov.in>). Applicant can upload the documents and pay the requisite fee through Net banking. Applicant shall, however, submit the application duly signed digitally.
- (b) Processing of such applications by Regional Authority (RAs) of DGFT would be done online and a digitally signed e-IEC would normally be issued/ e-mailed to the applicant within 2 working days.
- (c) In case the application is incomplete or otherwise ineligible, the same shall be rejected and a Rejection letter/email (with reasons for rejection) would be sent to the applicant.
- (d) Application for issue of e-IEC can also be made from eBiz platform (<https://www.ebiz.gov.in>).

1.12 e-BRC

- (a) One prominent initiative in recent times has been the e-BRC (Electronic Bank Realisation Certificate) project and its successful implementation by DGFT. It has enabled DGFT to capture details of realisation of export proceeds directly from the Banks through secured electronic mode. This has facilitated the implementation of various export promotion schemes without any physical interface with the stake holders.
- (b) RBI has also developed a comprehensive IT-based system called Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) for monitoring of export of goods and software and facilitating AD banks to report various returns through a single platform.

1.13 MoU with State Governments for sharing of e-BRC data

MOU has been signed with 14 state governments for sharing of e-BRC data to facilitate refund of VAT/GST by the state government to exporters. MOU has also been signed with Enforcement Directorate, Agricultural Directorate, Agricultural Processed Food Products Export Development Authority and Goods & Services Tax Network (GSTN).

1.14 Exporter Importer Profile

An electronic procedure has been created to upload various documents in exporter importer profile. Once uploaded, there will be no need to submit these documents / copies of these documents to Regional Authority repeatedly with each application. It intends to reduce the transaction cost and time and is a step towards paperless processing of different applications in DGFT.

1.15 Reduction in mandatory documents required for Export and Import

The number of mandatory documents required for exports and imports of goods from/into India have been reduced to three each, as prescribed under paragraph 2.06 of FTP.

1.16 Facility of online filing of applications

All the Regional Authorities (RA) of DGFT and extension counters have been networked with high speed internet. The applications are received and processed electronically. DGFT under the EDI initiatives has provided the facility of on line filing of applications to obtain Importer Exporter Code and various Authorisations / scrip's. DGFT is one of the first digital signature enabled organisation of the Government of India (GOI), which has introduced a higher level of Encrypted 2048bit digital signature. There is a web interface for online filing of application after accessing DGFT website (<http://dgft.gov.in>). The application can be filed by exporter/CHA sitting at home or office in 24X7 environments. Application fee can also be paid online from linked banks or by using debit/credit card. The applications are signed with a digital signature and submitted electronically to the concerned Regional Authority of DGFT, which are then processed on computer by the Regional Authority and Authorisations/ scrip's are issued. Online filing of Application has minimized the physical interface with RA.

1.17 Online Inter-ministerial consultation

Presently, the exporters are required to file applications online on the website of DGFT under the Icon E-COM and are required to submit the duly signed and stamped printout of the online application along with all the necessary documents viz. technical specifications, literature etc. Now, a facility is being provided to upload copies of all the required documents including technical specifications, literature etc in PDF/JPG/JPEG/GIF format in the online filing system in respect of (a) Fixation of norms under Advance Authorisation by Norms Committees (b) Export of Restricted Items (c) Import of Restricted Items (d) SCOMET Items. The exporters would not be required to submit the hard copy of application except architectural drawings, machine drawings etc which may be difficult to scan and upload. The processing of the applications will also be done online.

1.18 Facility to upload documents by CA/ CS / Cost Accountant

In order to move towards paperless processing, an electronic procedure is being developed to upload digitally signed documents by Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant. To start with, this facility would be created for Export From India Schemes under Chapter 3. Such documents like Annexure Attached to ANF 3B, ANF 3C and ANF 3D, which are at present signed by these signatories, can be facilitated by this procedure. Exporter shall link digitally uploaded annexure with his online applications after creation of such facility. These facilities may be extended in phased manner to upload documents pertaining to other schemes like Advance Authorisation, DFIA and EPCG.

1.19 Electronic Data Interchange (EDI)

DGFT has put in place a robust EDI system for the purpose of export facilitation and good governance. DGFT has set up a secured EDI message exchange system for various documentation related activities including import and export Authorisations established with other administrative departments, namely, Customs, Banks and EPCs. This has reduced the physical interface of exporters and importers with the Government Departments and is a significant measure in the direction of reduction of transaction cost. The endeavour of DGFT has been to enlarge the scope of EDI to achieve higher level of integration with partner departments.

1.20 Message Exchange with Community partners

Customs, Banks, Export Promotion Councils (EPCs) are major community partners of DGFT for message exchange. An effective message exchange system is in place with various community partners which is as follows:

- (a) Message Exchange with Customs
 - (i) Importer Exporter Code Number.
 - (ii) Authorisations/Scrips for DFIA, AA, EPCG.
 - (iii) Shipping Bills for Duty Free Import Authorisation (DFIA), Advance Authorisation (AA), Export Promotion Capital Goods (EPCG), Reward Scrips.

- (b) Message Exchange with eBiz (<https://www.ebiz.gov.in>): Application for e-IEC.
- (c) Message Exchange with Banks
- (i) Application Fee
- (ii) electronic Bank Realisation Certificate (e-BRC) data
- (d) Message Exchange with EPCs
Registration cum Membership Certificate (RCMC) data.
- (e) Message exchange with GSTN and RBI.

1.21 Encouraging development of Third Party API

DGFT will encourage development of third party software for integration with its system to offer users multiple options for interfacing with the DGFT.

1.22 Forthcoming e-Governance Initiatives

DGFT is currently working on the following EDI initiatives:

- (i) Message exchange for transmission of Bills of Entry (import details) from Customs to DGFT.
- (ii) Online issuance of Export Obligation Discharge Certificate (EODC).
- (iii) Message exchange with Ministry of Corporate Affairs for CIN & DIN Information.
- (iv) Message exchange with CBDT for PAN.
- (v) Open API for submission of e-IEC Application.
- (vi) Mobile Applications for FTP.

1.23 Free passage of Export consignment

Consignments of items meant for exports shall not be withheld/ delayed for any reason by any agency of Central/ State Government. In case of any doubt, authorities concerned may ask for an undertaking from exporter and release such consignment.

1.24 No seizure of export related Stock

No seizure shall be made by any agency so as to disrupt manufacturing activity and delivery schedule of exports. In exceptional cases, concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence of serious irregularity. However, such seizure should be lifted within 7 days unless the irregularities are substantiated.

1.25 24 X 7 Customs clearance

CBEC introduced the facility of 24 X 7 customs clearance in the year 2012 for facilitated Bills of Entry and factory stuffed container and goods exported under free Shipping Bills. At present, this facility is available at 19 sea port and 17 air cargo complexes. The 24 X 7 Customs clearance facility has now been extended to all Bills of Entry (not only facilitated Bills of Entry) at 19 sea port and 17 Air Cargo Complexes. Further, no MOT charges are required to be collected in respect of the services provided by the Customs officers at 24 X 7 Customs Ports and Airports.

1.26 Single Window in Customs

Indian Customs has introduced SWIFT (Single Window Interface for Facilitating trade) w.e.f. 01.04.2016 for ensuring ease of doing business. Under SWIFT, the Importers electronically lodge Integrated Declaration at a single point only with Customs. The required permission, if any, from other regulatory agencies (such as Animal quarantine, Plant quarantine, Drug Controller, Textile Committee etc.) is obtained online without the importer/exporter having to separately approach these agencies. Benefits of Single Window Scheme include:

- a. Reduced Cost of doing business;
- b. Enhanced transparency;
- c. Reduced duplicity and cost of compliance;
- d. Optimal utilization of man power.

1.27 Self-Assessment of Customs Duty

- (a) Self-Assessment of Customs duty by importers or exporters was introduced vide Finance Act, 2011. The system is trust based. The objective is to expedite release of imported / export goods. The system operates on an electronic Risk Management System (RMS)

- (b) The Finance Act, 2017 has amended Section 47 of the Customs Act, 1962 to Authorize an importer to pay duty/tax/cess on the date of presentation of self-assessed Bill of Entry.

1.28 Authorised Economic Operator (AEO) Programme

- (a) Based upon WCO's SAFE Framework of Standards (FoS), 'Authorised Economic Operator (AEO) programme' has been developed by Indian Customs to enable business involved in the international trade to reap the following benefits:
- (i) Secure supply chain from point of export to import;
 - (ii) Ability to demonstrate compliance with security standards when contracting to supply overseas importers / exporters;
 - (iii) Enhanced border clearance privileges in Mutual Recognition Agreement (MRA) partner countries;
 - (iv) Minimal disruption to flow of cargo after a security related disruption;
 - (v) Reduction in dwell time and related costs; and
 - (vi) Customs advice / assistance if trade faces unexpected issues with Customs of countries with which India have MRA.
- (b) The AEO programmes have been implemented by other Customs administrations that give AEO status holders preferential Customs treatment in terms of reduced examination, faster clearances and other benefits. Thus, the AEO programme is expected to result in Mutual Recognition Agreements (MRA) with these Customs administrations. MRAs would ensure export goods get due Customs facilitation at the point of entry in the foreign country. Apart from securing supply chain, the benefits include reduction in dwell time and consequent cost of doing business. Indian Customs has signed MRA with Hong Kong Customs to recognise respective AEO Programmes to enable trade to get benefits on reciprocal basis. Indian Customs is also engaged in finalising MRA with other countries such as South Korea, Taiwan, USA etc.
- (c) As a step further towards trust based compliance, Indian Customs has introduced the new/revamped Authorised Economic Operator (AEO) Programme wherein extensive benefits, including greater facilitation and self-certification, have been provided to those entities who have demonstrated internal strong control system and compliance with CBEC.

1.29 Prior filing facility for Shipping Bills

To facilitate processing of shipping bills before actual shipment, prior online filing facility for shipping bills has been provided by the Customs - 7 days for air shipments & ICDs and 14 days for shipments by sea.

1.30 Cutting down delay in filing of Export General Manifest (EGM) for duty drawback

To facilitate quicker filing of EGMs and quicker rectification of EGM errors, there is a mechanism of monthly monitoring of EGMs by Chief Commissioners of Customs to ensure that facilitation does not lag on this account (Instruction No. 603/01/2011-DBK dated 31.07.2013).

1.31 Facility of Common Bond / LUT against Authorisations issued under different EP Schemes

CBEC Circular 11(A)/2011-Cus dated 25.02.2011 has provided the financial year-wise facility of executing common Bond/LUT against Advance Authorisation (AA)/Export Promotion Capital Goods (EPCG) Authorisation which is usable across all EDI ports/locations.

1.32 Exemption from Service Tax on Services received abroad

(Deleted)

1.33 Export of perishable agricultural Products

To reduce transaction and handling costs, a single window system to facilitate export of perishable agricultural produce has been introduced. The system will involve creation of multi-functional nodal agencies to be accredited by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi. The detailed procedure has been notified at Appendix 1C to Appendices & ANFs.

1.34 Time Release Study (TRS)

Customs Authority has decided to undertake 'Time Release Study' (TRS) as per WCO guidelines at major Customs locations on six monthly basis. WCO Time Release Study (TRS) is a unique tool and method for measuring the actual performance of Customs. The underlying objectives of Time Release Study are:

- (i) Identifying bottlenecks in the international supply chain / or constraints affecting Customs release.

- (ii) Establishing baseline trade facilitation performance measurement.

1.35 Towns of Export Excellence (TEE)

- (a) **Objective:** Development and growth of export production centres. A number of towns have emerged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximize their potential and enable them to move up the value chain and also to tap new markets.
- (b) Selected towns producing goods of Rs. 750 Crore or more may be notified as TEE based on potential for growth in exports. However, for TEE in Handloom, Handicraft, Agriculture and Fisheries sector, threshold limit would be Rs.150 Crore. The following facilities will be provided to such TEE's:
- (i) Recognized associations of units will be provided financial assistance under MAI scheme, on priority basis, for export promotion projects for marketing, capacity building and technological services.
- (ii) Common Service Providers in these areas shall be entitled for Authorisation under EPCG scheme.
- (c) Notified Towns (TEEs) are listed in Appendix 1 B of Appendices & ANFs.

1.36 DGCI&S, Kolkata as the provider of trade data

Director General of Commercial Intelligence and Statistics(DGCI&S) is an ISO certified organization under the administrative control of DGFT . It is the provider of trade data which is a source of guidance and direction for export & import trade and which help the exporters and importers formulate their trade strategy. Foreign trade data is disseminated by DGCI&S through (i) Monthly & Quarterly publications in CD form and (ii) Generation of data from the Foreign Trade database as per user's request. The DGCI&S has a Priced Information System (PIS) for disseminating data except for purely Central and State Governments and United Nations bodies. DGCI&S has put in place a Data Suppression Policy. The aim of this policy is to maintain confidentiality of importer's and exporter's commercially sensitive business data. Transaction level data would not be made publicly available to protect privacy. DGCI&S trade data shall be made available at aggregate level with a minimum possible time lag on commercial criteria. DGCI&S can be visited at <http://dgciskol.nic.in>.

1.37 Reducing/eliminating printout in Customs Clearance

With the aim of ease of doing business and promoting paperless clearance, CBEC has done away with routine print-outs of several documents including GAR 7 Forms/TR6 Challans, TP copy, Exchange Control copy of Bill of Entry and Shipping Bills and Export Promotion copy of Shipping Bill.

However, hard copy of EP copy of shipping Bill/ Bill of Entry may be provided on request only.

1.38 National Committee on Trade Facilitation (NCTF)

Consequent to India's ratification of the WTO Agreement on Trade Facilitation (TFA) in April 2016, the National Committee on Trade Facilitation (NCTF) has been constituted. The establishment of the Committee is part of mandatory, institutional arrangement of the TFA. This inter-ministerial body on trade facilitation will be chaired by the Cabinet Secretary. Its Secretariat will be housed within the Central Board of Excise and Customs (CBEC), in the Directorate General of Export Promotion, New Delhi. The defined objective behind setting up the NCTF is to have national level body that will facilitate domestic co-ordination and implementation of TFA provisions. It will play the lead role in developing the Pan-India road map for trade facilitation. It will be instrumental in synergizing the various trade facilitation perspectives across the country and will also focus on an outreach programmes for sensitization of all stakeholders about TFA.

1.39 e-mail initiatives

CBEC has initiated e-mail notification service to importers for information related to all important stages of import clearances.

1.40 Facility of deferred payment

As a trade facilitation measure, CBEC has introduced facility of deferred payment of customs duty. Further, Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016 have been notified and the same have come into effect from 16.11.2016. The importers certified under AEO Programme (Tier-two) and (Tier-Three) have been notified for availing the benefit of these Rules.

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

2.00 Objective

The general provisions governing import and export of goods and services are dealt with in this chapter.

2.01 Exports and Imports – ‘Free’, unless regulated

- (a) Exports and Imports shall be ‘Free’ except when regulated by way of ‘prohibition’, ‘restriction’ or ‘exclusive trading through State Trading Enterprises (STEs)’ as laid down in Indian Trade Classification (Harmonized System) [ITC (HS)] of Exports and Imports. The list of ‘Prohibited’, ‘Restricted’, and STE items can be viewed by clicking on ‘Downloads’ at <http://dgft.gov.in>
- (b) Further, there are some items which are ‘free’ for import/export, but subject to conditions stipulated in other Acts or in law for the time being in force.

2.02 Indian Trade Classification (Harmonised System) [ITC (HS)] of Exports and Imports.

- (a) ITC (HS) is a compilation of codes for all merchandise / goods for export/ import. Goods are classified based on their group or sub-group at 2/4/6/8 digits.
- (b) ITC (HS) is aligned at 6 digit level with international Harmonized System goods nomenclature maintained by World Customs Organization (<http://www.wcoomd.org>). However, India maintains national Harmonized System of goods at 8 digit level which may be viewed by clicking on ‘Downloads’ at <http://dgft.gov.in>
- (c) The import/export policies for all goods are indicated against each item in ITC (HS). Schedule 1 of ITC (HS) lays down the Import Policy regime while Schedule 2 of ITC (HS) details the Export Policy regime.
- (d) Except where it is clearly specified, Schedule 1 of ITC (HS), Import Policy is for new goods and not for the Second Hand goods. For Second Hand goods, the Import Policy regime is given in Para 2.31 in this FTP.

2.03 Compliance of Imports with Domestic Laws

- (a) Domestic Laws/ Rules/ Orders/ Regulations/ technical specifications/ environmental/safety and health norms applicable to domestically produced goods shall apply, mutatis mutandis, to imports, unless specifically exempted.
- (b) However, Goods to be utilized/ consumed in manufacture of export products, as notified by DGFT, may be exempted from domestic standards/ quality specifications.

2.04 Authority to specify Procedures

DGFT may, specify Procedures to be followed by an exporter or importer or by any licensing/Regional Authority (RA) or by any other authority for purposes of implementing provisions of FT (D&R) Act, the Rules and the Orders made there under and FTP. Such procedures, or amendments if any, shall be published by means of a Public Notice.

Importer-Exporter Code/e-IEC**2.05 Importer-Exporter Code (IEC)**

- (I) An IEC is a 10-character alpha-numeric number allotted to a person that is mandatory for undertaking any export/import activities. With a view to maintain the unique identity of an entity (firm/company/LLP etc.), consequent upon introduction / implementation of GST, IEC will be equal to PAN and will be separately issued by DGFT based on an application.
- (a) Application for obtaining IEC may be filed online in ANF 2A with applicable fees and submitted with digital signature.
- (b) When an e-IEC is approved by the competent authority, applicant is informed through e-mail that a computer generated e-IEC is available on the DGFT website. By clicking on “Application Status” after having filled and submitted the requisite details in “Online IEC Application” webpage, applicant can view and print his e-IEC.
- (c) The applicant may submit online application with the following details /documents (scanned copies to be submitted/ uploaded) along with the IEC application:
 - (i) Digital photograph of the signatory applicant;
 - (ii) Copy of the PAN card of the business entity in whose name Import/Export would be done (Applicant individual in case of Proprietorship firms);
 - (iii) Cancelled cheque bearing entity’s pre-printed name or Bank certificate in prescribed format ANF-2A(I)
- (d) For modification in IEC, applicants may submit online application through digital signature (Class-II or Class-III), by paying applicable fees and uploading requisite documents, corresponding to the changes sought.
- (e) Detailed guidelines for applying for e-IEC is available at http://dgft.gov.in/exim/2000/iec_anf/iecanf.htm
- (II) No Export/Import without IEC:

- (i) No export or import shall be made by any person without obtaining an IEC number unless specifically exempted.
- (ii) Exempt categories and corresponding permanent IEC numbers are given in Para 2.07 of Handbook of Procedures.

2.06 Mandatory documents for export/import of goods from/into India:

- (a) Mandatory documents required for export of goods from India:
 1. Bill of Lading/ Airway Bill/ Lorry Receipt/ Railway Receipt/Postal Receipt
 2. Commercial Invoice cum Packing List*
 3. Shipping Bill/Bill of Export/ Postal Bill of Export
- (b) Mandatory documents required for import of goods into India
 1. Bill of Lading/Airway Bill/Lorry Receipt/ Railway Receipt/Postal Receipt in form CN-22 or CN 23 as the case may be.
 2. Commercial Invoice cum Packing List*
 3. Bill of Entry

[Note: *(i) As per CBEC Circulars issued under the Customs Act, 1962

(ii) Separate Commercial Invoice and Packing List would also be accepted.]

- (c) For export or import of specific goods or category of goods, which are subject to any restrictions/policy conditions or require NOC or product specific compliances under any statute, the regulatory authority concerned may notify additional documents for purposes of export or import.
- (d) In specific cases of export or import, the regulatory authority concerned may electronically or in writing seek additional documents or information, as deemed necessary to ensure legal compliance.
- (e) The above stipulations are effective from 1st April, 2015.

2.07 Principles of Restrictions

DGFT may, through a Notification, impose restrictions on export and import, necessary for: -

- (a) Protection of public morals;
- (b) Protection of human, animal or plant life or health;
- (c) Protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
- (d) Prevention of use of prison labour;
- (e) Protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- (f) Conservation of exhaustible natural resources;
- (g) Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived;
- (h) Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war
- (i) Relating to the importation or exportation of gold or silver.

2.08 Export/Import of Restricted Goods/Services

Any goods /service, the export or import of which is 'Restricted' may be exported or imported only in accordance with an Authorisation / Permission or in accordance with the Procedures prescribed in a Notification / Public Notice issued in this regard.

2.09 Export of SCOMET Items

Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET), as indicated in Appendix-3 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items, shall be governed by the specific provisions of (i) Chapter IV A of the FT(D&R) Act, 1992 as amended from time to time (ii) Sl. No. 4 & 5 of Table A and Appendix-3 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items (iii) Para 2.16, Para 2.17, Para 2.18 of FTP and (iv) Para 2.73 -2.82 of Hand Book of Procedures; in addition to the other provisions of FTP and Handbook of Procedures governing export Authorisations.

2.10 Actual User Condition

Goods which are importable freely without any 'Restriction' may be imported by any person. However, if such imports require an Authorisation, actual user alone may import such good(s) unless actual user condition is specifically dispensed with by DGFT.

2.11 Terms and Conditions of an Authorisation

Every Authorisation shall, inter alia, include either all or some of the following terms and conditions (as applicable in terms of the Para under which the Authorisation has been issued), in addition to such other conditions as may be specified:

- (a) Description, quantity and value of goods;

- (b) Actual User condition (as defined in Chapter 9);
- (c) Export Obligation;
- (d) Minimum Value addition to be achieved;
- (e) Minimum export/import price;
- (f) Bank guarantee/ Legal undertaking / Bond with Customs Authority/RA (as in para 2. 35 of FTP).
- (g) Validity period of import/export as specified in Handbook of Procedures.

2.12 Application Fee

Application for IEC/ Authorisation / License / Scrips must be accompanied by application fees as indicated in the **Appendix 2K** of Appendices and Aayat Niryat Forms. Fees must be paid online through electronic fund transfer (EFT) mechanism or through Credit/Debit Cards, unless provided otherwise.

2.13 Clearance of Goods from Customs against Authorisation

Goods already imported / shipped / arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against an Authorisation issued subsequently. However, such goods already imported/shipped/arrived, in advance are first warehoused against Bill of Entry for Warehousing and then cleared for home consumption against an Authorisation issued subsequently. This facility will however be not available to “restricted” items or items traded through STEs.

2.14 Authorisation - not a Right

No person can claim an Authorisation as a right and DGFT or RA shall have power to refuse to grant or renew the same in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules made there under and FTP.

2.15 Penal action and placing of an entity in Denied Entity List (DEL)

- a) If an Authorisation holder violates any condition of such Authorisation or fails to fulfill export obligation, or fails to deposit the requisite amount within the period specified in demand notice issued by Department of Revenue and /or DGFT, he shall be liable for action in accordance with FT (D&R) Act, the Rules and Orders made there under, FTP and any other law for time being in force.
- b) With a view to raising ethical standards and for ease of doing business, DGFT has provided for self certification system under various schemes. In such cases, applicants shall undertake self certification with sufficient care and caution in filling up information/particulars. Any information/particulars subsequently found untrue/incorrect will be liable for action under FTDR Act, 1992 and Rules therein in addition to penal action under any other Act/Order.
- c) A firm may be placed under Denied Entity List (DEL), by the concerned RA, under the provision of Rule 7 of Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993. On issuance of such an order, for reasons to be recorded in writing, a firm may be refused grant or renewal of a license, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits. If a firm is placed under DEL all new licences, scrips, certificates, instruments etc will be blocked from printing/ issue/renewal.
- d) DEL orders may be placed in abeyance, for reasons to be recorded in writing by the concerned RA. DEL order can be placed in abeyance, for a period not more than 60 days at a time.
- e) A firm's name can be removed from DEL, by the concerned RA for reasons to be recorded in writing, if the firm completes Export Obligation/ pays penalty/ fulfils requirement of Demand Notice(s) issued by the RA/submits documents required by the RA.

Prohibitions (Country, Organisations, Groups, Individuals etc. and Product Specific):

2.16 Prohibition on Import and Export of ‘Arms and related material’ from / to Iraq

Notwithstanding the policy on Arms and related materials in Chapter 93 of ITC(HS), the import/export of Arms and related material from/to Iraq is ‘Prohibited’. However, export of Arms and related material to Government of Iraq shall be permitted subject to ‘No Objection Certificate’ from the Department of Defence Production.

2.16 A Prohibition on Trade with the Islamic State in Iraq and the Levant [ISIL, also known as Daesh], Al Nusrat Front [ANF] and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al Qaida.

In compliance with United Nations Security Council Resolution No. 2199 [2015] (full text of the Resolution is available at <http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm>), trade in oil and refined oil products, modular refineries and related materials, besides items of cultural (including antiquities), scientific and religious importance is prohibited with the Islamic State in Iraq and the Levant [ISIL], Al Nusrat Front [ANF] and other individuals, groups, undertakings and entities associated, directly or indirectly, with Al Qaida.

2.17 Prohibition on direct or indirect import and export from/to DPRK

Direct or Indirect export and import of items, whether or not originating in Democratic People's Republic of Korea (DPRK) to/from DPRK is detailed in Appendix – I of FTP.

2.18 Direct or Indirect Export/Import to/from Iran

- (a) Direct or indirect export to Iran or import from Iran of any item, material, equipment, goods and technology mentioned in the following documents would be permitted subject to the provisions contained in Annex-B to the United Nations Security Council Resolution 2231 (2015):
 - (i) Items listed in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 and INFCIRC /254/Rev.7 /Part 2 (IAEA Documents) as updated by the IAEA from time to time.
 - (ii) Items listed in S/2006/263 (UN Security Council document) as updated by the Security Council from time to time.
- (b) All the UN Security Council Resolutions/Documents and IAEA Documents referred to above are available on the UN Security Council website (www.un.org/Docs/sc) and IAEA website (www.iaea.org).

2.19 Prohibition on Import of Charcoal from Somalia

Direct or indirect import of charcoal is prohibited from Somalia, irrespective of whether or not such charcoal has originated in Somalia [United Nations Security Council Resolution 2036 (2012)]. Importers of Charcoal shall submit a declaration to Customs that the consignment has not originated in Somalia.

Import / Export through State Trading Enterprises:**2.20 State Trading Enterprises (STEs)**

- (a) State Trading Enterprises (STEs) are governmental and non-governmental enterprises, including marketing boards, which deal with goods for export and /or import. Any good, import or export of which is governed through exclusive or special privilege granted to State Trading Enterprise (STE), may be imported or exported by the concerned STE as per conditions specified in ITC (HS). The list of STEs notified by DGFT is in Appendix-2J.
- (b) Such STE(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale in a non discriminatory manner and shall afford enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.
- (c) DGFT may, however, grant an authorisation to any other person to import or export any of the goods notified for exclusive trading through STEs.

Trade with Specific Countries:**2.21 Trade with Neighbouring Countries**

DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighboring countries.

2.22 Transit Facility

Transit of goods through India from/ or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with bilateral treaties between India and those countries and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions.

2.23 Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement

In case of trade with Russia under Debt Repayment Agreement, DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required, and anything contained in FTP, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.

Import of Specific Categories of Goods:**2.24 Import of Samples**

Import of samples shall be governed by Para 2.65 of Handbook of Procedures.

2.25 Import of Gifts

Import of gifts shall be 'free' where such goods are otherwise freely importable under ITC (HS). In other cases, such imports shall be permitted against an Authorisation issued by DGFT.

2.26 Passenger Baggage

- (a) Bona-fide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per limits, terms and conditions thereof in Baggage Rules notified by Ministry of Finance.
- (b) Samples of such items that are otherwise freely importable under FTP may also be imported as part of passenger baggage without an Authorisation.
- (c) Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without an Authorisation.

2.27 Re – import of goods repaired abroad

Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and re-imported without an Authorisation.

2.28 Import of goods used in projects abroad

Project contractors after completion of projects abroad, may import without an Authorisation, goods including capital goods used in the project, provided they have been used for at least one year.

2.29 Import of Prototypes

Import of new / second hand prototypes / second hand samples may be allowed on payment of duty without an Authorisation to an Actual User (industrial) engaged in production of or having industrial license / letter of intent for research in item for which prototype is sought for product development or research, as the case may be, upon a self- declaration to that effect, to satisfaction of customs authorities

2.30 Import through courier service/Post

Imports through a registered courier service or post are permitted as per Notification(s) issued under the Customs Act, 1962. However, importability of such items shall be regulated in accordance with FTP/ ITC (HS), 2017.

Import Policy for Second Hand Goods:**2.31 Second Hand Goods**

S.No.	Categories of Second Hand Goods	Import Policy	Conditions, if any
I	Second Hand Capital Goods		
(a)	i. Personal computers/ laptops including their refurbished/ re-conditioned spares ii. Photocopier machines/ Digital multifunction Print & Copying Machines iii. Air conditioners iv. Diesel generating sets.	Restricted	Importable against Authorisation
(b)	Refurbished / re-conditioned spares of Capital Goods	Free	Subject to production of Chartered Engineer certificate to the effect that such spares have at least 80% residual life of original spare.
(c)	All other second hand capital goods {other than	Free	

	(a) & (b) above}		
II	Second Hand Goods other than capital goods	Restricted	Importable against Authorisation

Import Policy for Metallic Waste and Scraps:

2.32 Import of Metallic waste and Scrap

- (a) Import of any form of metallic waste, scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste/scrap containing radioactive material, any types of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise as detailed in Para 2.54 of Handbook of Procedures.
- (b) The types of metallic waste and scrap which can be imported freely, and the Procedures of import in the shredded form; unshredded compressed and loose form is laid down in Para 2.54 of Handbook of Procedures.

2.33 Removal of Scrap/waste from SEZ

A SEZ unit/Developer/ Co-developer may be allowed to dispose of in DTA any waste or scrap, including any form of metallic waste and scrap, generated during manufacturing or processing activity, without an Authorisation, on payment of applicable Customs Duty.

Other Provisions Related to Imports:

2.34 Import under Lease Financing

No specific permission of RA is required for lease financed capital goods.

2.35 Execution of Legal Undertaking (LUT) / Bank Guarantee (BG)

- (a) Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, importer shall execute, Legal Undertaking (LUT) / Bank Guarantee (BG) / Bond with the Customs Authority, as prescribed, before clearance of goods.
- (b) In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish LUT/BG/Bond to RA concerned before sourcing material from indigenous supplier/nominated agency as prescribed in Chapter 2 of Handbook of Procedures.

2.36 Private/Public Bonded Warehouses for Imports

- (a) Private/ Public bonded warehouses may be set up in DTA as per rules, regulations and notifications issued under the Customs Act, 1962. Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such bonded warehouses.
- (b) Such goods may be cleared for home consumption in accordance with provisions of FTP and against Authorisation, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.
- (c) The clearance of the warehoused goods shall be as per the provisions of the Customs Act, 1962.

2.37 Special provision for Hides Skins and semi-finished goods

Hides, Skins and semi-finished leather may be imported in the Public/ Private Bonded warehouse for the purpose of DTA sale and the unsold items thereof can be re-exported from such bonded warehouses on payment of the applicable rate of export duty.

2.38 Sale on High Seas

Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to FTP or any other law in force.

Exports:

2.39 Free Exports

All goods may be exported without any restriction except to the extent that such exports are regulated by ITC (HS) or any other provision of FTP or any other law for the time being in force. DGFT may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in ITC (HS), may be exported without an Authorisation.

2.40 Deleted

2.41 Benefits for Supporting Manufacturers

For any benefit to accrue to the supporting manufacturer (as defined in Para 9.58 of FTP), the names of both supporting manufacturer as well as the merchant exporter must figure in the concerned export documents, especially in ARE-1 / ARE-3 / Shipping Bill / Bill of Export/ Airway Bill.

2.42 Third Party Exports

Third party exports (except Deemed Export) as defined in Chapter 9 shall be allowed under FTP. In such cases, export documents such as shipping bill shall indicate name of both manufacturing exporter/manufacturer and third party exporter(s). Bank Realization Certificate (BRC), Export Order and Invoice should be in the name of third party exporter.

Exports of Specific Categories:

2.43 Export of Samples

Export of Samples and Free of charge goods shall be governed by provisions given in Para 2.66 of Handbook of Procedures.

2.44 Export of Gifts

Goods including edible items, of value not exceeding Rs.5,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift. However, items mentioned as restricted for exports in ITC (HS) shall not be exported as a gift, without an Authorisation.

2.45 Export of Passenger Baggage

- (a) Bona-fide personal baggage may be exported either along with passenger or, if unaccompanied, within one year before or after passenger's departure from India. However, items mentioned as restricted in ITC (HS) shall require an Authorisation. Government of India officials proceeding abroad on official postings shall, however, be permitted to carry along with their personal baggage, food items (free, restricted or prohibited) strictly for their personal consumption. The Provisions of the Para shall be subject to Baggage Rules issued under Customs Act, 1962.
- (b) Samples of such items that are otherwise freely exportable under FTP may also be exported as part of passenger baggage without an Authorisation.

2.46 Import for export

- I. (a) Goods imported, in accordance with FTP, may be exported in same or substantially the same form without an Authorisation provided that item to be imported or exported is not in the restricted for import or export in ITC (HS).
- (b) Goods, including capital goods (both new and second hand), may be imported for export provided:
 - i. Importer clears goods under Customs Bond;
 - ii. Goods are freely exportable, i.e., are not "Restricted"/ "Prohibited"/ subject to "exclusive trading through State Trading Enterprises" or any conditionality/ requirement as may be required under Schedule 2 – Export Policy of the ITC (HS);
 - iii. Export is against freely convertible currency.
- (c) Goods in (b) above will include 'Restricted' goods for import (except 'Prohibited' items).
- (d) Capital goods, which are freely importable and freely exportable, may be imported for export on execution of LUT/BG with Customs Authority.
- (e) Notwithstanding the above, goods which are freely importable may be re-exported except items as in the Prohibited or SCOMET List of exports, in same or substantially same form even though such goods are under "restricted list" for export, subject to the following conditions:
 - (i) Goods are not of Indian Origin;
 - (ii) Goods imported shall be kept in bonded warehouse under supervision of Customs;
 - (iii) Goods to be exported have never been cleared for home consumption;
 - (iv) Export of goods shall be subjected to Section 69 of Customs Act, 1962.
- II. (a) Goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted for export only against payment in freely convertible currency, unless otherwise notified by DGFT.
- (b) Export of such goods to the notified countries (presently only Iran) would be permitted against payment in Indian Rupees, subject to minimum 15% value addition.
- (c) However, re-export of food, medicine and medical equipments, namely, items covered under ITC(HS) Chapters 2 to 4, 7 to 11, 15 to 21, 23, 30 and items under headings 9018, 9019, 9020, 9021 & 9022 of Chapter-90 of ITC(HS) will not be subject to minimum value addition requirement for export to Iran. Exports of these items to Iran shall, however, be subject to all other conditions of FTP 2015-20 and ITC (HS) 2017, as applicable. Bird's eggs covered

under ITC (HS) 0407 & 0408 and Rice covered under ITC (HS) 1006 are not covered under this dispensation, as at II (a) above.

- (d) Exports under this dispensation, as at I (e) and II (a), (b) and (c) above shall not be eligible for any export incentives.

2.47 Export through Courier Service/Post

Exports through a registered courier service is permitted as per Notification issued by DoR. However, exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP/ ITC (HS), 2017.

2.48 Export of Replacement Goods

Goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed for export by Customs authorities, provided that replacement goods are not mentioned as restricted/SCOMET items for exports in ITC (HS). If the export item is 'restricted'/ under SCOMET, the exporter shall require a export license for replacement.

2.49 Export of Repaired Goods

Goods or parts thereof, except restricted under ITC (HS), on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export. Such goods shall be allowed clearance without an Authorisation and in accordance with customs notification. To that extent the exporter shall return the benefits /incentive availed on the returned goods. If the item is 'restricted' for import, the exporter shall require an import license.

However, re-export of such defective parts/spares by the Companies/firms and Original Equipment Manufacturers shall not be mandatory if they are imported exclusively for undertaking root cause analysis, testing and evaluation purpose."

2.50 Export of Spares

Warranty spares (whether indigenous or imported) of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods [except those restricted under ITC (HS)] may be exported along with main equipment or subsequently but within contracted warranty period of such goods, subject to approval of RBI.

2.50A Re-export of imported Goods found defective and unsuitable for use:

Imported goods found defective after Customs clearance, or not found as per specifications or requirements may be re-exported back as per Customs Act, 1962.

2.51 Private Bonded Warehouses for Exports

- (a) Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per terms and conditions of notifications issued by DoR.
- (b) Such warehouses shall be entitled to procure goods from domestic manufacturers without payment of duty. Supplies made by a domestic supplier to such notified warehouses shall be treated as physical exports provided payments are made in free foreign exchange.

Payments and Receipts on Imports / Exports:

2.52 Denomination of Export Contracts

- (a) All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but export proceeds shall be realized in freely convertible currency.
- (b) However, export proceeds against specific exports may also be realized in rupees, provided it is through a freely convertible Vostro account of a non resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union (ACU) or Nepal or Bhutan. Additionally, rupee payment through Vostro account must be against payment in free foreign currency by buyer in his non- resident bank account. Free foreign exchange remitted by buyer to his non-resident bank (after deducting bank service charges) on account of this transaction would be taken as export realization under export promotion schemes of FTP.
- (c) Contracts (for which payments are received through Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar. However, participants in the ACU may settle their transactions in ACU Dollar or in ACU Euro as per RBI Notifications. Central Government may relax provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank/Government of India line of credit.

2.53 Export to Iran –Realisations in Indian Rupees to be eligible for FTP benefits / incentives

Notwithstanding the provisions contained in para 2.52 (a) above, export proceeds realized in Indian Rupees against exports to Iran are permitted to avail exports benefits / incentives under the Foreign Trade Policy (2015-20), at par with export proceeds realized in freely convertible currency.

2.54 Non-Realisation of Export Proceeds

(a) If an exporter fails to realize export proceeds within time specified by RBI, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law in force, be liable to return all benefits / incentives availed against such exports and action in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under and FTP.

(b) In case an Exporter is unable to realize the export proceeds for reasons beyond his control (force-majeure), he may approach RBI for writing off the unrealised amount as laid down in Para 2.87 of Handbook of Procedures.

(c) The payment realized through insurance cover, would be eligible for benefits under FTP as per Procedures laid down in Para 2.85 of Handbook of Procedures.

2.54A Export Credit Agencies (ECAs)

(i) Export Credit Agencies (ECAs) are policy instrument for Government to support exports. ECAs support exports by insurance, guarantee and also direct lending. Export Credit Agencies (ECAs) like Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) provides credit insurance support to exports and export credit lending. Covers issued by ECGC to exporters, protect against losses arising out of payment failures due to insolvency or default of the buyers or due to political risks. Exporters can diversify their markets in addition to protecting existing markets through such covers. ECGC also supports Medium and Long term (MLT) exports including project exports. Exim Bank is the other ECA in the business of lending for MLT exports and fronting the government's line of credit.

(ii) ECGC indemnifies losses of exporters in export trade due to insolvency or default of the buyer. Additionally losses due to political risk like war, sudden import restriction, promulgation of law or decree after the shipment has been effected are also covered. Some of the anti-dumping measures or non-tariff barriers introduced after a shipment has been made will come under the purview of the political risk. In such cases exporter's interest are protected by ECGC.

Export Promotion Councils:**2.55 Recognition of EPCs to function as Registering Authority for issue of RCMC**

(a) Export Promotion Councils (EPCs) are organizations of exporters, set up with the objective to promote and develop Indian exports. Each Council is responsible for promotion of a particular group of products/ projects/services as given in Appendix 2T of AANF.

(b) EPCs are also eligible to function as Registering Authorities to issue Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) to its members. The criteria for EPCs to be recognized as Registering Authorities for issue of RCMC to its members are detailed in Para 2.92 of the Handbook of Procedures.

2.56 Registration-cum-Membership Certificate (RCMC)

Any person, applying for:

(a) An Authorisation to import/export (except items) listed as 'Restricted' items in ITC (HS)

Or

(b) Any other benefit or concession under FTP shall be required to furnish or upload on DGFT's website in the Importer Exporter Profile, the RCMC granted by competent authority in accordance with Procedures specified in Handbook of Procedures unless specifically exempted under FTP. Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) issued by Spices Board and Certificate of Registration as Exporter of coir & coir products issued by the Coir Board shall be treated as Registration-Cum-Membership Certificate (RCMC) for the purposes under this Policy.

Policy Interpretation and Relaxations:**2.57 Interpretation of Policy**

(a) The decision of DGFT shall be final and binding on all matters relating to interpretation of Policy, or provision in Handbook of Procedures, Appendices and Aayat Niryat Forms or classification of any item for import / export in the ITC (HS).

- (b) A Policy Interpretation Committee (PIC) may be constituted to aid and advice DGFT. The composition of the PIC would be as follows:
- (i) DGFT: Chairman
 - (ii) All Additional DGFTs in Headquarters: Members
 - (iii) All Joint DGFTs in Headquarters looking after Policy matters: Members
 - (iv) Joint DGFT (PRC/PIC): Member Secretary
 - (v) Any other person / representative of the concerned Ministry / Department, to be co-opted by the Chairman.

2.58 Exemption from Policy/Procedures

DGFT may in public interest pass such orders or grant such exemption, relaxation or relief, as he may deem fit and proper, on grounds of genuine hardship and adverse impact on trade to any person or class or category of persons from any provision of FTP or any Procedures. While granting such exemption, DGFT may impose such conditions as he may deem fit after consulting the Committees as under:

Sl. No.	Description	Committee
(a)	Fixation / modification of product norms	Norms Committees
(b)	Nexus with Capital Goods (CG) and benefits under EPCG Schemes	EPCG Committee
(c)	All other issues	Policy Relaxation Committee (PRC)

2.59 Personal Hearing by DGFT for Grievance Redressal

- (a) Government is committed to easy and speedy redressal of grievances from Trade and Industry. Paragraph 2.58 of FTP provides for relaxation of Policy and Procedures on grounds of genuine hardship and adverse impact on trade. If an importer/exporter is aggrieved by any decision taken by Policy Relaxation Committee (PRC), or a decision/order by any authority in the Directorate General of Foreign Trade, a specific request for Personal Hearing (PH) along with the prescribed application fee as per Appendix-2K has to be made to DGFT. DGFT may consider request for relaxation after consulting concerned Norms Committee, EPCG Committee or Policy Relaxation Committee (PRC) and the decision conveyed in pursuance to the personal hearing shall be final and binding.
- (b) The opportunity for Personal Hearing will not apply to a decision/order made in any proceeding, including an adjudication proceeding, whether at the original stage or at the appellate stage, under the relevant provisions of FT (D&R) Act, 1992, as amended from time to time.

2.60 Regularization of EO default and settlement of Customs duty and interest through Settlement Commission

With a view to providing assistance to firms who have defaulted under FTP for reasons beyond their control as also facilitating merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been decided to empower Settlement Commission in Department of Revenue to decide such cases also with effect from 01.04.2005.

Self Certification of Originating Goods:

2.61 Approved Exporter Scheme for Self Certification of Certificate of Origin.

- (i) Currently, Certificates of Origin under various Preferential Trade Agreements [PTA], Free Trade Agreements [FTAs], Comprehensive Economic Cooperation Agreements [CECA] and Comprehensive Economic Partnerships Agreements [CEPA] are issued by designated agencies as per Appendix 2B of Appendices and Aayat and Niryat Forms. A new optional system of self certification is being introduced with a view to reducing transaction cost.

- (ii) The Manufacturers who are also Status Holders shall be eligible for Approved Exporter Scheme. Approved Exporters will be entitled to self-certify their manufactured goods as originating from India with a view to qualifying for preferential treatment under different PTAs/FTAs/ CECAs/CEPAs which are in operation. Self-certification will be permitted only for the goods that are manufactured as per the Industrial Entrepreneurs Memorandum (IEM) / Industrial License (IL) /Letter of Intent (LOI) issued to manufacturers.
- (iii) Status Holders will be recognized by DGFT as Approved Exporters for self-certification based on availability of required infrastructure, capacity and trained manpower as per the details in Para 2.109 of Handbook of Procedures 2015-20 read with Appendix 2F of Appendices & Aayaat Niryat Forms.
- (iv) The details of the Scheme, along with the penalty provisions, are provided in Appendix 2F of Appendices and Aayaat Niryat Forms and will come into effect only when India incorporates the scheme into a specific agreement with its partner/s and the same is appropriately notified by DGFT.

2.62 Certification of Origin of Goods EU-GSP

Exporters can self-certify the Statement on Origin of their goods, as per the self-certification scheme , Certification of Origin of Goods for European Union Generalised System of Preferences (EU-GSP) , of the European Union (EU) under the Registered Exporter System (REX) as in Para 2.104 (c) of the Handbook of Procedures.

CHAPTER 3

EXPORTS FROM INDIA SCHEMES

3.00 Objective

The objective of schemes under this chapter is to provide rewards to exporters to offset infrastructural inefficiencies and associated costs.

3.01 Exports from India Schemes

There shall be following two schemes for exports of Merchandise and Services respectively:

- (i) Merchandise Exports from India Scheme (MEIS).
- (ii) Service Exports from India Scheme (SEIS).

3.02 Nature of Rewards

Duty Credit Scrips shall be granted as rewards under MEIS and SEIS. The Duty Credit Scrips and goods imported / domestically procured against them shall be freely transferable. The Duty Credit Scrips can be used for :

- (i) Payment of Basic Customs Duty and Additional Customs Duty specified under sections 3 (1), 3 (3) and 3 (5) of the Customs Tariff Act, 1975 for import of inputs or goods, including capital goods, as per DoR Notification, except items listed in Appendix 3A.
- (ii) Payment of Central excise duties on domestic procurement of inputs or goods,
- (iii) Deleted
- (iv) Payment of Basic Customs Duty and Additional Customs Duty specified under Sections 3 (1), 3 (3) and 3 (5) of the Customs Tariff Act, 1975 and fee as per paragraph 3.18 of this Policy.

Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)

3.03 Objective

Objective of the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) is to promote the manufacture and export of notified goods/ products.

3.04 Entitlement under MEIS

Exports of notified goods/products with ITC[HS] code, to notified markets as listed in Appendix 3B, shall be rewarded under MEIS. Appendix 3B also lists the rate(s) of rewards on various notified products [ITC (HS) code wise]. The basis of calculation of reward would be on realised FOB value of exports in free foreign exchange, or on FOB value of exports as given in the Shipping Bills in freely convertible foreign currencies, whichever is less, unless otherwise specified.

3.05 Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

- (i) Exports of goods through courier or foreign post office using e-commerce, as notified in Appendix 3C, of FOB value upto Rs. 25000 per consignment shall be entitled for rewards under MEIS.

- (ii) If the value of exports using e-commerce platform is more than Rs 25000 per consignment then MEIS reward would be limited to FOB value of Rs.25000 only.
- (iii) Such goods can be exported in manual mode through Foreign Post Offices at New Delhi, Mumbai and Chennai.
- (iv) Export of such goods under Courier Regulations shall be allowed manually on pilot basis through Airports at Delhi, Mumbai and Chennai as per appropriate amendments in regulations to be made by Department of Revenue. Department of Revenue shall fast track the implementation of EDI mode at courier terminals.

3.06 Ineligible categories under MEIS

The following exports categories /sectors shall be ineligible for Duty Credit Scrip entitlement under MEIS

- (i) Supplies made from DTA units to SEZ units
- (ii) Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of FTP;
- (iii) Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country but trans-shipped through India;
- (iv) Deemed Exports;
- (v) SEZ/ EOU /EHTP/ BTP /FTWZ products exported through DTA units;
- (vi) Export products which are subject to Minimum export price or export duty.
- (vii) Exports made by units in FTWZ.

Service Exports from India Scheme (SEIS)

3.07 Objective

Objective of Service Exports from India Scheme (SEIS) is to encourage and maximize export of notified Services from India.

3.08 Eligibility

- (a) Service Providers of notified services, located in India, shall be rewarded under SEIS. Only Services rendered in the manner as per Para 9.51(i) and Para 9.51(ii) of this policy shall be eligible. The notified services and rates of rewards are listed in Appendix 3D.
- (b) Such service provider should have minimum net free foreign exchange earnings of US\$15,000 in preceding financial year to be eligible for Duty Credit Scrip. For Individual Service Providers and sole proprietorship, such minimum net free foreign exchange earnings criteria would be US\$10,000 in preceding financial year.
- (c) Payment in Indian Rupees for service charges earned on specified services, shall be treated as receipt in deemed foreign exchange as per guidelines of Reserve Bank of India. The list of such services is indicated in Appendix 3E.
- (d) Net Foreign exchange earnings for the scheme are defined as under:
 Net Foreign Exchange = Gross Earnings of Foreign Exchange minus Total expenses / payment / remittances of Foreign Exchange by the IEC holder, relating to service sector in the Financial year.
- (e) If the IEC holder is a manufacturer of goods as well as service provider, then the foreign exchange earnings and Total expenses / payment / remittances shall be taken into account for service sector only
- (f) In order to claim reward under the scheme, Service provider shall have to have an active IEC at the time of rendering such services for which rewards are claimed.

3.09 Ineligible categories under SEIS

Foreign exchange remittances other than those earned for rendering of notified services would not be counted for entitlement. Thus, other sources of foreign exchange earnings such as equity or debt participation, donations, receipts of repayment of loans etc. and any other inflow of foreign exchange, unrelated to rendering of service, would be ineligible.

3.10 Entitlement under SEIS

Service Providers of eligible services shall be entitled to Duty Credit Scrip at notified rates (as given in Appendix 3D) on net foreign exchange earned.

3.11 Remittances through Credit Card and other instruments for MEIS and SEIS

Free Foreign Exchange earned through international credit cards and other instruments, as permitted by RBI shall also be taken into account for computation of value of exports.

3.12 Effective date of schemes (MEIS and SEIS)

The schemes shall come into force with effect from the date of notification of this Policy, i.e. the rewards under MEIS/SEIS shall be admissible for exports made/services rendered on or after the date of notification of this Policy.

3.13 Special Provisions

- (a) Government reserves the right in public interest, to specify export products or services or markets, which shall not be eligible for computation of entitlement of duty credit scrip.
- (b) Government reserves the right to impose restriction / change the rate/ceiling on Duty Credit Scrip under this chapter.
- (c) Government may also notify goods in Appendix 3A which shall not be allowed for debiting through Duty Credit Scripts in case of import.
- (d) Government may prescribe value cap of any kind for a product(s) or limit total reward per IEC holder under this chapter at any time.

Common Provisions for Exports from India Schemes (MEIS and SEIS)**3.14 Transitional Arrangement**

For the goods exported or services rendered upto the date of notification of this Policy, which were otherwise eligible for issuance of scrips under erstwhile Chapter 3 of the earlier Foreign Trade Policy(ies) and scrip is applied / issued on or after notification of this Policy against such export of goods or services rendered, the then prevailing policy and procedure regarding eligibility, entitlement, transferability, usage of scrip and any other condition in force at the time of export of goods or rendering of the services, shall be applicable to such scrips.

3.15 CENVAT/ Drawback

Additional Customs duty specified under Sections 3(1), 3(3) and 3(5) of the Customs Tariff Act, 1975 /Central excise duty paid in cash or through debit under Duty Credit scrip shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per DoR rules or notifications. Basic Custom duty paid in cash or through debit under Duty Credit scrip shall be adjusted for Duty Drawback as per DoR rules or notifications.

3.16 Import under lease financing

Utilization of Duty Credit Scrip shall be permitted for payment of duty in case of import of capital goods under lease financing in terms of provision in paragraph 2.34 of FTP.

3.17 Transfer of export performance

- (a) Transfer of export performance from one IEC holder to another IEC holder shall not be permitted. Thus, a shipping bill containing name of applicant shall be counted in export performance / turnover of applicant only if export proceeds from overseas are realized in applicant's bank account and this shall be evidenced from e - BRC / FIRC.
- (b) However, MEIS, rewards can be claimed either by the supporting manufacturer (along with disclaimer from the company / firm who has realized the foreign exchange directly from overseas) or by the company/ firm who has realized the foreign exchange directly from overseas.

3.18 Facility of payment of custom duties and fee through duty credit scrips

- (a) Duty Credit Scrip can be utilized / debited for payment of Custom Duties in case of EO defaults for Authorisations issued under Chapters 4 and 5 of Foreign Trade Policy. Such utilization /usage shall be in respect of those goods which are permitted to be imported under the respective reward schemes. However, penalty / interest shall be required to be paid in cash.
- (b) Duty credit scrips can also be used for payment of composition fee under FTP, for payment of application fee under FTP, if any and for payment of value shortfall in EO under Para 4.49 of HBP 2015-20.

3.19 Risk Management System

- (a) A Risk Management System shall be in operation whereby every month Computer system in DGFT Headquarters, on random basis and on the basis of guidelines issued by the DGFT from time to time, will select 10% of applications for each RA where scrips and Status Holder Certificates have already been issued, under each scheme. RA in turn may call for original documents in all such selected cases for further examination in detail. In case any discrepancy and/ or over claim is found on such examination, the applicant shall be under obligation to rectify such discrepancy and/or refund over claim in cash with interest at the rate prescribed under section 28 A A of the Customs Act 1962, from the date of issue of scrip in the relevant Head of Account of

Customs within one month. The original holder of scrip, however, may refund such over claim by surrendering the same scrip whether partially utilized or fully unutilized, without interest.

- (b) Regional Authority may ask for original proof of landing certificate (wherever required under the policy), annexures attached to ANFs or any other document, which has been uploaded digitally or any other export related documents related to the application such as Export Invoices at any time within three years from the date of issue of scrip. Failure to submit such documents in original would make applicant liable to refund the reward granted along with interest at the rate prescribed under section 28 A A of the Customs Act 1962, from the date of issuance of scrip. If an applicant is found to have mis-declared the Item description under any ITC HS Code, appropriate action under FT(D&R) Act, would be taken. It would be the responsibility of applicant to maintain such documents, certificate etc. for a period of at least three years from the date of issuance of scrips or the completion of scrutiny under RMS initiated by the RA whichever is later.

3.20 Status Holder

- (a) Status Holders are business leaders who have excelled in international trade and have successfully contributed to country's foreign trade. Status Holders are expected to not only contribute towards India's exports but also provide guidance and handholding to new entrepreneurs.
- (b) All exporters of goods, services and technology having an import-export code (IEC) number shall be eligible for recognition as a status holder. Status recognition will depend on export performance. An applicant shall be categorized as status holder on achieving export performance during the current and previous three financial years (for Gems & Jewellery Sector the performance during the current and previous two financial years shall be considered for recognition as status holder) as indicated in paragraph 3.21 of Foreign Trade Policy. The export performance will be counted on the basis of FOB of export earning in freely convertible foreign currencies
- (c) For deemed export, FOR value of exports in Indian Rupees shall be converted in US\$ at the exchange rate notified by CBEC, as applicable on 1st April of each Financial Year.
- (d) For granting status, export performance is necessary in at least two out of four years.

3.21 Status Category

Status Category	Export Performance FOB / FOR (as converted) Value (in US \$ million)
One Star Export House	3
Two Star Export House	25
Three Star Export House	100
Four Star Export House	500
Five Star Export House	2000

3.22 Grant of Double Weightage

- (a) The exports by IEC holders under the following categories shall be granted double weightage for calculation of export performance for grant of status.
- Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) as defined in Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006.
 - Manufacturing units having ISO/BIS.
 - Units located in North Eastern States including Sikkim and Jammu & Kashmir.
 - Units located in Agri Export Zones.
- (b) Double Weightage shall be available for grant of One Star Export House Status category only. Such benefit of double weightage shall not be admissible for grant of status recognition of other categories namely Two Star Export House, Three Star Export House, Four Star export House and Five Star Export House.
- (c) A shipment can get double weightage only once in any one of above categories.

3.23 Other conditions for grant of status

- (a) Export performance of one IEC holder shall not be permitted to be transferred to another IEC holder. Hence, calculation of exports performance based on disclaimer shall not be allowed.
- (b) Exports made on re-export basis shall not be counted for recognition.
- (c) Export of items under Authorisation, including SCOMET items, would be included for calculation of export performance.

3.24 Privileges of Status Holders

A Status Holder shall be eligible for privileges as under:

- (a) Authorisation and Customs Clearances for both imports and exports may be granted on self-declaration basis;
- (b) Input-Output norms may be fixed on priority within 60 days by the Norms Committee ;Special scheme in respect of Input Output Norms to be notified by DGFT from time to time, for specified status holder
- (c) Exemption from furnishing of Bank Guarantee for Schemes under FTP, unless specified otherwise anywhere in FTP or HBP;
- (d) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. Remittance / receipts, however, would be received through banking channels;
- (e) Two star and above Export houses shall be permitted to establish Export Warehouses as per Department of Revenue guidelines.
- (f) Three Star and above Export House shall be entitled to get benefit of Accredited Clients Programme (ACP) as per the guidelines of CBEC (website: <http://cbec.gov.in>).
- (g) The status holders would be entitled to preferential treatment and priority in handling of their consignments by the concerned agencies.
- (h) Manufacturers who are also status holders (Three Star/Four Star/Five Star) will be enabled to self-certify their manufactured goods (as per their IEM/IL/LOI) as originating from India with a view to qualify for preferential treatment under different preferential trading agreements (PTA), Free Trade Agreements (FTAs), Comprehensive Economic Cooperation Agreements (CECA) and Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA). Subsequently, the scheme may be extended to remaining Status Holders.
- (i) Manufacturer exporters who are also Status Holders shall be eligible to self-certify their goods as originating from India as per Para 2.108 (d) of Hand Book of Procedures.
- (j) Status holders shall be entitled to export freely exportable items (excluding Gems and Jewellery, Articles of Gold and precious metals) on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rupees One Crore or 2% of average annual export realization during preceding three licensing years, whichever is lower. For export of pharma products by pharmaceutical companies, the annual limit would be 2% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN, WHO-PAHO and Government health programmes, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme

CHAPTER 4**DUTY EXEMPTION /REMISSION SCHEMES****4.00 Objective**

Schemes under this Chapter enable duty free import of inputs for export production, including replenishment of inputs or duty remission.

4.01 Schemes

- (a) Duty Exemption Schemes.

The Duty Exemption schemes consist of the following:

- Advance Authorisation (AA) (which will include Advance Authorisation for Annual Requirement).
 - Duty Free Import Authorisation (DFIA).
- (b) Duty Remission Scheme.
- Duty Drawback (DBK) Scheme, administered by Department of Revenue.

4.02 Applicability of Policy & Procedures

Authorisation under this Chapter shall be issued in accordance with the Policy and Procedures in force on the date of issue of the Authorisation.

4.03 Advance Authorisation

- (a) Advance Authorisation is issued to allow duty free import of input, which is physically incorporated in export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, catalyst which is consumed / utilized in the process of production of export product, may also be allowed.
- (b) Advance Authorisation is issued for inputs in relation to resultant product, on the following basis:
- (i) As per Standard Input Output Norms (SION) notified (available in Hand Book of Procedures);
- OR
- (ii) On the basis of self declaration as per paragraph 4.07 of Handbook of Procedures.
- OR
- (iii) Applicant specific prior fixation of norm by the Norms Committee.
- OR
- (iv) On the basis of Self Ratification Scheme in terms of Para 4.07A of Foreign Trade Policy.

4.04 Advance Authorisation for Spices

Duty free import of spices covered under Chapter-9 of ITC (HS) shall be permitted only for activities like crushing/grinding / sterilization/ manufacture of oils or oleoresins. Authorisation shall not be available for simply cleaning, grading, re-packing etc.

4.04 A Special Advance Authorisation Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing accessories.

Duty free import of fabric under 'Special Advance Authorisation Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories' shall be allowed, as per Customs Notification issued for this scheme, for export of items covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import, subject to the following terms and conditions:

- (i) The authorisation shall be issued based on Standard Input Output Norms (SION) or prior fixation of norms by Norms Committee.
- (ii) The authorisation shall be issued for the import of relevant fabrics including inter lining only as input. No other input, packing material, fuel, oil and catalyst shall be allowed for import under this authorisation.
- (iii) Exporters shall be eligible for All Industry Rate of Duty Drawback, for non fabric inputs, as determined by Central Government for this scheme. For the purpose of value addition norm of Para 4.08 of FTP, the value of any other input used on which benefit of Drawback is claimed or intended to be claimed shall be equal to 22% of the FOB value of export realised. Minimum value addition shall be as per Para 4.09 of FTP.
- (iv) Where the exporter desires to claim drawback determined and fixed by Jurisdictional Customs Authority (brand rate), he shall follow Para 4.15 of FTP regarding declarations to be made in application for the authorisation and make export under claim for brand rate. In such cases the value addition shall be as per Para 4.08 of FTP. Minimum value addition shall be as per Para 4.09 of FTP.
- (v) Authorisation, and the fabric imported, shall be subject to actual user condition. The same shall be non transferable even after completion of export obligation. However fabric imported may be transferred for job work in terms of provisions of GST Acts under intimation to the Customs authority at the port of registration (excluding to units located in areas eligible for area based exemption from Central Excise Duty). Invalidation of the Authorisation shall not be permitted.

- (vi) The fabric imported shall be subject to pre-import condition and it shall be physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). Only Physical exports shall fulfil the export obligation.
- (vii) Provisions of paragraphs 4.02, 4.05(a), 4.13(i), 4.13(ii), 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.21(i), 4.21(ii), 4.21(iii), 4.21(v), 4.22(i), and 4.24 of Foreign Trade Policy shall be applicable in so far as they are not inconsistent with this scheme.

4.05 Eligible Applicant / Export / Supply

- (a) Advance Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer.
- (b) Advance Authorisation for pharmaceutical products manufactured through Non-Infringing (NI) process (as indicated in paragraph 4.18 of Handbook of Procedures) shall be issued to manufacturer exporter only.
- (c) Advance Authorisation shall be issued for
 - (i) Physical export (including export to SEZ);
 - (ii) Intermediate supply; and/or
 - (iii) Supply of goods to the categories mentioned in paragraph 7.02 (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of this FTP.
 - (iv) Supply of 'stores' on board of foreign going vessel / aircraft, subject to condition that there is specific Standard Input Output Norms in respect of item supplied.

4.06 Advance Authorisation for Annual Requirement

- (i) Advance Authorisation for Annual Requirement shall only be issued for items notified in Standard Input Output Norms (SION), and it shall not be available in case of adhoc norms under paragraph 4.03 (b)(ii) of FTP.
- (ii) Advance Authorisation for Annual Requirement shall also not be available in respect of SION where any item of input appears in Appendix 4-J.

4.07 Eligibility Condition to obtain Advance Authorisation for Annual Requirement

- (i) Exporters having past export performance (in at least preceding two financial years) shall be entitled for Advance Authorisation for Annual requirement.
- (ii) Entitlement in terms of CIF value of imports shall be upto 300% of the FOB value of physical export and / or FOR value of deemed export in preceding financial year or Rs 1 crore, whichever is higher.

4.07A Self Ratification Scheme

- i. Where there is no SION/valid Adhoc Norms for an export product and where SION has been notified but exporter intends to use additional inputs in the manufacturing process, eligible exporter can apply for an Advance Authorisation under this scheme on self declaration and self ratification basis. RA may issue Advance Authorisations and such cases need not be referred to Norms Committees for ratification of norms. Application under this scheme shall be made along with a Certificate from Chartered Engineer in the prescribed format.
- ii. A Certificate from a Chartered Engineer who has been not been penalised in the last five years under FT(D&R) Act 1992, Customs Act 1962, Central Excise Act 1944, GST Acts and allied acts and rules made there under shall only be accepted for grant of Authorisation under this scheme.
- iii. Detailed procedure for administering the scheme shall be prescribed in the Handbook of Procedures.
- iv. An exporter (manufacturer or merchant) who holds AEO Certificate under Common Accreditation Programme of CBEC is eligible to opt for this scheme.
- v. The scheme shall not be available for the following export products.
 - a) All items covered under Chapter-1 to 24 and Chapter-71 of ITC(HS) Classification;
 - b) Biotechnology items and related products; and
 - c) SCOMET items.
- vi. The scheme shall not be available for the following inputs.
 - a) All vegetable / edible oils classified under Chapter-15 and all types of oilseeds classified under Chapter-12 of ITC (HS) book;
 - b) All types of cereals classified under Chapter-10 of ITC (HS) book;
 - c) Horn, hoof and any other organ of animal;
 - d) Wild animal products, organs and waste thereof;
 - e) Honey;
 - f) All items with basic customs duty of 30% or more;

- g) All types of fruits/ nuts/ vegetables classified under Chapter-7 and Chapter-8 of ITC (HS) book;
 - h) Items covered under heading 2515, 2516, 3301, 3302, 3303 6801 and 6802 of ITC(HS) Classification;
 - i) Items covered under Chapter 50 to 63 of ITC(HS) classification.
 - j) Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudoephedrine;
 - k) Vitamins;
 - l) Biotechnology items and related products;
 - m) Insecticides, Rodenticides, Fungicides, herbicides, Anti sprouting products, and plant growth regulators, disinfectants and similar products of all forms, types and grades;
 - n) Waste/Scrap of all types; and
 - o) Second hand goods.
- vii. Inputs imported shall be subject to pre import condition and they shall be physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In case of local procurement under invalidation/ARO, the inputs shall be procured prior to manufacture of export item and shall be physically incorporated in the export product.
- viii. Wherever value of by-products and recoverable wastage generated during manufacturing process is more than 5% of CIF value, corresponding quantity of main input shall be reduced from the entitlement to the extent that value of disallowed quantity is equal to the value of by-products and recoverable wastage generated during manufacturing process.
- ix. DGFT or any person authorised by him may conduct audit of the manufacturer. The frequency and manner of audit shall be prescribed by DGFT in Handbook of Procedures. The manufacturer shall be required to provide the necessary facility to verify the books of account/other documents as required, give information and assistance for timely completion of the audit. Non-availability of production and consumption documents/data shall be treated as misdeclaration and indulgence in fraudulent activities and shall be penalised under FT(D&R) Act, as amended and rules made there under.
- x. DGFT or any person authorised by him may initiate special audit, considering the nature and complexity of the case and revenue of government, if he is of the opinion at any stage of scrutiny/enquiry/investigation that the norms have not been claimed correctly or the excess benefit has been availed. Special audit can be conducted even if the manufacturer has already been audited before.
- xi. If the audit results in detection of misdeclaration and/or instances of claiming of inputs which are not used in manufacturing process or excess quantity of inputs than consumed, demand and recovery actions will be initiated in addition to initiation of action against the authorisation holder, manufacturer and Chartered Engineer in terms of Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 and/or Customs Act 1962, as amended and rules made there under.
- xii. In cases where Chartered Engineer has not exercised due diligence or has willfully become party to misdeclaration action will be initiated under against such person under FT(D&R) Act 1992, as amended and rules made there under. In addition, such cases shall also be referred to 'The Institute of Engineers India for taking action as warranted under the bylaws of the institute.
- xiii. All the provisions applicable for Advance Authorisation Scheme shall be applicable to this scheme also in so far they are not inconsistent with this scheme.

4.08 Value Addition

Value Addition for the purpose of this Chapter (except for Gems and Jewellery sector for which value addition is prescribed in paragraph 4.38 of FTP) shall be:-

$$VA = \frac{A-B}{B} \times 100, \text{ where}$$

A = FOB value of export realized/FOR value of supply received.

B = CIF value of inputs covered by Authorisation, plus value of any other input used on which benefit of DBK is claimed or intended to be claimed.

4.09 Minimum Value Addition

- (i) Minimum value addition required to be achieved under Advance Authorisation is 15%.
- (ii) Export Products where value addition could be less than 15% are given in Appendix 4D.
- (iii) Deleted

- (iv) Minimum value addition for Gems & Jewellery Sector is given in paragraph 4.61 of Handbook of Procedures.
- (v) In case of Tea, minimum value addition shall be 50%.

4.10 Import of Mandatory Spares

Import of mandatory spares which are required to be exported / supplied with the resultant product shall be permitted duty free to the extent of 10% of CIF value of Authorisation.

4.11 Ineligible categories of import on Self Declaration basis

- (a) Import of following products shall not be permissible on self-declaration basis:
 - (i) All vegetable / edible oils classified under Chapter-15 and all types of oilseeds classified under Chapter-12 of ITC (HS) book;
 - (ii) All types of cereals classified under Chapter-10 of ITC (HS) book;
 - (iii) All Spices other than light black pepper (light berries) having a basic customs duty of more than 30%, classified under Chapter-9 and 12 of ITC (HS) book;
 - (iv) All types of fruits/ vegetables having a basic customs duty of more than 30%, classified under Chapter-7 and Chapter-8 of ITC (HS) book;
 - (v) Horn, Hoof and any other organ of animal;
 - (vi) Honey;
 - (vii) Rough Marble Blocks/Slabs; and
 - (viii) Rough Granite.
 - (ix) Vitamins except for use in pharmaceutical industry.
- (b) For export of perfumes, perfumery compounds and various feed ingredients containing vitamins, no Authorisation shall be issued by Regional Authority under paragraph 4.07 of Handbook of Procedures and applicants shall be required to apply under paragraph 4.06 of Hand Book of Procedures to the Norms Committee.
- (c) Where export and/or import of biotechnology items and related products are involved, Authorisation under paragraph 4.07 of Handbook of Procedures shall be issued by Regional Authority only on submission of a "No Objection Certificate" from Department of Biotechnology.

4.12 Accounting of Input

- (i) Wherever SION permits use of either (a) a generic input or (b) alternative input, unless the name of the specific input together with quantity [which has been used in manufacturing the export product] gets indicated / endorsed in the relevant shipping bill and these inputs, so endorsed, within quantity specified and match the description in the relevant bill of entry, the concerned Authorisation will not be redeemed. In other words, the name/description of the input used (or to be used) in the Authorisation must match exactly with the name/description endorsed in the shipping bill.
- (ii) In addition, if in any SION, a single quantity has been indicated against a number of inputs (more than one input), then quantities of such inputs to be permitted for import shall be in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production, within overall quantity against such group of inputs. Proportion of these inputs actually used/consumed in production of export product shall be clearly indicated in shipping bills.
- (iii) At the time of discharge of export obligation (issue of EODC) or at the time of redemption, Regional Authority shall allow only those inputs which have been specifically indicated in the shipping bill together with quantity.
- (iv) The above provisions will also be applicable for supplies to SEZs and supplies made under Deemed exports. Details as given above will have to be indicated in the relevant Bill of Export, ARE-3, Central Excise certified Invoice / import document / Tax Invoice for export prescribed under the GST rules

4.13 Pre-import condition in certain cases

- (i) DGFT may, by Notification, impose pre-import condition for inputs under this Chapter.
- (ii) Import items subject to pre-import condition are listed in Appendix 4-J or will be as indicated in Standard Input Output Norms (SION).

- (iii) Import of drugs from unregistered sources shall have pre-import condition.

4.14 Details of Duties exempted

Imports under Advance Authorisation are exempted from payment of Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty, Transition Product Specific Safeguard Duty, wherever applicable. Import against supplies covered under paragraph 7.02 (c), (d) and (g) of FTP will not be exempted from payment of applicable Anti-dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty and Transition Product Specific Safeguard Duty, if any. However, imports under Advance Authorisation for physical exports are also exempt from whole of the integrated tax and Compensation Cess leviable under sub-section (7) and sub-section (9) respectively, of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as may be provided in the notification issued by Department of Revenue, and such imports shall be subject to pre-import condition. Imports against Advance Authorisations for physical exports are exempted from Integrated Tax and Compensation Cess upto 31.03.2018 only.

4.15 Admissibility of Drawback

Drawback as per rate determined and fixed by Customs authority in terms of DoR Rules shall be available for duty paid imported or indigenous inputs (not specified in the norms) used in the export product. For this purpose, applicant shall indicate clearly details of duty paid input in the application for Advance Authorisation. As per details mentioned in the application, Regional Authority shall also clearly endorse details of such duty paid inputs in the condition sheet of the Advance Authorisation.

4.16 Actual User Condition for Advance Authorisation

- (i) Advance Authorisation and / or material imported under Advance Authorisation shall be subject to 'Actual User' condition. The same shall not be transferable even after completion of export obligation. However, Authorisation holder will have option to dispose of product manufactured out of duty free input once export obligation is completed.
- (ii) In case where CENVAT/input tax credit facility on input has been availed for the exported goods, even after completion of export obligation, the goods imported against such Advance Authorisation shall be utilized only in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer). For this, the Authorisation holder shall produce a certificate from either the jurisdictional Customs Authority or Chartered Accountant, at the option of the exporter, at the time of filing application for Export Obligation Discharge Certificate to Regional Authority concerned.
- (iii) Waste / Scrap arising out of manufacturing process, as allowed, can be disposed off on payment of applicable duty even before fulfillment of export obligation.

4.17 Validity Period for Import and its Extension

Validity period for import under Advance Authorisation shall be as prescribed in Handbook of Procedures.

4.18 Importability/Export ability of items that are Prohibited/Restricted/ STE

- (i) No export or import of an item shall be allowed under Advance Authorisation / DFIA if the item is prohibited for exports or imports respectively. Export of a prohibited item may be allowed under Advance Authorisation provided it is separately so notified, subject to the conditions given therein.
- (ii) Items reserved for imports by STEs cannot be imported against Advance Authorisation / DFIA. However, those items can be procured from STEs against ARO or Invalidation letter. STEs are also allowed to sell goods on High Sea Sale basis to holders of Advance Authorisation / DFIA holder. STEs are also permitted to issue "No Objection Certificate(NOC)" for import by Advance Authorisation / DFIA holder. Authorisation Holder would be required to file Quarterly Returns of imports effected against such NOC to concerned STE and STE would submit half-yearly import figures of such imports to concerned administrative Department for monitoring with a copy endorsed to DGFT.
- (iii) Items reserved for export by STE can be exported under Advance Authorisation / DFIA only after obtaining a 'No Objection Certificate' from the concerned STE.
- (iv) Import of restricted items shall be allowed under Advance Authorisation/ DFIA.
- (v) Export of restricted / SCOMET items however, shall be subject to all conditionalities or requirements of export authorisation or permission, as may be required, under Schedule 2 of ITC (HS).

4.19 Free of Cost Supply by Foreign Buyer

Advance Authorisation shall also be available where some or all inputs are supplied free of cost to exporter by foreign buyer. In such cases, notional value of free of cost input shall be added in the CIF value of import and FOB value of export for the purpose of computation of value addition. However, realization of export proceeds will be equivalent to an amount excluding notional value of such input.

4.20 Domestic Sourcing of Inputs

- (i) Holder of an Advance Authorisation / Duty Free Import Authorisation can procure inputs from indigenous supplier/ State Trading Enterprise/EOU/EHTP/BTP/STP in lieu of direct import. Such procurement can be against Advance Release Order (ARO), or Invalidation Letter.
- (ii) When domestic supplier intends to obtain duty free material for inputs through Advance Authorisation for supplying resultant product to another Advance Authorisation / DFIA / EPCG Authorisation, Regional Authority shall issue Invalidation Letter.
- (iii) Regional Authority shall issue Advance Release Order if the domestic supplier intends to seek refund of duties exempted through Deemed Exports mechanism as per provisions under Chapter-7 of FTP.
- (iv) Regional Authority may issue Advance Release Order or Invalidation Letter at the time of issue of Authorisation simultaneously or subsequently.
- (v) Advance Authorisation holder under DTA can procure inputs from / SEZ units without obtaining Advance Release Order or Invalidation Letter.
- (vi) Deleted
- (vii) Validity of Advance Release Order / Invalidation Letter shall be co-terminous with validity of Authorisation.

4.21 Currency for Realisation of Export Proceeds.

- (i) Export proceeds shall be realized in freely convertible currency except otherwise specified. Provisions regarding realisation and non realisation of export proceeds are given in paragraph 2.52, 2.53 and 2.54 of FTP.
- (ii) Deleted
- (iii) Export to SEZ Units shall be taken into account for discharge of export obligation provided payment is realised from Foreign Currency Account of the SEZ unit.
- (iv) Export to SEZ Developers / Co-developers can also be taken into account for discharge of export obligation even if payment is realised in Indian Rupees.
- (v) Authorisation holder needs to file Bill of Export for export to SEZ unit / developer / co-developer in accordance with the procedures given in SEZ Rules, 2006.

4.22 Export Obligation Period and its Extension

Period for fulfilment of export obligation and its extension under Advance Authorisation shall be as prescribed in Handbook of Procedures.

4.23 Deleted**4.24 Re-import of exported goods under Duty Exemption / Remission Scheme**

Goods exported under Advance Authorisation/ Duty Free Import Authorisation may be re-imported in same or substantially same form subject to such conditions as may be specified by Department of Revenue. Authorisation holder shall also inform about such re-importation to the Regional Authority which had issued the Authorisation within one month from date of re-import.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION SCHEME (DFIA)**4.25 DFIA Scheme**

- (a) Duty Free Import Authorisation is issued to allow duty free import of inputs. In addition, import of oil and catalyst which is consumed / utilised in the process of production of export product, may also be allowed.
- (b) Provisions of paragraphs 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 and 4.24 of FTP shall be applicable to DFIA also.
- (c) Duty Free Import Authorisation Scheme shall not be available for import of raw sugar.

4.26 Duties Exempted

- (i) Duty Free Import Authorisation shall be exempted only from payment of Basic Customs Duty (BCD).
- (ii) Deleted
- (iii) Drawback as per rate determined and fixed by Customs authority shall be available for duty paid inputs, whether imported or indigenous, used in the export product. However, in case such drawback is claimed for inputs not specified in SION, the applicant should have indicated clearly details of such duty paid inputs also in the application for Duty Free Import Authorisation, and as per the details mentioned in the application, the

Regional Authority should also have clearly endorsed details of such duty paid inputs in the condition sheet of the Duty Free Import Authorisation.

4.27 Eligibility

- (i) Duty Free Import Authorisation shall be issued on post export basis for products for which Standard Input Output Norms have been notified.
- (ii) Merchant Exporter shall be required to mention name and address of supporting manufacturer of the export product on the export document viz. Shipping Bill/ Bill of Export / Tax Invoice for export prescribed under the GST rules.
- (iii) Application is to be filed with concerned Regional Authority before effecting export under Duty Free Import Authorisation.
- (iv) No Duty Free Import Authorisation shall be issued for an input which is subjected to pre-import condition or where SION prescribes 'Actual User' condition or Appendix-4J prescribes pre import condition for such an input.

4.28 Minimum Value Addition

Minimum value addition of 20% shall be required to be achieved.

4.29 Validity & Transferability of DFIA

- (i) Applicant shall file online application to Regional Authority concerned before starting export under DFIA.
- (ii) Export shall be completed within 12 months from the date of online filing of application and generation of file number.
- (iii) While doing export/supply, applicant shall indicate file number on the export /supply documents viz. Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules.
- (iv) In terms of Para 4.12 of FTP, Wherever SION permits use of either (a) a generic input or (b) alternative input, the specific input together with quantity [which has been used in manufacturing the export product] should be indicated / endorsed in the relevant Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules . Only such inputs may be permitted for import in the authorisation in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production, within overall quantity against such generic input/alternative input.
- (v) In addition, if in any SION, a single quantity has been indicated against a number of inputs (more than one input), then quantities of such inputs to be permitted for import shall be in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production and declared in Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules within overall quantity against such group of inputs. Proportion of these inputs actually used/consumed in production of export product shall be clearly indicated in Shipping Bill / Bill of Export / Tax invoice for supply prescribed under GST rules.
- (vi) Separate DFIA shall be issued for each SION and each port.
- (vii) Exports under DFIA shall be made from a single port as mentioned in paragraph 4.37 of Handbook of Procedures.
- (viii) Regional Authority shall issue transferable DFIA with a validity of 12 months from the date of issue. No further revalidation shall be granted by Regional Authority.

4.30 Sensitive Items under Duty Free Import Authorisation

- (a) In respect of following inputs, exporter shall be required to provide declaration with regard to technical characteristics, quality and specification in Shipping Bill:

“Alloy steel including Stainless Steel, Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings, Solvent, Perfumes / Essential Oil/ Aromatic Chemicals, Surfactants, Relevant Fabrics, Marble, Articles made of Polypropylene, Articles made of Paper and Paper Board, Insecticides, Lead Ingots, Zinc Ingots, Citric Acid, Relevant Glass fibre reinforcement (Glass fibre, Chopped / Stranded Mat, Roving Woven Surfacing Mat), Relevant Synthetic Resin (unsaturated Polyester Resin, Epoxy Resin, Vinyl Ester Resin, Hydroxy Ethyl Cellulose), Lining Material”.

- (b) While issuing Duty Free Import Authorisation, Regional Authority shall mention technical characteristics, quality and specification in respect of above inputs in the Authorisation.

SCHEMES FOR EXPORTERS OF GEMS AND JEWELLERY

4.31 Import of Input

Exporters of gems and Jewellery can import / procure duty free (excluding Integrated Tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of customs Tariff Act) input for manufacture of export product.

4.32 Items of Export

Following items, if exported, would be eligible:

- (i) Gold jewellery, including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above up to a maximum limit of 22 carats;
- (ii) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;
- (iii) Platinum jewellery including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

4.33 Schemes

The schemes are as follows:

- (i) Advance Procurement / Replenishment of Precious Metals from Nominated Agencies;
- (ii) Replenishment Authorisation for Gems;
- (iii) Replenishment Authorisation for Consumables;
- (iv) Advance Authorisation for Precious Metals.

4.34 Advance Procurement/ Replenishment of Precious Metals from Nominated Agencies

- (i) Exporter of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof including mountings and findings may obtain gold / silver / platinum as an input for export product from Nominated Agency, in advance or as replenishment after export in accordance with the procedure specified in this behalf.

No replenishment of the precious metal shall be available to the exporter/manufacturer where the exporter/manufacturer avails any of the benefits in respect of exported product.

- a. CENVAT Credit is availed on inputs or services by the manufacturer.
- b. Finished goods stage rebate is availed under Notification No 19/2004-CE (NT) dated 06.09.2004.
- c. Input stage rebate is availed in respect of duty of excise paid on the precious metal bar or articles of precious metal under Notification No 21/2004-CE(NT) dated 06.09.2004.
- d. Precious metal or articles of precious metal are procured by the manufacturer under rule 19(2) of the Central Excise Rules, 2002.
- e. Input Tax Credit is availed on inputs or services or both by the exporter under Chapter V of CGST Act; or refund of ITC or refund of IGST is availed under section 54 of the CGST Act.
- (ii) The export would be subject to wastage norms and minimum value addition as prescribed in paragraph 4.60 and 4.61 respectively in the Handbook of Procedures.

4.35 Replenishment Authorisation for Gems

- (i) Exporter may obtain Replenishment Authorisation for Gems from Regional Authority in accordance with procedure specified in Handbook of Procedures as per the replenishment rate prescribed in Appendix 4F. Replenishment Authorisation for Gems shall be freely transferable.
- (ii) Replenishment Authorisation for Gems may be issued against export including that made against supply by Nominated Agency (paragraph 4.41 of FTP) and against supply by foreign buyer (paragraph 4.45 of FTP).
- (iii) In the case of studded gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the value of Gem Replenishment Authorisation shall be on the remaining FOB value of exports after deducting the value of gold/ silver/ platinum including admissible wastage. The scale of replenishment and the item of import will be as prescribed in Appendix 4G.

4.36 Replenishment Authorisation for Consumables

- (i) Replenishment Authorisation for duty free (excluding Integrated Tax and Compensation cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act) import of Consumables, Tools and other items namely, Tags and labels, Security censor on card, Staple wire, Poly bag (as notified by Customs) for Jewellery made out of

precious metals (other than Gold & Platinum) equal to 2% and for Cut and Polished Diamonds and Jewellery made out of Gold and Platinum equal to 1% of FOB value of exports of the preceding year, may be issued on production of Chartered Accountant Certificate indicating the export performance. However, in case of Rhodium finished Silver jewellery, entitlement will be 3% of FOB value of exports of such jewellery. This Authorisation shall be non-transferable and subject to actual user condition.

- (ii) Application for import of consumables as given above shall be filed online to the concerned Regional Authority in ANF 4H.

4.37 Advance Authorisation for Precious Metals

- (a) Advance Authorisation shall be granted on pre-import basis with 'Actual User' condition for duty free (excluding Integrated Tax and Compensation cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act) import of:
 - (i) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;
 - (ii) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;
 - (iii) Platinum of fineness not less than 0.900 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.
- (b) Advance Authorisation shall carry an export obligation which shall be fulfilled as per procedure indicated in Chapter 4 of Handbook of Procedures.
- (c) Value Addition shall be as per paragraph 4.38 of FTP and 4.61 of Handbook of Procedures.

4.38 Value Addition

Minimum Value Addition norms for gems and jewellery sector are given in paragraph 4.61 of Handbook of Procedures. It would be calculated as under:

$$VA = \frac{A-B}{B} \times 100, \text{ where}$$

A = FOB value of the export realised/ FOR value of supply received.

B = Value of inputs (including domestically procured) such as gold/silver/platinum content in export product plus admissible wastage along with value of other items such as gemstone etc. Wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplier.

4.39 Wastage Norms

Wastage or manufacturing loss for gold/silver/platinum jewellery shall be admissible as per paragraph 4.60 of Handbook of Procedures.

4.40 DFIA not available

Duty Free Import Authorisation scheme shall not be available for Gems and Jewellery sector.

4.41 Nominated Agencies

- (i) Exporters may obtain gold / silver / platinum from Nominated Agency. Exporter in EOU and units in SEZ would be governed by the respective provisions of Chapter-6 of FTP / SEZ Rules, respectively.
- (ii) Nominated Agencies are MMTC Ltd, The Handicraft and Handlooms Exports Corporation of India Ltd, The State Trading Corporation of India Ltd, PEC Ltd, STCL Ltd, MSTC Ltd, and Diamond India Limited.
- (iii) Notwithstanding any provision relating to import of gold by Nominated Agencies under Foreign Trade Policy (2015-2020), the import of gold by Four Star and Five Star Houses with Nominated Agency Certificate is subjected to actual user condition and are permitted to import gold as input only for the purpose of manufacture and export by themselves during the remaining validity period of the Nominated Agency certificate.
- (iv) Reserve Bank of India can authorize any bank as Nominated Agency.
- (iv) Procedure for import of precious metal by Nominated Agency (other than those authorized by Reserve Bank of India and the Gems & Jewellery units operating under EOU and SEZ schemes) and the monitoring mechanism thereof shall be as per the provisions laid down in Hand Book of Procedures.

- (v) A bank authorised by Reserve Bank of India is allowed export of gold scrap for refining and import standard gold bars as per Reserve Bank of India guidelines.

4.42 Import of Diamonds for Certification / Grading & Re- export

Following agencies are permitted to import diamonds to their laboratories without any import duty, for the purpose of certification / grading reports, with a condition that the same should be re-exported with the certification/grading reports, as per the procedure laid down in Hand Book of Procedures:

- (1) Gemological Institute of America (GIA), Mumbai, Maharashtra.
- (2) Indian Diamond Institute, Surat, Gujarat, India.
- (3) International Institute of Diamond Grading & Research India Pvt. Ltd., Surat, Gujarat, India.
- (4) HRD Diamond Institute Private Limited, Mumbai, Maharashtra, India
- (5) International Gemological Institute (India) Pvt. Ltd, Bandra Kurla Complex, Mumbai

4.43 Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/ Grading & Re-import

List of authorized laboratories for certification / grading of diamonds of 0.25 carat and above are given in paragraph 4.74 of Handbook of Procedures.

4.44 Export of Cut & Polished Diamonds with Re-import Facility at Zero Duty

An exporter (with annual export turnover of Rs 5 crores for each of the last three years) or the authorized offices/agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Hand Book of Procedures may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within 3months from the date of export. Such facility of re-import at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue.

4.45 Export against Supply by Foreign Buyer

- (i) Where export orders are placed on nominated agencies / status holder / exporters of three years standing having an annual average turnover of Rupees five crores during preceding three financial years, foreign buyer may supply in advance and free of charge, gold / silver / platinum, alloys, findings and mountings of gold / silver / platinum for manufacture and export.
- (ii) Such supplies can also be in advance and may involve semi-finished jewellery including findings / mountings / components for repairs / re-make and export subject to minimum value addition as prescribed under paragraph 4.61 of Handbook of Procedures. In such cases of export, wastage norms as per paragraph 4.60 of Handbook of Procedures shall apply.
- (iii) Exports may be made by nominated agencies directly or through their associates or by status holder / exporter. Import and Export of findings shall be on net to net basis.

4.46 Export Promotion Tours/ Export of Branded Jewellery

- (i) Nominated Agencies and their associates, with approval of Department of Commerce and with approval of Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), may export gold / silver / platinum jewellery and articles thereof for exhibitions abroad.
- (ii) Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted, subject to conditions as in Handbook of Procedures.

4.47 Personal Carriage of Export /Import Parcels

Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and import parcels by an Indian importer/foreign national may be permitted as per the Handbook of Procedures.

4.48 Export by Post

Export of jewellery through Foreign Post Office including via Speed Post is allowed. The jewellery parcel shall not exceed 20 kgs by weight.

4.49 Private / Public Bonded Warehouse

Private / Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/DTA for import and re-export of cut and polished diamonds, cut and polished coloured gemstones, uncut & unset precious & semi-precious stones, subject to achievement of minimum value addition of 5% by DTA units.

4.49(A)

Import, auction/sale and re-export of rough diamonds by entities, as notified vide RBI Notification 116 of 1st April, 2014, as amended from time to time, on consignment or outright basis, will be permitted in Special Notified Zone (SNZ) administered by the operator of SNZ, under supervision of Customs. The procedure of import, auction/ sale and re-export of rough diamonds (unsold) would be as specified by CBEC.

4.50 Diamond & Jewellery Dollar Accounts

- (a) Firms and companies dealing in purchase / sale of rough or cut and polished diamonds / precious metal jewellery plain, minakari and / or studded with / without diamond and / or other stones with a track record of at least two years in import or export of diamonds / coloured gemstones / diamond and coloured gemstones studded jewellery / plain gold jewellery and having an average annual turnover of Rs.3 crore or above during preceding three licensing years may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts (DDA).
- (b) Dollars in such accounts available from bank finance and / or export proceeds shall be used only for:
 - (i) Import / purchase of rough diamonds from overseas/ local sources;
 - (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources;
 - (iii) Import / purchase of gold from overseas / nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and
 - (iv) Transfer to Rupee Account of exporter. Details of this DDA Scheme are given in Handbook of Procedures.
- (c) A non DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert the same into Rupees within 7 days. Cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non-DDA holder will also be counted towards discharge of his export obligation and/ or entitle him to replenishment Authorisation.

4.51 Export of cut & polished precious and semi-precious stones for treatment and re-import

Gems and Jewellery exporters shall be allowed to export cut and polished precious and semi-precious stones for the treatment and re-import as per customs rules and regulations. In case of re-export, the exporter shall be entitled for duty drawback as per rules.

4.52 Re-import of rejected Jewellery

Gems & Jewellery exporters shall be allowed to re-import rejected precious metal jewellery as per paragraph 4.91 of Handbook of Procedures.

4.53 Export and import on consignment basis

Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export and import diamond, gemstones & jewellery on consignment basis as per Handbook of Procedures and Customs Rules and Regulations.

CHAPTER 5**EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS (EPCG) SCHEME****5.00 Objective**

The objective of the EPCG Scheme is to facilitate import of capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness.

5.01 EPCG Scheme

- (a) EPCG Scheme allows import of capital goods (except those specified in negative list in Appendix 5 F) for pre-production, production and post-production at zero customs duty. Capital goods imported under EPCG Authorisation for physical exports are also exempt from IGST and Compensation Cess upto 31.3.2018 only, leviable thereon under the subsection(7) and subsection (9) respectively, of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as provided in the notification issued by Department of Revenue. Alternatively, the Authorisation holder may also procure Capital Goods from indigenous sources in accordance with provisions of paragraph 5.07 of FTP. Capital goods for the purpose of the EPCG scheme shall include:

- (i) Capital Goods as defined in Chapter 9 including in CKD/SKD condition thereof;
 - (ii) Computer systems and software which are a part of the Capital Goods being imported;
 - (iii) Spares, moulds, dies, jigs, fixtures, tools & refractories; and
 - (iv) Catalysts for initial charge plus one subsequent charge.
- (b) Import of capital goods for Project Imports notified by Central Board of Excise and Customs is also permitted under EPCG Scheme.
- (c) Import under EPCG Scheme shall be subject to an export obligation equivalent to 6 times of duties, taxes and cess saved on capital goods, to be fulfilled in 6 years reckoned from date of issue of Authorisation.
- (d) Authorisation shall be valid for import for 18 months from the date of issue of Authorisation. Revalidation of EPCG Authorisation shall not be permitted.
- (e) In case Integrated Tax and Compensation Cess are paid in cash on imports under EPCG, incidence of the said Integrated Tax and Compensation Cess would not be taken for computation of net duty saved provided Input Tax Credit is not availed.
- (f) Deleted.
- (g) Deleted.
- (h) Import of items which are restricted for import shall be permitted under EPCG Scheme only after approval from Exim Facilitation Committee (EFC) at DGFT Headquarters.
- (i) If the goods proposed to be exported under EPCG authorisation are restricted for export, the EPCG authorisation shall be issued only after approval for issuance of export authorisation from Exim Facilitation Committee at DGFT Headquarters.

5.02 Coverage

- (a) EPCG scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers. Name of supporting manufacturer(s) shall be endorsed on the EPCG Authorisation before installation of the capital goods in the factory / premises of the supporting manufacturer (s). In case of any change in supporting manufacturer (s) the RA shall intimate such change to jurisdictional Customs Authority of existing as well as changed supporting manufacturer(s) and the Customs at port of registration of Authorisation.
- (b) Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme also covers a service provider who is designated / certified as a Common Service Provider (CSP) by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export Excellence subject to provisions of Foreign Trade Policy/Handbook of Procedures with the following conditions:-
- (i) Export by users of the common service, to be counted towards fulfillment of EO of the CSP shall contain the EPCG Authorisation details of the CSP in the respective Shipping bills and concerned RA must be informed about the details of the Users prior to such export;
 - (ii) Such export will not count towards fulfillment of specific export obligations in respect of other EPCG Authorisations (of the CSP/User); and
 - (iii) Authorisation holder shall be required to submit Bank Guarantee (BG) which shall be equivalent to the duty saved. BG can be given by CSP or by any one of the users or a combination thereof, at the option of the CSP.

5.03 Actual User Condition

Imported capital goods shall be subject to Actual User condition till export obligation is completed and EODC is granted.

5.04 Export Obligation (EO)

Following conditions shall apply to the fulfilment of EO:-

- (a) EO shall be fulfilled by the authorisation holder through export of goods which are manufactured by him or his supporting manufacturer / services rendered by him, for which the EPCG authorisation has been granted.
- (b) EO under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by the applicant in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall EO period including

extended period, if any; except for categories mentioned in paragraph 5.13(a) of HBP. Such average would be the arithmetic mean of export performance in the preceding three licensing years for same and similar products.

- (c) In case of indigenous sourcing of Capital Goods, specific EO shall be 25% less than the EO stipulated in Para 5.01.
- (d) Shipments under Advance Authorisation, DFIA, Drawback scheme or reward schemes under Chapter 3 of FTP; would also count for fulfillment of EO under EPCG Scheme.
- (e) Export shall be physical export. However, supplies as specified in paragraph 7.02 (a), (b), (e), (f) & (h) of FTP shall also be counted towards fulfillment of export obligation, along with usual benefits available under paragraph 7.03 of FTP.
- (f) EO can also be fulfilled by the supply of ITA-I items to DTA, provided realization is in free foreign exchange.
- (g) Royalty payments received by the Authorisation holder in freely convertible currency and foreign exchange received for R&D services shall also be counted for discharge under EPCG.
- (h) Payment received in rupee terms for such Services as notified in Appendix 5D shall also be counted towards discharge of export obligation under the EPCG scheme.

5.05 Deleted

5.06 LUT/Bond/BG in case of Agro units

LUT/Bond or 15% BG, as applicable, may be furnished for EPCG authorisation granted to units in Agri-Export Zones provided EPCG authorisation is taken for export of primary agricultural product(s) notified or their value added variants.

5.07 Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to Domestic Supplier

A person holding an EPCG authorisation may source capital goods from a domestic manufacturer. Such domestic manufacturer shall be eligible for deemed export benefits under paragraph 7.03 of FTP and as may be provided under GST Rules under the category of deemed exports. Such domestic sourcing shall also be permitted from EOUs and these supplies shall be counted for purpose of fulfilment of positive NFE by said EOU as provided in Para 6.09 (a) of FTP.

5.08 Calculation of Export Obligation

In case of direct imports, EO shall be reckoned with reference to actual duty saved amount. In case of domestic sourcing, EO shall be reckoned with reference to notional Customs duties saved on FOR value.

5.09 Incentive for early EO fulfilment

With a view to accelerating exports, in cases where Authorisation holder has fulfilled 75% or more of specific export obligation and 100% of Average Export Obligation till date, if any, in half or less than half the original export obligation period specified, remaining export obligation shall be condoned and the Authorisation redeemed by RA concerned. However no benefit under Para 5.21 of HBP shall be permitted where incentive for early EO fulfilment has been availed.

5.10 Reduced EO for Green Technology Products

For exporters of Green Technology Products, Specific EO shall be 75% of EO as stipulated in Para 5.01. There shall be no change in average EO imposed, if any, as stipulated in Para 5.04. The list of Green Technology Products is given in Para 5.29 of HBP.

5.11 Reduced EO for North East Region and Jammu & Kashmir

For units located in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu & Kashmir, specific EO shall be 25% of the EO, as stipulated in Para 5.01. There shall be no change in average EO imposed, if any, as stipulated in Para 5.04.

5.12 Post Export EPCG Duty Credit Scrip(s)

- (a) Post Export EPCG Duty Credit Scrip(s) shall be available to exporters who intend to import capital goods on full payment of applicable duties, taxes and cess in cash and choose to opt for this scheme.
- (b) Basic Customs duty paid on Capital Goods shall be remitted in the form of freely transferable duty credit scrip(s), similar to those issued under Chapter 3 of FTP.
- (c) Specific EO shall be 85% of the applicable specific EO under the EPCG Scheme. However, average EO shall remain unchanged.
- (d) Duty remission shall be in proportion to the EO fulfilled.

- (e) All provisions for utilization of scrips issued under Chapter 3 of FTP shall also be applicable to Post Export EPCG Duty Credit Scrip (s).
- (f) All provisions of the existing EPCG Scheme shall apply insofar as they are not inconsistent with this scheme.

CHAPTER 6

EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs)

6.00 Introduction and Objective

- (a) Units undertaking to export their entire production of goods and services(except permissible sales in DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronics Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park(STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) Scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, re-engineering, rendering of services, development of software, agriculture including agro-processing, aquaculture, animal husbandry, bio-technology, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture. Trading units are not covered under these schemes.
- (b) Objectives of these schemes are to promote exports, enhance foreign exchange earnings, attract investment for export production and employment generation.

6.01 Export and Import of Goods

- (a) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). However export of gold jewellery, including partly processed jewellery, whether plain or studded, and articles, containing gold of 8 carats and above upto a maximum limit of 22 carats only shall be permitted.
- (b) Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfilment of the conditions indicated in ITC (HS). In respect of an EOU, permission to export a prohibited item may be considered, by BOA, on a case to case basis, provided such raw materials are imported and there is no procurement of such raw material from DTA.
- (c) Procurement and supply of export promotion material like brochure / literature, pamphlets, hoardings, catalogues, posters etc up to a maximum value limit of 1.5% of FOB value of previous years exports shall also be allowed.
- (d) (i) An EOU / EHTP/ STP/ BTP unit may import and / or procure, from DTA or bonded warehouses in DTA / international exhibition held in India, all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS) subject to conditions given at para (ii) & (iii) below. Any permission required for import under any other law shall be applicable. Units shall also be permitted to import goods including capital goods required for approved activity, free of cost or on loan / lease from clients. Import of capital goods will be on a self-certification basis. Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for export production.
- (ii) The imports and/ or procurement from bonded warehouse in DTA or from international exhibition held in India shall be without payment of duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and additional duty, if any, leviable thereon under Section 3(1), 3(3) and 3(5) of the said Customs Tariff Act. Such imports and/ or procurements shall be made without payment of integrated tax and compensation cess leviable thereon under section 3(7) and 3(9) of the Customs Tariff Act, 1975 as per notification issued by the Department of Revenue and such exemptions would be available upto 31.03.2018 only.
- (iii) The procurement of goods covered under GST from DTA would be on payment of applicable GST and compensation cess. The refund of GST paid on such supply from DTA to EOU would be available to the supplier subject to such conditions and documentations as specified under GST rules and notifications issued there under. EOUs can also procure excisable goods falling under the Fourth Schedule of Central Excise Act, 1944 from DTA without payment of applicable duty of excise.
- (e) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units. However, in respect of Chrome Ore/Chrome concentrate, State Trading Regime as stipulated in export policy of these items, will be applicable to EOUs.
- (f) EOU/EHTP/STP/BTP units may import/procure from DTA, with or without payment of duties/taxes as provided at Para 6.01 (d)(ii) and 6.01(d)(iii) above, certain specified goods for creating a central facility. Software EOU/ DTA units may use such facility for export of software.

- (g) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use outside the premises of the unit.
- (h) Gems and jewellery EOUs may source gold / silver / platinum through nominated agencies on loan / outright purchase basis. Units obtaining gold / silver / platinum from nominated agencies, either on loan basis or outright purchase basis shall export gold / silver / platinum within 90 days from date of release.
- (i) EOU / EHTP / STP / BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/ Escrow Rupee Account of buyer subject to RBI clearance, if any.
- (j) Procurement and export of spares / components, upto 5% of FOB value of exports, may be allowed to same consignee / buyer of the export article, subject to the condition that it shall not count for NFE and direct tax benefits.
- (k) BOA may allow, on a case to case basis, requests of EOU / EHTP / STP/ BTP units in sectors other than Gems & Jewellery, for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with manufactured article. Such goods may be allowed to be imported / procured from DTA by EOU with or without payment of duty and/or taxes as provided at Para 6.01 (d) (ii) and (iii) above, as the case may be to the extent of 5% FOB value of such manufactured articles exported by the unit in preceding financial year. Details of procured / imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents. In such cases, value of procured / imported goods will not be taken into account for calculation of NFE and DTA sale entitlement. Such procured / imported goods shall not be allowed to be sold in DTA. BOA may also specify any other conditions.

6.02 Second hand Capital goods

Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported with or without payment of duty/ taxes as provided under Para 6.01(d)(ii) above.

6.03 Leasing of Capital Goods

- (a) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may, on the basis of a firm contract between parties, source capital goods from a domestic/ foreign leasing company with or without payment of duties/taxes as provided at Para 6.01 (d) (ii) and (iii) above, as the case may be in such a case, EOU/EHTP /STP / BTP unit and domestic/ foreign leasing company shall jointly file documents to enable import/ procurement of capital goods.
- (b) An EOU/EHTP/BTP/STP unit may sell capital goods and lease back the same from a Non Banking Financial Company (NBFC), subject to the following conditions:
 - (i) The unit should obtain permission from the jurisdictional Deputy /Assistant Commissioner of Customs for entering into transaction of 'Sale and Lease Back of Assets', and submit full details of the goods to be sold and leased back and the details of NBFC;
 - (ii) The goods sold and leased back shall not be removed from the unit's premises;
 - (iii) The unit should be NFE positive at the time when it enters into sale and lease back transaction with NBFC;
 - (iv) A joint undertaking by the unit and NBFC should be given to pay duty on goods in case of violation or contravention of any provision of the notification under which these goods were imported or procured, read with Customs Act, 1962 or Central Excise Act, 1944, and that the lien on the goods shall remain with the Customs Department, which will have first charge over the said goods for recovery of sum due from the unit to Government under provision of Section 142(b) of the Customs Act, 1962 read with the Customs (Attachment of Property of Defaulters for Recovery of Govt. Dues) Rules, 1995.

6.04 Net Foreign Exchange Earnings

EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. In addition sector specific provision of Appendix 6 B of Appendices & ANFs, where a higher value addition and other conditions are given, shall be required to be followed. NFE Earnings shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from commencement of production. Whenever a unit is unable to achieve NFE due to prohibition / restriction imposed on export of any product mentioned in LoP, the five year block period for calculation of NFE earnings may be suitably extended by BoA. Further, wherever a unit is unable to achieve NFE due to adverse market condition or any grounds of genuine hardship having adverse impact on functioning of the unit, the five year block period for calculation of NFE earnings may be extended by BOA for a period of upto one year, on a case to case basis. The method of calculation of NFE in detail is given in Para 6.10 of Handbook of Procedures 2015-20

6.05 Applications & Approvals/Letter of Permission / Letter of Intent and Legal Undertaking

- (a) (i) Application for setting up an EOU shall be considered by Unit Approval Committee (UAC)/ Board of Approval (BoA) as the case may be, as detailed in the Hand Book of Procedure. A detail of administration of EOUs and power of DC is given in HBP.
- (ii) In case of units under EHTP / STP schemes, necessary approval / permission under relevant paras of this Chapter shall be granted by officer designated by Ministry of Communication and Information Technology, Department of Electronics & Information Technology, instead of DC, and by Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BOA.
- (iii) Bio-Technology Parks (BTP) would be notified by DGFT on recommendations of Department of Bio-technology. In case of units in BTP, necessary approval / permission under relevant provisions of this chapter will be granted by designated officer of Department of Bio-technology.
- (iv) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by DC / designated officer to EOU / EHTP / STP / BTP unit. The validity of LoP/LoI shall be given in the Hand Book of Procedures.
- (b) LoP / LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority, subject to compliance of provision in Para 6.01 above, would be construed as an Authorisation for all purposes.
- (c) Unit shall execute an LUT with DC concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of LoP / LoI / IL / LUT shall render the unit liable to penal action under provisions of the FT (D&R) Act, as amended, and Rules and Orders made there under, without prejudice to action under any other law / rules and cancellation or revocation of LoP / LoI / IL.

6.06 Investment Criteria

Only projects having a minimum investment of Rs.1 Crore in plant & machinery shall be considered for establishment as EOUs. However, this shall not apply to existing units, units in EHTP / STP/ BTP, and EOUs in Handicrafts /Agriculture/ Floriculture/Aquaculture/Animal Husbandry /Information Technology, Services, Brass Hardware and Handmade jewellery sectors. BOA may allow establishment of EOUs with a lower investment criteria.

6.07 Applications & Approvals

- (a) Deleted
- (b) Deleted
- (c) Deleted
- (d) Deleted

6.08 DTA Sale of Finished Products / Rejects / Waste/ Scrap / Remnants and By-products

Entire production of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be exported. However, the following are allowed as exceptions subject to the conditions specified.

- (a) (i) Units, other than gems and jewellery units may sell finished goods manufactured by them as specified in LoP (including by-products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods) which are freely importable under FTP in DTA, subject to fulfillment of positive NFE, on payment of excise duty, if applicable, and/ or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Custom leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption, if any on the inputs utilized for the purpose of manufacturing of such finished goods (including by-products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods). No DTA sale shall be permissible in respect of, pepper & pepper products, marble and such other items as may be notified from time to time.
- (ii) Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in activities of packaging / labeling / segregation / refrigeration / compacting / micronisation / pulverization / granulation / conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa.
- (iii)(a) Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from Foreign Currency Account of SEZ unit.
- (b) Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs).

- (iv) An amount equal to Anti Dumping duty under section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 leviable at the time of import, shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into DTA from the unit.
- (v) The DTA sale by EOU/EHTP/STP/BTP units shall be subject to payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Custom leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption, if any on the inputs utilized for the purpose of manufacturing of such finished goods (including by-products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods). This reversal of Customs Duty would be as per prevailing SION norms or norms fixed by Norms Committee (where no SION norms are fixed).
- (vi) Such DTA sale shall also be subject to refund of any benefits under Chapter 7 of FTP availed by the EOU/supplier as per FTP, on the goods used for manufacture of the goods cleared into the DTA.
- (b) For services, including software units, sale in DTA in any mode, including on line data communication, shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA, subject to fulfillment of positive NFE. The unit shall pay applicable GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption, on inputs used in such jewellery.
- (d) Unless specifically prohibited in LoP, rejects may be sold in DTA on payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on inputs on prior intimation to Customs authorities. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap / waste / remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in DTA, as per SION notified under Duty Exemption Scheme, on payment of applicable duties and/ or taxes and compensation cess. Such sales of scrap / waste / remnants shall not be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by norms, DC may fix ad- hoc norms for a period of six months and within this period, norms should be fixed by Norms Committee. Ad-hoc norms will continue till such time norms are fixed by Norms Committee. Scrap / waste / remnants may also be exported.
- (f) There shall be no duties / taxes on scrap / waste / remnants, in case same are destroyed with permission of Customs authorities. The expression “no duties/ taxes” shall not include applicable taxes and cess under the GST laws.
- (g) By-products included in LoP may also be sold in DTA subject to achievement of positive NFE, on payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess along with reversal of duties of Custom leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, if availed on inputs.
- (h) Deleted
- (i) In case of units manufacturing electronics hardware and software, NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.
- (j) Deleted
- (k) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for first year, except pharmaceutical units where this will be based on its estimated exports for first two years.
- (l) Deleted
- (m) Procurement of spares / components, up to 2% of the value of manufactured articles, cleared into DTA, during the preceding year, may be allowed for supply to the same consignee / buyer for the purpose of after-sale-service. The same can be cleared in DTA on payment of applicable GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption, if any

6.09 Other Supplies

Following supplies effected from EOU / EHTP / STP / BTP units will be counted for fulfillment of positive NFE. Such supplies shall not include “marble”, except if such supply of marble is an inter unit supply as provided at Sub - Para(c) below:

- (a) Supplies effected in DTA to holders of Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA under duty exemption / remission scheme / EPCG scheme. However, printing sector EOU's (or any other sector that may be notified in HBP), can't supply goods, where basic customs duty and CVD is nil or exempted otherwise, to holders of Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement.
- (b) Supplies effected in DTA against foreign exchange remittance received from overseas.
- (c) Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units, provided that such goods are permissible for procurement in terms of Para 6.01 of FTP.
- (d) Supplies made to bonded warehouses set up under FTP and / or under section 65 of Customs Act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange.
- (e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by MoF, as may be provided in HBP.
- (f) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-1) items and notified zero duty telecom / electronics items.
- (g) Supplies of items like tags, labels, printed bags, stickers, belts, buttons or hangers to DTA unit for export.
- (h) Supply of LPG produced in an EOU refinery to Public Sector domestic oil companies for being supplied to household domestic consumers at subsidized prices under the Public Distribution System (PDS) Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002, as notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide notification No. E-20029/18/2001-PP dated 28.01.2003 (hereinafter referred to as PDS Scheme) subject to the following conditions:-
 - (i) Only supply of such quantity of LPG would be eligible for which Ministry of Petroleum and Natural Gas declines permission for export and requires the LPG to be cleared in DTA; and
 - (ii) The Ministry of Finance by a notification has permitted duty free imports of LPG for supply under the aforesaid PDS Scheme.

6.10 Export through others

An EOU/ EHTP/ STP/BTP unit may export goods manufactured/ software developed by it through another exporter or any other EOU/EHTP/STP/SEZ unit subject to conditions mentioned in Para 6.19 of HBP.

6.11 Entitlement for Supplies from the DTA

- (a) Supplies from DTA to EOU/EHTP/STP/ BTP units for use in their manufacture for exports will be eligible for "benefits under Chapter 7 of FTP". DTA supplier shall be eligible for relevant entitlements under chapter 7 of FTP, besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. The refund of GST paid on such supply from DTA to EOU would be available to the supplier subject to such conditions and documentations as specified under GST rules and notifications issued there under.
- (b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of Replenishment Authorisations at rates and for items mentioned in HBP.
- (c) In addition, EOU / EHTP / STP / BTP units shall be entitled to following:-
 - (i) Reimbursement of Central Sales Tax (CST) on goods manufactured in India. Simple interest @ 6% per annum will be payable on delay in refund of CST, if the case is not settled within 30 days of receipt of complete application (as in Para 9.10 (b) of HBP).
 - (ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on goods, falling in Fourth Schedule of Central Excise Act, procured from DTA on such goods manufactured in India.
 - (iii) Deleted
 - (iv) Deleted

6.12 Other Entitlements

Other entitlements of EOU/EHTP/STP/BTP units are as under:

- (a) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for SSI sector.
- (b) Export proceeds will be realized within nine months.
- (c) Units will be allowed to retain 100% of its export earnings in the EEFC account.
- (d) Unit will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where:

- (i) The unit has turnover of Rs. 5 crore or above;
- (ii) The unit is in existence for at least three years; and
- (iii) The unit:
 - (1) has achieved positive NFE / export obligation wherever applicable;
 - (2) has not been issued a show cause notice or a confirmed demand, during the preceding 3 years, on grounds other than procedural violations, under the penal provision of the Customs Act, the Central Excise Act, the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, the Foreign Exchange Management Act, the Finance Act, 1994 covering Service Tax or any allied Acts or the rules made thereunder, on account of fraud / collusion / wilful mis-statement / suppression of facts or contravention of any of the provisions thereof;
- (e) 100% FDI investment permitted through automatic route similar to SEZ units.
- (f) Deleted
- (g) The Units Approval Committee may consider on a case-to-case basis request for sharing of infrastructural facilities among EOUs and it shall forward its recommendation to the Board of Approval for its consideration. While accepting such proposals, the NFE obligations of the Units shall not be altered. Such facilities will be available to Units in EHTP / STP after getting approval from IMSC. However, sharing of facilities between EOUs and SEZ Units shall not be permitted.

6.13 Inter Unit Transfer

- (a) Transfer of manufactured goods from one EOU/ EHTP/STP/BTP unit to another EOU / EHTP/ STP/ BTP unit is allowed on payment of applicable GST and compensation cess with prior intimation to concerned Development Commissioners of the transferor and transferee units as well as concerned Customs authorities, as per following procedure for movement of goods:
 - i. The supplier EOU shall endorse on usual commercial documents, such as, tax invoice and delivery challan, the amount of duties of Custom leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on inputs used in the manufacture of such finished goods (including by-products, rejects, waste and scraps arising in the course of production, manufacture, processing or packaging of such goods) supplied to another EOU. The recipient EOU shall pay such endorsed Customs duty besides his own liability of reversal of Customs duty as provided in Para 6.08 above, before clearance of such finished goods in DTA and as provided under DoR notifications/circulars/ guidelines in this regard.
 - ii. Upon receipt of goods, the recipient EOU shall submit endorsed copies of tax invoice to their jurisdictional Customs authority as well as to the jurisdictional Customs authorities of the supplier EOU.
- (b) Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units, with prior intimation to concerned DC and Customs authorities on payment of applicable GST and compensation cess. Such transferred goods may also be returned by the second unit to the original unit in case of rejection or for any reason on payment of applicable GST and compensation cess.
- (c) Goods supplied by one unit of EOU/EHTP/STP/ BTP to another unit shall be on payment of applicable GST and compensation cess as per following procedure for movement of goods:
 - (i) The supplier EOU shall endorse on usual commercial documents, such as, tax invoice and delivery challan, the amount of duties of Customs leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on such goods supplied to another EOU. The recipient EOU shall pay such endorsed Customs duty and applicable GST and compensation cess before clearance of such goods or finished goods manufactured or produced from such goods in DTA.
 - (ii) Upon receipt of goods, the recipient EOU shall submit endorsed copies of tax invoice to their jurisdictional Customs authority as well as to the jurisdictional Customs authorities of the supplier EOU.
- (d) In respect of a group of EOUs / EHTPs / STPs / BTP Units which source inputs centrally in order to obtain bulk discount and / or reduce cost of transportation and other logistics cost and / or to maintain effective supply chain, inter unit transfer of goods and services may be permitted on a case-to-case basis by the Unit Approval Committee. In case inputs so sourced are imported and then transferred to another unit, then value of the goods so transferred shall be taken as inflow for the unit transferring these goods and as outflow for the unit receiving these goods, for the purpose of calculation of NFE.

6.14 Sub-Contracting

- (a) (i) EOU/EHTP/STP /BTP units, including gems and jewellery units, may on the basis of annual permission from Customs authorities, sub - contract production processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in DTA.
- (ii) These units may sub – contract upto 50% of overall production of previous year in value terms in DTA with permission of Customs authorities.
- (b) (i) EOU may, with annual permission from Customs authorities, under take job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in name of DTA/ EOU. For such exports, DTA units will be entitled for refund of duty paid on inputs by way of brand rate of duty drawback. However, such brand rate of drawback shall be as per Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017 and shall be limited to Customs duties and Central Excise Duties (in respect of eligible items covered under Schedule IV of Central Excise Act, 1944).
- (ii) Import of goods for execution of export order placed on EOU by foreign supplier on job work basis, would be allowed with or without payment of duties and/or taxes as provided under Para 6.01(d)(ii) above subject to condition that no DTA clearance shall be allowed.
- (iii) Sub - contracting of both production and production processes may also be under taken without any limit through other EOU/EHTP/ STP/ BTP/ SEZ units, on the basis of records maintained in unit.
- (iv) EOU/EHTP/STP/BTP units may sub - contract part of production process abroad and send intermediate products abroad as mentioned in LoP. No permission would be required when goods are sought to be exported from sub - contractor premises abroad. When goods are sought to be brought back, prior intimation to concerned DC and Customs authorities shall be given
- (c) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from job worker's premises on payment of applicable duty and/or taxes, as provided under Para 6.08 above on transaction value or destroyed in presence of Customs authority or returned to unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi-precious stones.
- (d) Sub - contracting/ exchange by gem sand jewellery EOUs through other EOUs or SEZ units or units in DTA, shall be as per procedure indicated in HBP.

6.15 Sale of Unutilized Material

- (a) In case an EOU / EHTP/ STP/BTP unit is unable to utilize goods and services, imported or procured from DTA, it may be:
 - (i) Transferred to another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit; or
 - (ii) Disposed of in DTA with intimation to Customs authorities on payment of applicable duties and/ or taxes and compensation cess. In addition, exemption of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed, if any on the goods , at the time of import will also be payable and submission of import Authorisation; or
 - (iii) Exported.

Such transfer from EOU/EHTP/ STP/ BTP unit to another such unit would be treated as import for receiving unit.

- (b) Capital goods and spares that have become obsolete/ surplus, may be exported or transferred to SEZ unit, transferred to another EOU/EHTP/STP/BTP/on payment of applicable GST and compensation cessor disposed of in DTA on payment of applicable GST and compensation cess and duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. Benefit of depreciation will be available in case of disposal in DTA only when the unit has achieved positive NFE taking into consideration the depreciation allowed. No duty shall be payable other than the applicable taxes under GST laws incase capital goods, raw material consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap/ waste/remnants /rejects are destroyed within unit after intimation to Customs authorities or destroyed outside unit with permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi-precious stones.
- (c) In case of textile sector, disposal of left over material/ fabrics upto 2% of CIF value or quantity of import, whichever is lower, on payment of duty on transaction value, may be allowed, subject to certification of Central Excise/Customs officers that these are left over items.

- (d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

6.16 Reconditioning/Repair and Re - engineering

- (a) EOUs shall be set up with approval of UAC to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, upgradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. Provisions of paragraphs 6.08, 6.09, 6.10, 6.13, 6.14 of FTP and Para 6.29(a), (b), (c) and (d) of HBP shall not, however, apply to such activities.
- (b) EHTP/STP/BTP units shall be set up with approval of IMSC to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, upgradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. Provisions of paragraphs 6.08, 6.09, 6.10, 6.13, 6.14 of FTP and Para 6.29(a), (b), (c) and (d) of HBP shall not, however, apply to such activities.

6.17 Replacement / Repair of Imported / Indigenous Goods

- (a) General provisions of FTP relating to export /import of replacement/repair of goods would also apply equally to EOU/EHTP/STP/BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by DC.
- (b) Goods sold in DTA and not accepted for any reasons, maybe brought back for repair/replacement, under intimation to concerned jurisdictional customs authorities.
- (c) Goods or parts thereof, on being imported / indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently, may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, goods may be brought back from foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. The unit can take free of cost replacement (duty paid) from the authorized agents in India of foreign suppliers, provided the defective part is re – exported or destroyed. However, destruction shall not apply to precious and semi-precious stones and precious metals.

6.18 Exit from EOU Scheme

- (a) With approval of DC, an EOU may opt out of scheme. Such exit shall be subject to payment of applicable Excise and Customs duties and on payment of applicable IGST/ CGST/ SGST/ UTGST and compensation cess, if any, and industrial policy in force.
- (b) If unit has not achieved obligations, it shall also be liable to penalty at the time of exit.
- (c) In the event of a gems and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gems and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by DoC, at price to be determined by that agency.
- (d) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by DC to exit from the scheme at any time on payment of applicable duties and taxes and compensation cess on capital goods under the prevailing EPCG Scheme for DTA Units. This will be subject to fulfillment of positive NFE criteria under EOU scheme, eligibility criteria under EPCG scheme and standard conditions indicated in HBP.
- (e) Unit proposing to exit out of EOU scheme shall intimate DC and Customs authorities in writing. Unit shall assess duty liability arising out of exit and submit details of such assessment to Customs authorities. Customs authorities shall confirm duty liabilities on priority basis, subject to the condition that the unit has achieved positive NFE, taking into consideration the depreciation allowed. After payment of duty and clearance of all dues, unit shall obtain “No Dues Certificate” from Customs authorities. On the basis of “No Dues Certificate” so issued by the Customs authorities, unit shall apply to DC for final exit. In case there is no proceeding pending under FT (D&R) Act, as amended, DC shall issue final exit order within a period of 7 working days. Between “No Dues Certificate” issued by Customs authorities and final exit order by DC, unit shall not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or inputs. However, unit can claim Advance Authorisation / DFIA / Duty Drawback. Since the duty calculations and dues are disputed and take a long time, a BG / Bond / Installment processes backed by BG shall be provided for expediting the exit process.
- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machines procured from abroad after payment of applicable import duty, or from domestic market after payment of excise duty/GST, and unit is subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after exit would be without payment of duty. Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under EPCG Scheme and after completely fulfilling export obligation gets converted into EOU, unit would not be charged customs duty on capital goods at the time of removal of such capital goods in DTA when exit.
- (g) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by DC to exit under Advance Authorisation as one time option. This will be subject to fulfillment of positive NFE criteria.

- (h) A simplified procedure may be provided to fast track the De-bonding/ Exit of the STP / EHTP Unit which has not availed any duty benefit on procurement of raw material, capital goods etc.

6.19 Conversion

- (a) Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit.
- (b) Existing EHTP / STP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will avail exemptions in duties and taxes as applicable.
- (c) Applications for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit from existing DTA units, having an investment of Rs. 50 crores and above in plant and machinery or exporting Rs. 50 crores and above annually, shall be placed before BOA for a decision.

6.20 Monitoring of NFE

Performance of EOU/EHTP/STP/ BTP units shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines in HBP.

6.21 Export through Exhibitions / Export Promotion Tours/ Showrooms Abroad /Duty Free Shops

EOU / EHTP/STP/BTP are permitted to:

- (i) Export goods for holding/participating in Exhibitions abroad with permission of DC.
- (ii) Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.
- (iii) Export goods for display / sale in permitted shops set up abroad.
- (iv) Display / sell in permitted shops set up abroad, or in showrooms of their distributors / agents.
- (v) Set up showrooms / retail outlets at International Airports.

6.22 Personal Carriage of Import / Export Parcels including through Foreign Bound Passengers

Import/ export through personal carriage of gems and jewellery items may be undertaken as per Customs procedure. However, export proceeds shall be realized through normal banking channel. Import/ export through personal carriage by units, other than gems and jewellery units, shall be allowed provided goods are not in commercial quantity. An authorized person of Gems & Jewellery EOU may also import gold in primary form, upto 10Kgs in a financial year through personal carriage, as per guidelines prescribed by RBI and DoR.

6.23 Export / Import by Post / Courier

Goods including free samples, may be exported/imported by air freight or through foreign post office or through courier, as per Customs procedure.

6.24 Administration of EOUs / Powers of DC

Details of administration of EOUs and power of DC is given in HBP.

6.25 Revival of Sick Units

Subject to a unit being declared sick by appropriate authority, proposals for revival of the unit or its takeover may be considered by BOA.

6.26 Approval of EHTP/ STP

Deleted

6.27 Approval of BTP

Deleted

6.28 Warehousing Facilities

Deleted

CHAPTER 7

DEEMED EXPORTS

7.00 Objective

To provide a level-playing field to domestic manufacturers in certain specified cases, as may be decided by the Government from time to time.

7.01 Deemed Exports

- (i) “Deemed Exports” for the purpose of this FTP refer to those transactions in which goods supplied do not leave country, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange. Supply of goods as specified in Paragraph 7.02 below shall be regarded as “Deemed Exports” provided goods are manufactured in India.
- (ii) “Deemed Exports” for the purpose of GST would include only the supplies notified under Section 147 of the CGST/SGST Act, on the recommendations of the GST Council. The benefits of GST and conditions applicable for such benefits would be as specified by the GST Council and as per relevant rules and notification.

7.02 Categories of Supply

Supply of goods under following categories (a) to (d) by a manufacturer and under categories (e) to (h) by main / sub-contractors shall be regarded as “Deemed Exports”:

A. Supply by manufacturer:

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA;
- (b) Supply of goods to EOU / STP / EHTP / BTP;
- (c) Supply of capital goods against EPCG Authorisation;
- (d) Deleted

B. Supply by main / sub-contractor (s):

- (e)
 - (i) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral Agencies / Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty.
 - (ii) Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral Agencies/Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF, for which bids have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad.
 - (iii) Supplies covered in this paragraph shall be under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those Agencies / Funds.
 - (iv) A list of agencies, covered under this paragraph, for deemed export benefits, is given in Appendix 7A.
- (f)
 - (i) Supply of goods to any project or for any purpose in respect of which the Ministry of Finance, by erstwhile Notification No. 12/2012 –Customs dated 17.3.2012, as amended from time to time, had permitted import of such goods at zero customs duty (with exemption of both BCD and CVD) subject to conditions specified therein and which are continued under the Customs Notification No. 50/2017-Customs dated 30.6.2017 with exemption of zero basic customs duty and subject to conditions mentioned in the said new notification. Benefits of deemed exports shall be available only if the supply is made under procedure of ICB.
 - (ii) Supply of goods required for setting up of any mega power project, as specified in the list 31 at Sl. No. 598 of Department of Revenue Notification No. 50/2017-Customs dated 30.6.2017, as amended from time to time and subject to conditions mentioned therein, shall be eligible for deemed export benefits provided such mega power project conforms to the threshold generation capacity specified in the above said Notification.
 - (iii) For mega power projects, ICB condition would not be mandatory if the requisite quantum of power has been tied up through tariff based competitive bidding or if the project has been awarded through tariff based competitive bidding.
- (g) Supply of goods to United Nations or International organization for their official use or supplied to the projects financed by the said United Nations or an International organization approved by Government of India in pursuance of section 3 of United Nations (Privileges and Immunities Act), 1947. List of such organization and conditions applicable to such supplies is given in the Customs notification no. 84/97-Customs dated 11.11.1997, as amended from time to time. A list of Agencies, covered under this paragraph, is given in Appendix-7B.
- (h) Supply of goods to nuclear power projects provided:
 - (i) Such goods are required for setting up of any Nuclear Power Project as specified in the list 32 at Sl. No. 602, Customs notification no. 50/2017-Customs dated 30.6.2017, as amended from time to time and subject to conditions mentioned therein.

- (ii) The project should have a capacity of 440 MW or more.
- (iii) A certificate to the effect is required to be issued by an officer not below the rank of Joint Secretary to Government of India, in Department of Atomic Energy.
- (iv) Tender is invited through National competitive bidding (NCB) or through ICB.

7.03 Benefits for Deemed Exports

Deemed exports shall be eligible for any / all of following benefits in respect of manufacture and supply of goods, qualifying as deemed exports, subject to terms and conditions as given in HBP and ANF-7A:

- (a) Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA.
- (b) Deemed Export Drawback for BCD.
- (c) Refund of terminal excise duty for excisable goods mentioned in Schedule 4 of Central Excise Act 1944 provided the supply is eligible under that category of deemed exports and there is no exemption.

7.04 Benefits to the Supplier /Recipient

Categories of supplies as per Para 7.02	Benefits on supplies, as given in Para 7.03 above, whichever is applicable.		
	Para 7.03 (a) Advance Authorisation	Para 7.03 (b) Duty Drawback	Para 7.03 (c) Terminal Excise Duty
(a)	Yes (for inter mediate supplies against an invalidation letter)	Yes (against ARO)	Yes
(b)	Yes	Yes	Yes
(c)	Yes	Yes	NA
(d)	deleted	deleted	deleted
(e)	Yes	Yes	NA
(f)	Yes	Yes	Yes, only for para 7.08(iii)(a)
(g)	Yes	Yes	NA
(h)	Yes	Yes	NA

7.05 Conditions for refund of terminal excise duty

- (i) Supply of goods will be eligible for refund of terminal excise duty as per Para 7.03 (c) of FTP, provided recipient of goods does not avail CENVAT credit/rebate on such goods.
- (ii) Deleted
 - (a) Deleted
 - (b) Deleted
 - (c) Deleted
 - (d) Deleted

7.06 Conditions for refund of deemed export drawback

Supplies will be eligible for deemed export drawback as per para 7.03 (b) of FTP, as under:

The refund of drawback in the form of Basic Customs duty of the inputs used in manufacture and supply under the said category shall be given on brand rate basis upon submission of documents evidencing actual payment of basic custom duties.

7.07 Common conditions for deemed export benefits

- (i) Supplies shall be made directly to entities listed in the Para 7.02. Third party supply shall not be eligible for benefits/exemption.
- (ii) In all cases, supplies shall be made directly to the designated Projects / Agencies/ Units/ Advance Authorisation/ EPCG Authorisation holder. Sub-contractors may, however, make supplies to main contractor instead of supplying directly to designated Projects/ Agencies. Payments in such cases shall be made to sub-contractor by main-contractor and not by project Authority.
- (iii) Supply of domestically manufactured goods by an Indian Sub-contractor to any Indian or foreign main contractor, directly at the designated project's/ Agency's site, shall also be eligible for deemed export benefit provided name of sub-contractor is indicated either originally or subsequently (but before the date of supply of such goods) in the main contract. In such cases payment shall be made directly to sub-contractor by the Project Authority.

7.08 Benefits on specified supplies

- (i) Deemed export benefits shall be available for supplies of 'Cement' under Para 7.02 (e) only.
- (ii) Deemed export benefit shall be available on supply of "Steel":
 - (a) As an inputs to Advance Authorisation/ Annual Advance Authorisation/DFIA holder/ an EOU.
 - (b) To multilateral/ bilateral funded Agencies as per sub-Para 7.02(e).
- (iii) Deemed export benefit shall be available on supply of "Fuel" (in respect of eligible fuel items covered under Schedule 4 of Central Excise Act 1944) provided supplies are made to:
 - a. Project listed for petroleum operations in the Customs Notification No. 50/2017-Customs dated 30.6.2017 under Sr. No. 404, as amended from time to time and subject to conditions mentioned therein and covered in Para 7.02 (f) of FTP.
 - b. EOUs;
 - c. Advance Authorisation holder / Annual Advance Authorisation holder.

7.09 Liability of Interest

Incomplete/deficient application is liable to be rejected. However, simple interest @ 6% per annum will be payable on delay in refund of duty drawback and terminal excise duty under the scheme, provided the claim is not settled within 30 days from the date of issue of final Approval Letter by RA.

7.10 Risk Management and Internal Audit mechanism

- (a) A Risk Management system shall be in operation, wherein every month, Computer system in DGFT headquarters, on random basis, will select 10% of cases, for each RA, where benefit(s) under this chapter has/have already been granted. Such cases shall be scrutinized by an internal Audit team, headed by a Joint DGFT, in the office of respective Zonal Addl. DGFT. The team will be responsible to audit claims of not only for its own office but also the claims of all RAs falling under the jurisdiction of the Zone.
- (b) The respective RA may also, either on the basis of report from Internal Audit/ External Audit Agency(ies) or suo-motu, reassess any case, where any erroneous/in-eligible payment has been made/claimed. RA will take necessary action for recovery of payment along with interest at the rate of 15% per annum on the recoverable amount.

7.11 Penal Action

In case, claim is filed by submitting mis-declaration/mis-representation of facts, then in addition to effecting recovery under Para 7.10(b) above, the applicant shall be liable for penal action under the provisions of F.T. (D&R) Act, Rules and orders made there under.

7.12 Transitional Para

Deemed exports benefits contained in FTP 2015-20 shall be available for supplies effected till 30.06.2017 in terms of FTP 2015-20 provisions as it stood till 30.06.2017. In respect of supply made after 30.6.2017, new provision shall apply.

CHAPTER 8

QUALITY COMPLAINTS AND TRADE DISPUTES

8.00 Objective

Exporters need to project a good image of the country abroad to promote exports. Maintaining an enduring relationship with foreign buyers is of utmost importance, and complaints or trade disputes, whenever they arise, need to be settled amicably as soon as possible. Importers too may have grievances as well.

In an endeavour to resolve such complaints or trade disputes and to create confidence in the business environment of the country, a mechanism is being laid down to address such complaints and disputes in an amicable way.

8.01 Quality Complaints/ Trade disputes

The following type of complaints may be considered:

- (a) Complaints received from foreign buyers in respect of poor quality of the products supplied by exporters from India;
- (b) Complaints of importers against foreign suppliers in respect of quality of the products supplied; and
- (c) Complaints of unethical commercial dealings categorized mainly as non-supply/ partial supply of goods after confirmation of order; supplying goods other than the ones as agreed upon; non-payment; non-adherence to delivery schedules, etc.

8.02 Obligation on the part of importer/ exporter

- (a) Rule 11 of the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, requires that on the importation into, or exportation out of, any customs ports of any goods, whether liable to duty or not, the owner of such goods shall in the Bill of Entry or the Shipping Bill or any other documents prescribed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), state the value, quality and description of such goods to the best of his knowledge and belief and in case of exportation of goods, certify that the quality and specification of the goods as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods are being exported and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or Shipping Bill or any other documents. Violation of this provision renders the exporter liable for penal action.
- (b) Certain export commodities have been notified for Compulsory Quality Control & Pre-shipment Inspection prior to their export. Penal action can be taken under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 as amended in 1984, against exporters who do not conform to these standards and/ or provisions of the Act as laid down for such products.

8.03 Provisions in FT (D&R) Act & FT (Regulation) Rules for necessary action against erring exporters/ importers

Action against erring exporters can be taken under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended and under Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, as follows:-

- (a) Section 8 of the Act empowers the Director General of Foreign Trade or any other person authorized by him to suspend or cancel the Importer Exporter Code Number for the reasons as given therein.
- (b) Section 9 (2) of the Act empowers the Director General of Foreign Trade or an officer authorised by him to refuse to grant or renew a license, certificate, scrip or any other instrument bestowing financial or fiscal benefit granted under the Act.
- (c) Section 9(4) empowers the Director General of Foreign Trade or the officer authorized by him to suspend or cancel any License, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefit granted under the Act.
- (d) Section 11(2) of the Act provides for imposition of fiscal penalty in cases where a person makes or abets or attempts to make any import or export in contravention of any provision of the Act, any Rules or Orders made there under or the Foreign Trade Policy.

8.04 Mechanism for handling of Complaints/ Disputes**(a) Committee on Quality complaints and Trade Disputes (CQCTD)**

To deal effectively with the increasing number of complaints and disputes, a 'Committee on Quality Complaints and Trade Disputes' (CQCTD) will be constituted in the 22 offices of the RA's of DGFT. Names of RAs, where CQCTD has been constituted and jurisdiction of CQCTD is given in Chapter 8 of the Handbook of Procedures.

(b) Composition of the CQCTD

The CQCTD would be constituted under the Chairpersonship of the Head of Office. The constitution of CQCTD is given in Chapter 8 of the Hand Book of Procedures.

(c) Functions of CQCTD

The Committee (CQCTD) will be responsible for enquiring and investigating into all Quality related complaints and other trade related complaints falling under the jurisdiction of the respective RAs. It will take prompt and effective steps to redress and resolve the grievances of the importers, exporters and overseas buyers, preferably within three months of receipt of the complaint. Wherever required, the Committee (CQCTD) may take the assistance of the Export Promotion Councils/FIEO/Commodity Boards or any other agency as considered appropriate for settlement of these disputes.

8.05 Proceedings under CQCTD

CQCTD proceedings are only reconciliatory in nature and the aggrieved party, whether the foreign buyer or the Indian importer, is free to pursue any legal recourse against the other erring party.

8.06 Procedures to deal with complaints and trade disputes

The procedure for making an application for such complaints or trade disputes and the procedure to deal with such quality complaints and disputes is given in the Handbook of Procedures.

8.07 Corrective Measures

The Committee at RA level can authorize the Export Inspection Agency or any technical authority to assess whether there has been any technical failure of not meeting the standards, manufacturing/ design defects, etc. for which complaints have been received.

8.08 Nodal Officer

Director General of Foreign Trade would appoint an officer, not below the rank of Joint Director General, in the Headquarters, to function as the 'Nodal Officer' for coordinating with various Regional Authorities of DGFT.

CHAPTER 9

DEFINITIONS

For purpose of FTP, unless context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings attached to them:-

- 9.01 "Accessory" or "Attachment" means apart, sub-assembly or assembly that contributes to efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.
- 9.02 "Act" means Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) [FT (D&R) Act] as amended from time to time.
- 9.03 "Actual User" is a person (either natural & legal) who is authorized to use imported goods in his/its own premise which has a definitive postal address.
- (a) "Actual User (Industrial)" is a person (either natural & legal) who utilizes imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit which has a definitive postal address.
- (b) "Actual User (Non-Industrial)" is a person (either natural & legal) who utilizes the imported goods for his own use in.
- (i) any commercial establishment, carrying on any business, trade or profession, which has a definitive postal address; or

- (ii) any laboratory, Scientific or Research and Development(R&D) institution, university or other educational institution or hospital which has a definitive postal address; or
- (iii) Any service industry which has a definitive postal address.
- 9.04 "AEZ" means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 2V of Appendices and Aayat Niryat Forms.
- 9.05 "Appeal" is an application filed under section 15 of the Act and includes such applications preferred by DGFT officials in government interest against decision by designated adjudicating/appellate authorities.
- 9.06 "Applicant" means person on whose behalf an application is made and shall, wherever context so requires, includes person signing the application.
- 9.07 "Authorisation" means permission as included in Section 2(g) of the Act to import or export as per provisions of FTP.
- 9.08 "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological up-gradation or expansion. It includes packaging machinery and equipment, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control.
- Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in services sector.
- 9.09 "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act the Rules and Orders made there under or under FTP.
- 9.10 "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to another component.
- 9.11 "Consumables" means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process, will be deemed to be consumables.
- 9.12 "Consumer Goods" means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durable and accessories thereof.
- 9.13 "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from /to India are balanced either by direct imports/exports from importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise.
- Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. Balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.
- 9.14 "Developer" means a person or body of persons, company, firm and such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintains or manages a part or whole of infrastructure and other facilities in SEZ as approved by Central Government and also includes a co-developer.
- 9.15 "Development Commissioner" means Development Commissioner of SEZ
- 9.16 "Domestic Tariff Area (DTA)" means area within India which is outside SEZs and EOU/ EHTP/STP/BTP.
- 9.17 Deleted
- 9.17A "e – commerce" for the purpose of Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) under Foreign Trade Policy (2015-20) (FTP) shall mean the export of goods hosted on a website accessible through the internet to a purchaser. While the dispatch of goods shall be made through courier or postal mode, as specified under the MEIS, the payment for goods purchased on e-commerce platform shall be done through international credit /debit cards and as per the Reserve Bank of India Circular (RBI/2015-16/185) [A.P.(DIR Series) Circular No. 16 dated September

- 24, 2015.] as amended from time to time.
- 9.18 "EOU" means Export Oriented Unit for which a letter of permit has been issued by Development Commissioner.
- 9.19 "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to duty of excise under Central Excise and Salt Act 1944(1 of 1944).
- 9.20 "Export" is as defined in FT (D&R) Act, 1992, as amended from time to time.
- 9.21 "Exporter" means a person who exports or intends to export and hold an IEC number, unless otherwise specifically exempted.
- 9.22 "Export Obligation" means obligation to export product or products covered by Authorisation or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by Regional or competent authority.
- 9.23 "Free" as appearing in context of import/export policy for items means goods which do not need any 'Authorisation' / License or permission for being imported into the country or exported out.
- 9.24 "FTP" means the Foreign Trade Policy which specifies policy for exports and imports under Section 5 of the Act.
- 9.25 "Import" is as defined in FT (D&R) Act, 1992 as amended from time to time.
- 9.26 "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an IEC number, unless otherwise specifically exempted.
- 9.27 ITC (HS) refers to Indian Trade Classification (Harmonized System) at 8 digits.
- 9.28 "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to job worker, so as to complete a part of process resulting in manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for aforesaid process.
- 9.29 "Licensing Year" means period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.
- 9.30 "Managed Hotel" means hotels managed by a three star or above hotel/ hotel chain under an operating management contract for a duration of at least three years between operating hotel/ hotel chain and hotel being managed. Management contract must necessarily cover the entire gamut of operations/management of managed hotel.
- 9.31 "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling, Re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering.
- Manufacture, for the purpose of FTP, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.
- 9.32 "Manufacturer Exporter" means a person who exports goods manufactured by him or intends to export such goods.
- 9.33 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or in tending to export goods.
- 9.34 "NC" means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade for approval of adhoc input –output norms in cases where SION does not exist and recommend SION to be notified in DGFT.
- 9.35 "Notification" means a notification published in Official Gazette.
- 9.36 "Order" means an Order made by Central Government under the Act.
- 9.37 "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself, and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. Part may be a component, spare or an accessory.
- 9.38 "Person" means both natural and legal and includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person including the DGFT officials.

- 9.39 "Policy" means Foreign Trade Policy (2015-2020) as amended from time to time.
- 9.40 "Prescribed" means prescribed under the Act or the Rules or Orders made there under or under FTP.
- 9.41 "Prohibited" indicates the import/export policy of an item, as appearing in ITC (HS) or elsewhere, whose import or export is not permitted.
- 9.42 "Public Notice" means a notice published under provisions of paragraph 2.55 of FTP
- 9.42A "Project Exports" refers to export of engineering goods on deferred payment terms and execution of turnkey projects and civil construction contracts abroad collectively.
Project Exports would encompass (i) Civil construction contracts; (ii) Turnkey Engineering contracts including supply of Capital Goods on deferred payment terms; (iii) Process and Engineering Consultancy Services; and (iv) Project Construction items (excluding Steel and Cement).
- 9.43 "Quota" means the quantity of goods of a specific kind that is permitted to be imported without restriction or imposition of additional Duties.
- 9.44 "Raw material" means input(s) needed for manufacturing of goods. These inputs may either be in a raw/natural/unrefined/unmanufactured or manufactured state.
- 9.45 "Regional Authority" means authority competent to grant an Authorisation under the Act/Order.
- 9.46 "Registration-Cum-Membership Certificate"(RCMC) means certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council/Commodity Board/Development Authority or other competent authority as prescribed in FTP or Handbook of Procedure.
- 9.47 "Restricted" is a term indicating the import or export policy of an item, which can be imported into the country or exported outside, only after obtaining an Authorisation from the offices of DGFT.
- 9.48 "Rules" means Rules made by Central Government under Section 19 of the FT (D&R) Act.
- 9.49 "SCOMET" is the nomenclature for dual use items of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET). Export of dual-use items and technologies under India's Foreign Trade Policy is regulated. It is either prohibited or is permitted under an Authorisation.
- 9.50 "Services" include all tradable services covered under General Agreement on Trade in Services (GATS) and earning free foreign exchange.
- 9.51 "Service Provider" means a person providing:
(i) Supply of a 'service' from India to any other country; (Mode 1- Cross border trade)
(ii) Supply of a 'service' from India to service consumer(s) of any other country in India; (Mode 2-Consumption abroad)
(iii) Supply of a 'service' from India through commercial presence in any other country. (Mode 3 – Commercial Presence.)
(iv) Supply of a 'service' from India through the presence of natural persons in any other country (Mode 4- Presence of natural persons.)
- 9.52 "Ships" mean all types of vessels used for seaborne trade or coastal trade, and shall include second hand vessels.
- 9.53 "SION" means Standard Input Output Norms notified by DGFT.
- 9.54 "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution that is ready to replace an identical or similar part or sub- assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.

- 9.55 "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy through Notification/Public Notice.
- 9.56 "Status holder" means an exporter recognized as One Star Trading House/ Two Star Trading House / Three Star Trading House/ Four Star Trading House/ Five Star Trading House by DGFT/Development Commissioner.
- 9.57 "Stores" means goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spares and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting.
- 9.58 (a) "Supporting Manufacturer" is one who manufactures goods/products or any part/accessories/components of a good/product for a merchant exporter or a manufacturer exporter under a specific Authorisation.
- (b) "Supporting Manufacturer" for the EPCG Scheme shall be one in whose premises/factory Capital Goods imported/ procured under EPCG Authorisation is installed.
- 9.59 State Trading Enterprises (STEs), for the purpose of this FTP, are those entities which are granted exclusive right/privileges export and /or import as per Para 2.20 (a) of FTP.
- 9.60 "Third-party exports" means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s).
- In such cases, export documents such as shipping bills shall indicate names of both manufacturer exporter/manufacturer and third party exporter(s). Bank Realisation Certificate (BRC), Self Declaration Form (SDF), export order and invoice should be in the name of third party exporter.
- 9.61 "Transaction Value" is as defined in Customs Valuation Rules of Department of Revenue.
- 9.62 "Wild Animal" means any wild animal as defined in Section 2 (36) of Wildlife (Protection) Act, 1972.

Appendix I (Para 2.17)

2.17 Prohibition on direct or indirect import and export from/to Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Prohibition on export:

(A) The direct or indirect supply, sale, transfer or export of the following items to Democratic People's Republic of Korea (DPRK) is prohibited:-

- (i) any battle tanks, armoured combat vehicles, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related materiel including spare parts;
- (ii) All arms and related materiel, including small arms and light weapons and their related materiel;
- (iii) all items, materials, equipment, goods and technology as set out in the UNSC United Nations Security Council and International Atomic Energy Agency (IAEA) documents, namely,

1. S/2006/853*;
2. S/2006/853/Corr.1;
3. Part B of S/2009/364;
4. Annex III of Resolution 2094 (2013);
5. S/2016/1069;
6. Annex A to INFCIRC/254/Rev.12/Part1 (IAEA document);
7. Annex to INFCIRC/254/Rev.9/Part2 (IAEA document);
8. S/2014/253;
9. S/2016/308;
10. Annex III of Resolution 2321 (2016); and

11. other items, materials, equipment, goods and technology, as determined by the Central Government, which could contribute to DPRK's nuclear related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction related programmes;

(iv) Luxury goods, including, but not limited to, the items specified in Annex IV of Resolution 2094 (2013), Annex IV of Resolution 2270 (2016) and Annex IV of Resolution 2321 (2016);

(v) Items as determined by the Central Government, except food or medicine that could directly contribute to the development of the Democratic People's Republic of Korea's operational capabilities of its armed forces. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 8 (a) and (b) of Resolution 2270 (2016);

Prohibition on import:

(B) The direct or indirect procurement or import from DPRK, of items, whether or not originating in DPRK, covered in sub-paragraphs (A)(i), (A)(ii), (A)(iii) and (A)(v) above is prohibited.

Sectoral prohibitions (export)

(C) The direct or indirect supply, sale, transfer or export of the following items to DPRK is prohibited:

(i) New helicopters and vessels, except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

(ii) Aviation fuel, including aviation gasoline, naphtha-type jet fuel, kerosene-type jet fuel, and kerosene-type rocket fuel. This measure is subject to the provisions of paragraph 31 of Resolution 2270 (2016) and paragraph 20 of Resolution of 2321 (2016);

(iii) Condensates and natural gas liquids;

(iv) Refined petroleum products. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 14 of Resolution 2375 (2017);

(v) Crude oil. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 15 of Resolution 2375 (2017);

Sectoral prohibitions (import)

(D) The direct or indirect procurement or import from DPRK, of the following items is prohibited:

(i) Coal, iron and iron ore. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 8 of Resolution 2371 (2017);

(ii) Gold, titanium ore, vanadium ore, and rare earth minerals;

(iii) Copper, nickel, silver and zinc;

(iv) Statues, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;

(v) Seafood (including fish, crustaceans, molluscs, and other aquatic invertebrates in all forms). This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 9 of Resolution 2371 (2017);

(vi) Lead and lead ore. This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 10 of Resolution 2371 (2017);

(vii) Textiles (including but not limited to fabrics and partially or fully completed apparel products). This measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraph 16 of Resolution 2375 (2017);

Explanation.-

- a) UNSC means the United Nations Security Council;
- b) IAEA means the International Atomic Energy Agency;
- c) Committee means the Committee of the UNSC set up in terms of paragraph 12 of Resolution 1718 (2006); and Resolution, as the case may be, means the UNSC Resolutions under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Democratic People's Republic of Korea, namely, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2231 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) and 2375 (2017).

GLOSSARY (ACRONYMS)

Acronym	Explanation
AA	Advance Authorisation
AANF	Appendices and Aayaat Niryat Form
ACU	Asian Clearing Union

AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayat Niryaat Form
ARE-1	Application for Removal of Excisable Goods for Export (By Air/Sea/Post/Land)
ARE-3	Application for Removal of Excisable Goods from a factory or a warehouse to another warehouse
ACP	Accredited Clients Programme
AEO	Authorised Economic Operator
AES	Approved Exporter's Scheme
APEDA	Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
ARO	Advance Release Order
ASEAN	Association of South- East Asian Nations
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
AU	Actual User
BCD	Basic Customs Duty
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BOA	Board of Approval
BOT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Biotechnology Park
BIS	Bureau of Indian Standards
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CED	Central Excise Duty
CENVAT	Central Value Added Tax
CETF	Common Effluent Treatment Facility
CFCs	Common Facility Centres
CG	Capital Goods
CIF	Cost, Insurance & Freight
CIN	Corporate Identification Number
CIS	Commonwealth of Independent States
CKD	Completely Knocked Down
CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CQCTD	Committee on Quality Complaints and Trade Disputes
CRES	Certificate of Registration as Exporter of Spices
CST	Central Sales Tax
CIN	Company Identification Number
CRES	Certification of Registration as Exporter of Spices

CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CSP	Common Service Provider
CECA	Comprehensive Economic Cooperation Agreement
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DBK	Drawback
DC	Development Commissioner
DDA	Diamond Dollar Accounts
DEA	Department of Economic Affairs
DEL	Denied Entity List
DES	Duty Exemption Schemes
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics.
DIN	Director Identification Number
DPIN	Designated Partner Identification Number
DGFT	Director General of Foreign Trade
DIPP	Department of Industrial Policy & Promotion
DoBT	Department of Bio-Technology
DoC	Department of Commerce
DeitY	Department of Electronics and Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Telecommunications
DRS	Duty Remission Schemes
DTA	Domestic Tariff Area
e-BRC	Electronic Bank Realisation Certificate
e-IEC	Electronic Importer-Exporter Code
ECA	Enforcement- cum-Adjudication
EDI	Electronic Data Interchange
ECGC	Export Credit Guarantee Corporation
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EGM	Export General Manifest
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council
EO	Export Obligation
EODC	Export Obligation Discharge Certificate
EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council

EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Process Outsourcing
EXIM	Export Import
FDI	Foreign Direct Investment
FE	Foreign Exchange
FEMA	Foreign Exchange Management Act
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FOB	Free On Board
FOR	Freight on Road and Rails
FT(D&R)Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)
FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
FT(R)	Rules Foreign Trade (Regulation) Rules
FTWZ	Free Trade and Warehousing Zone
FTA	Free Trade Agreement
G&J EPC	Gems & Jewellery Export Promotion Council
GOI	Government of India
GATS	General Agreement on Trade in Services
GR	Guarantee of Realisation
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Process
HBP	Handbook of Procedures
HHEC	Handicraft & Handlooms Exports Corporation
ICB	International Competitive Bidding
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
ISO	International Organisation for Standardisation
IAEA	International Atomic Energy Agency
INFCIRC	International Atomic Energy Agency Information Circular
IEM	Industrial Entrepreneurial Memorandum
IMSC	Inter-Ministerial Standing Committee
IL	Industrial Licensing
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) for Export & Import Items
KVIC	Khadi and Village Industries Commission
LC	Letter of Credit
LCS	Land Customs Station
LLPIN	Limited Liability Partnership Number
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LoC	Line of Credit

LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Undertaking
MAI	Market Access Initiative
MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MEIS	Merchandise Exports from India Scheme
MRA	Mutual Recognition Agreements
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance
MSME	Ministry of Micro Small and Medium Enterprises
MSMED	Micro Small and Medium Enterprises Development
MSTC	Metal Scrap Trade Corporation
NBFC	Non- Banking Financial Company
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NI	Non-Infringing
NCB	National Competitive Bidding
NOC	No Objection Certificate
PDS	Public Distribution System
PEC	Project and Equipment Corporation of India Ltd.
PIC	Policy Interpretation Committee
PRC	Policy Relaxation Committee
PAN	Permanent Account Number
PH	Personal Hearing
PTA	Preferential Trade Agreement
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
REP	Replenishment
RPA	Rupee Payment Area
S/B	Shipping Bill
SAD	Special Additional Duty
SCOMET	Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technology
SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SEIS	Service Exports from India Scheme
SIA	Secretariat for Industrial Assistance
SIIC	State Industrial Infrastructure Corporation

SION	Standard Input Output Norms
SKD	Semi- Knocked Down
SLEPC	State Level Export Promotion Committee
STC	State Trading Corporation
STCL	Spices Trading Corporation Limited
STE	State Trading Enterprise
STH	Star Trading House
STPI	Software Technology Park of India
STR	State Trading Regime
SUVs	Sports Utility Vehicles
TED	Terminal Excise Duty
TEE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TPO	Trade Promotion Organization
TRA	Telegraphic Release Advice
TRQ	Tariff Rate Quota
TUFS	Technology Up gradation Fund Scheme
UAC	Units Approval Committee
UN	United Nations
VA	Value Addition
WCO	World Customs Organisation
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices